

मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता: स्थिरता ही मूलमंत्र

भारत के बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों ने वित्त वर्ष 24 में शानदार प्रदर्शन किया है। बैंक ऋण में दोहरे अंकों और व्यापक आधार वाली वृद्धि, सकल और निवल गैर-निष्पादित आस्तियां कई वर्षों के निचले स्तर पर हैं, और बैंक आस्ति गुणवत्ता में सुधार एक स्वस्थ और स्थिर बैंकिंग क्षेत्र के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। पूंजीगत बाजार भारत की विकास कहानी में प्रमुख बन रहे हैं, जिसमें प्रौद्योगिकी, नवाचार और डिजिटलीकरण के बल पर पूंजी निर्माण और निवेश परिदृश्य में हिस्सेदारी बढ़ रही है। भारतीय शेयर बाजार सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले बाजारों में से एक रहा है, जिसमें वित्त वर्ष 2024 के दौरान भारत का निफ्टी 50 इंडेक्स 26.8 प्रतिशत बढ़ा है, जबकि यह वित्त वर्ष 23 के दौरान (-)8.2 प्रतिशत बढ़ा था। भारतीय शेयर बाजार के बाजार पूंजीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसमें बाजार पूंजीकरण जीडीपी अनुपात दुनिया में पांचवां सबसे बड़ा है। विनियामक उपायों और 'वर्ष 2047 तक सभी के लिए बीमा' हासिल करने के दृष्टिकोण से समर्थित, भारत अगले पांच वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ते बीमा बाजारों में से एक के रूप में उभरने के लिए तैयार है। पेंशन क्षेत्र में ग्राहकों और प्रबंधनाधीन आस्तियों में मजबूत वृद्धि देखी गई है।

भारत के वित्तीय क्षेत्र के लिए संभावनाएं उज्ज्वल दिखाई दे रही हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों पर आगे ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। शेयर बाजार में खुदरा निवेशकों की उल्लेखनीय वृद्धि पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अति आत्मविश्वास के कारण सट्टेबाजी और अधिक रिटर्न की उम्मीद की संभावना है, जो वास्तविक बाजार स्थितियों के अनुरूप नहीं हो सकती है, यह एक गंभीर चिंता का विषय है। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए, वित्तीय क्षेत्र को बैंकिंग क्षेत्र का समर्थन करने और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक पूंजी की कमी को पूरा करने की आवश्यकता है। इसलिए, वित्तीय क्षेत्र को ऐसी गति से विस्तार करना चाहिए जो आर्थिक विकास के साथ तालमेल बिठाए। विशेष रूप से, भारत अपने वर्तमान विकास चरण में अर्थव्यवस्था पर वित्तीयकरण का जोखिम नहीं उठा सकता है।

वित्तीय बाजारों में खुदरा बिक्री में वृद्धि की भागीदारी और वित्तीय उत्पादों से परिचितता भारत के विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने के साथ ही बढ़ने लगी है। इसलिए, बैंकिंग, बीमा और पूंजीगत बाजारों में काम करने वाली फर्मों को उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखना चाहिए और निष्पक्ष बिक्री, प्रकटीकरण, पारदर्शिता, विश्वसनीयता और जवाबदेही के माध्यम से अपनी सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए। उनकी आंतरिक मूल्यांकन और प्रोत्साहन प्रणाली इन विचारों के अनुरूप होनी चाहिए। यह उनके और राष्ट्र के हित में है कि वे दीर्घावधि में अपने वाणिज्यिक लक्ष्यों के अनुकूल हैं।

परिचय

2.1 भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्रों ने निरंतर भू-राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद मजबूत प्रदर्शन किया है। केंद्रीय बैंक ने पूरे वर्ष एक स्थिर नीति दर बनाए रखी, जिसमें समग्र मुद्रास्फीति दर नियंत्रण में रही। रूस-यूक्रेन संघर्ष के बाद मौद्रिक सख्ती के प्रभाव बैंकों के बीच ऋण और जमा ब्याज दरों में वृद्धि में स्पष्ट हैं। बैंक ऋणों में विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण और व्यापक वृद्धि देखी गई, जिसमें व्यक्तिगत ऋण और सेवाएं सबसे आगे रहीं।

2.2 पूंजी बाजारों ने भी प्रभावशाली परिणाम दिखाए हैं, जिसमें भारत का शेयर बाजार पूंजीकरण जीडीपी अनुपात में वैश्विक स्तर पर पांचवें स्थान पर रहा है। एक मजबूत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) की विद्यमानता और

1 वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज (डब्ल्यूएफई) के अनुसार

बैंकों और माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (एमएफआई) की अधिक भागीदारी से वित्तीय समावेशन में सुधार करने में योगदान मिला है। बीमा और पेंशन क्षेत्र भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसा कि उनके व्यय कवरेज से प्रदर्शित होता है।

2.3 इस पृष्ठभूमि में, अध्याय को दो भागों में विभाजित किया गया है- मौद्रिक विकास और वित्तीय मध्यस्थता। मौद्रिक विकास भाग अर्थव्यवस्था की मौद्रिक और तरलता स्थितियों को प्रस्तुत करता है।

2.4 वित्तीय मध्यस्थता भाग विभिन्न वित्तीय संस्थानों और वित्तीय बाजार लिखतों की स्थिति पर चर्चा करता है जो भारत में वित्तीय बाजार परिवेश का हिस्सा हैं। इस भाग का खंड I देश के बैंकिंग क्षेत्र के प्रदर्शन को प्रस्तुत करता है, जो वित्तीय मध्यस्थता परिदृश्य का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। खंड II संकटग्रस्त आस्तियों का निपटान करने के लिए सरकार के तंत्र और इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी/कोड) दिवालियापन का समाधान करने में एक गेम-चेंजर के रूप में उभरी है। खंड III में डिजिटल वित्तीय समावेशन और डेटा सुरक्षा पर अधिक जोर देने के साथ वित्तीय समावेशन के प्रति सरकार के दृष्टिकोण पर चर्चा की गई है। खंड IV में वित्तीय समावेशन को सुविधाजनक बनाने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में एमएफआई की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। खंड V में प्रतिभूति बाजारों पर चर्चा की गई है, जो कॉर्पोरेट क्षेत्र और सरकार के लिए संसाधन जुटाने का एक वैकल्पिक और कुशल साधन बनने के लिए एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। प्रौद्योगिकी और विनियमन में सर्वोत्तम प्रथाओं का उपयोग करने में भारत के प्रतिभूति बाजारों का वैश्विक कदम की बात है। खंड VI में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्त टेक-सिटी (आईएफएससी जीआईएफटी सिटी) और यह कैसे एक वैश्विक वित्तीय और आईटी सेवा हब के रूप में उभर रहा है, के बारे में बताया गया है। खंड VII और VIII में बीमा और पेंशन क्षेत्रों में विकास प्रस्तुत किया गया है। खंड IX में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, नियामक समन्वय और समग्र वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के तंत्र पर चर्चा की गई है। खंड X में आगे बढ़ने के लिए प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख करते हुए, वित्तीय क्षेत्र के लिए एक समग्र निष्कर्ष और दृष्टिकोण प्रदान किया गया है।

मौद्रिक विकास

2.5 मौद्रिक नीति आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति और निवेश जैसे व्यापक आर्थिक संकेतकों पर अपने प्रभाव के माध्यम से किसी देश की आर्थिक स्थितियों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। मौद्रिक नीति की विभिन्न लिखतें, जैसे बैंकों के नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) और वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर), केंद्रीय बैंक के खुले बाजार संचालन और ऋण की सीमा निर्धारित करना आदि, केंद्रीय बैंक द्वारा इस समग्र उद्देश्य की दिशा में उपयोग किए जाते हैं। अध्याय का यह खंड अर्थव्यवस्था में हाल के मौद्रिक विकास को प्रस्तुत करता है, जो उभरती हुई तरलता स्थितियों और बैंकों की उधार और जमा दरों के संदर्भ में मौद्रिक नीति संचरण पर ध्यान केंद्रित करता है।

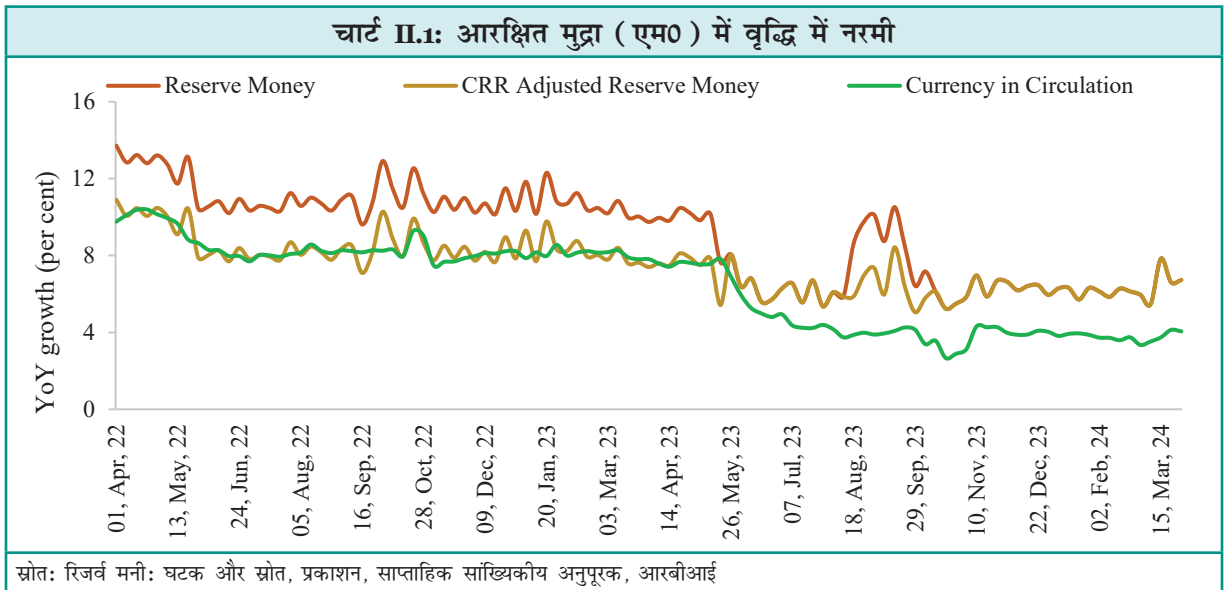
मौद्रिक और ऋण शर्तें

2.6 वर्ष के दौरान मौद्रिक और ऋण की स्थिति मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप विकसित हुई, जिससे घरेलू आर्थिक गतिविधि को सहायता मिली है। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने वित्त वर्ष 24 में नीतिगत रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर यथास्थिति बनाए रखा। इसने यह सुनिश्चित करने के लिए समायोजन वापस लेने पर ध्यान केंद्रित किया है कि मुद्रास्फीति धीरे-धीरे लक्ष्य के अनुरूप हो और विकास को समर्थन मिले। मई 2022 और फरवरी 2023 के बीच किए गए 250 आधार अंकों (बीपीएस) की संचयी नीति रेपो दर वृद्धि के साथ, अर्थव्यवस्था में अपना काम करते हुए, एमपीसी ने फरवरी 2023 से नीति रेपो दर को स्थिति की मांग होने पर उचित और समय पर नीतिगत कार्रवाई करने के लिए तत्परता के साथ बिना परिवर्तन के 6.5 प्रतिशत पर रखा गया है।

2.7 वित्त वर्ष 24 के दौरान मौद्रिक और ऋण स्थितियों के विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक, ₹2,000

बैंक नोटों की वापसी (मई 2023)² एचडीएफसी बैंक के साथ एक गैर-बैंक एचडीएफसी का विलय (जुलाई 2023), और वृद्धिशील सीआरआर (आई-सीआरआर) का अस्थायी अधिरोपण (अगस्त 2023) थे। बैंकिंग प्रणाली में जमा के रूप में ₹2,000 बैंक नोटों के एक बड़े हिस्से की वापसी के कारण आरक्षित धन और प्रचलन में मुद्रा (सीआईसी) में विस्तार धीमा हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार, प्रचलन में ₹2,000 के बैंक नोटों का कुल मूल्य 19 मई 2023 (जब ₹2,000 के बैंक नोटों को वापस लेने की घोषणा की गई थी) तक ₹3.56 लाख करोड़ से घटकर 28 जून 2024 तक ₹7,581 करोड़ रह गया है, जो दर्शाता है कि ₹2,000 मूल्यवर्ग के 97.87 प्रतिशत बैंक नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं। इसने और सावधि जमा दरों में वृद्धि ने कुल जमा और व्यापक धन (एम3) में तेजी लाने में योगदान दिया। प्रचलन में मुद्रा (सीआईसी) में वृद्धि पिछले वर्ष के 7.8 प्रतिशत से घटकर 4.1 प्रतिशत हो गई, जो ₹2,000 के बैंक नोटों को वापस लेने के प्रभाव को दर्शाती है।

2.8 रिजर्व मनी (एमओ) ने 29 मार्च 2024 तक 6.7 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष (वाईओवाई) वृद्धि दर्ज की, जबकि पिछले वर्ष यह 9.7 प्रतिशत थी। सीआरआर में बदलावों के पहले दौर के प्रभाव के लिए समायोजित एमओ ने एक साल पहले 7.4 प्रतिशत की तुलना में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। एमओ में वृद्धि मुख्य रूप से वित्त वर्ष 2024 के दौरान शुद्ध विदेशी परिसंपत्तियों (एनएफए) द्वारा संचालित थी।



2.9 एचडीएफसी बैंक के साथ एचडीएफसी के विलय (1 जुलाई 2023 से प्रभावी) के प्रभाव को छोड़कर ब्रॉड मनी (एम3) में वृद्धि 22 मार्च 2024 तक 11.2 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) थी, जबकि एक साल पहले यह 9 प्रतिशत थी। घटकों के मामले में सबसे महत्वपूर्ण घटक, कुल जमा (एडी) ने एम3 के विस्तार में सबसे अधिक योगदान दिया। स्रोतों में, वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण ने एम3 में वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसकी हिस्सेदारी 22 मार्च 2024 तक

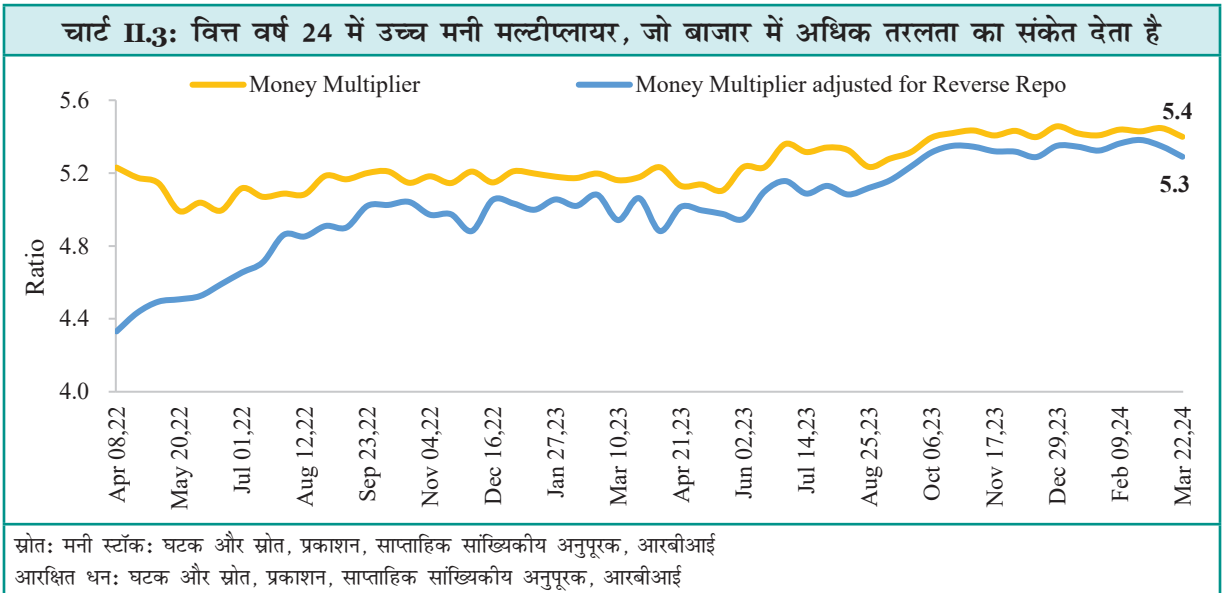
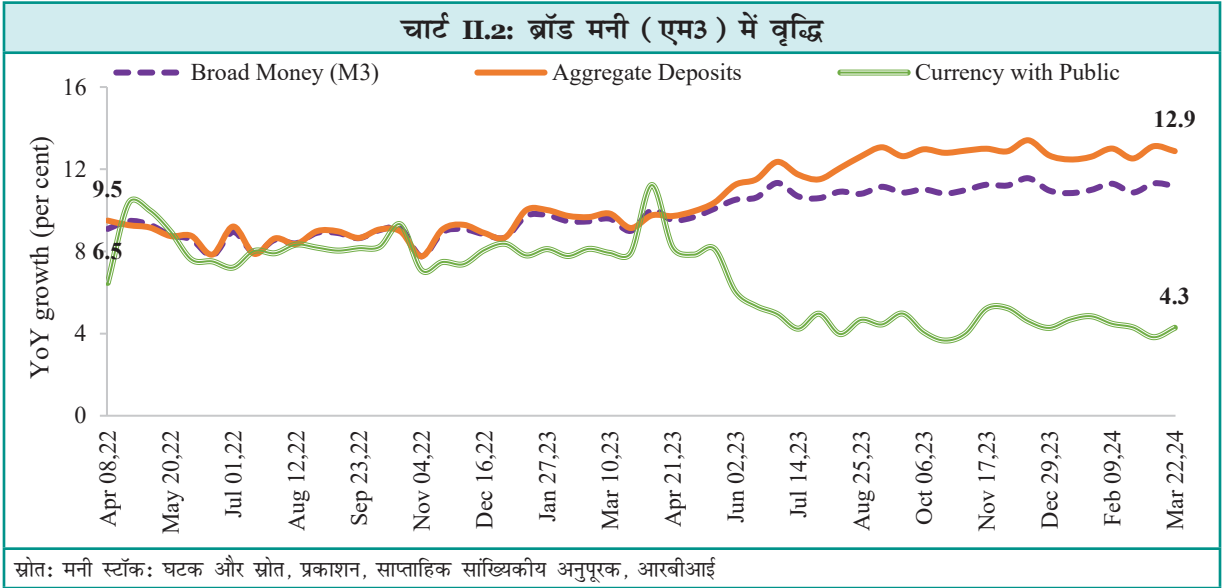
2 19 मई 2023 के परिपत्र

https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=55707 के तहत, आरबीआई ने ₹2000 के बैंक नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की है क्योंकि (i) ₹2000 मूल्यवर्ग के लगभग 89% बैंक नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे और अब उनका अनुमानित जीवन काल 4-5 वर्ष पूरा होने वाला है; (ii) प्रचलन में इन बैंक नोटों का कुल मूल्य 31 मार्च 2018 तक अपने चरम पर ₹6.73 लाख करोड़ (प्रचलन में नोटों का 37.3%) से घटकर ₹3.62 लाख करोड़ हो गया है, जो 31 मार्च 2023 तक प्रचलन में नोटों का केवल 10.8% है; (iii) इस मूल्यवर्ग का लेन-देन के लिए सामान्यतः उपयोग नहीं किया जाता है, और (iv) अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों का स्टॉक जनता की मुद्रा आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त बना हुआ है।

3 आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 1 जुलाई, 2024, '2000 रुपये के मूल्यवर्ग के नोटों के निकासी-स्थिति', https://www.rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=58199

4 व्यापक मुद्रा के घटक = जनता के पास मुद्रा+ कुल जमा (बैंकों के पास मांग जमा + बैंकों के पास समय सीमा के लिए जमा + रिजर्व बैंक के अन्य डिपॉजिट)

67.1 प्रतिशत थी, जिसे सरकार को दिए गए निवल बैंक ऋण (29.4 प्रतिशत की हिस्सेदारी⁵) द्वारा पूरक बनाया गया।



2.10 22 मार्च 2024 तक, मुद्रा गुणक (एमएम) एक साल पहले 5.2 के मुकाबले 5.4 था। केंद्रीय बैंक के पास बैंकों की जमा राशियों के विश्लेषणात्मक रूप से समान रिवर्स रेपो राशियों के लिए समायोजित, मार्च 2024⁶ तक समायोजित एमएम मामूली रूप से कम होकर 5.3 पर था।

नीति दरों में तरलता की स्थिति और रुझान

2.11 आरबीआई के तरलता प्रबंधन में तरलता की स्थिति में बदलाव के जवाब में दो-तरफा संचालन शामिल थे। वित्त वर्ष 2024 के दौरान, 17 पाक्षिक परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) नीलामी और सात परिवर्तनीय दर रेपो

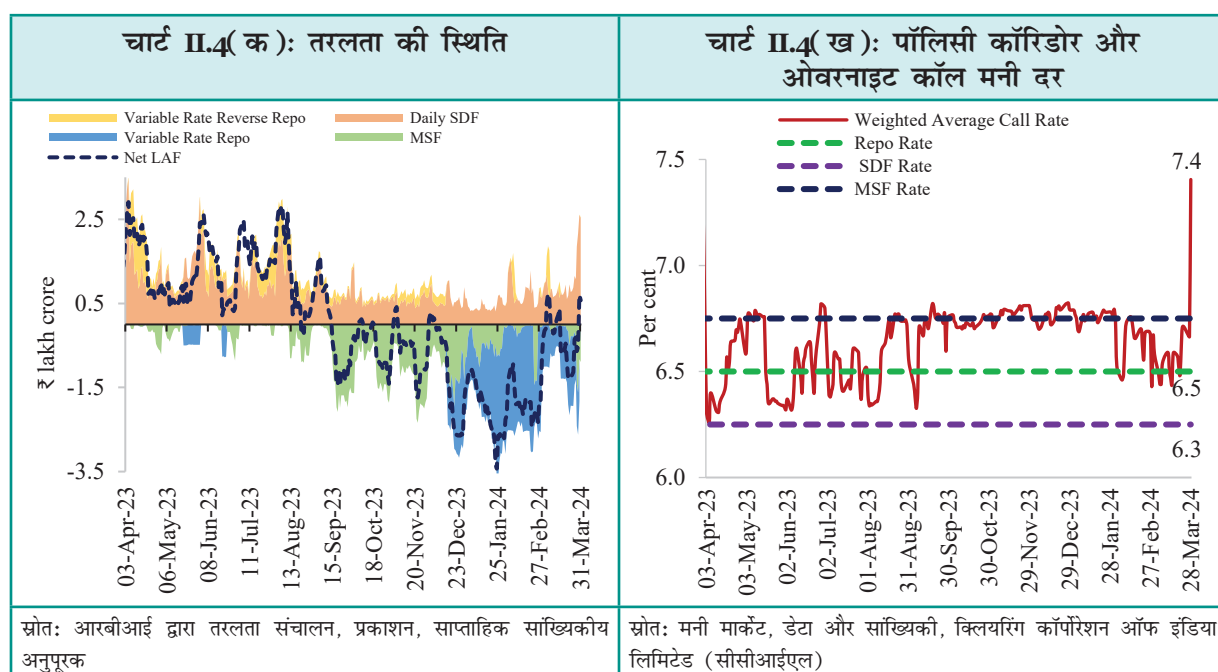
5 व्यापक मुद्रा के स्रोत = सरकार को निवल बैंक ऋण + वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण + बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां + जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएँ - बैंकिंग क्षेत्र की शुद्ध गैर-मौद्रिक देयताएँ)

6 मनी मल्टीप्लायर (एमएम) एम 3 की उस राशि को संदर्भित करता है जो बैंक अपने पास उपलब्ध एमओ के प्रत्येक रुपये से उत्पन्न करता है। यह मौद्रिक आधार और अर्थव्यवस्था की मुद्रा आपूर्ति के बीच के संबंध को दर्शाता है, जो यह दर्शाता है कि बैंक की उधार गतिविधि से मुद्रा आपूर्ति कितनी तेजी से बढ़ेगी। एमएम का मूल्य जितना अधिक होगा और इसके विपरीत बाजार में तरलता उतनी ही अधिक होगी।

(वीआरआर) नीलामी प्राथमिक संचालन के रूप में की गई। इसके अलावा, मौद्रिक नीति रुख के साथ सरेखण में तरलता की स्थिति को संशोधित करते हुए, 49 फाइन-ट्यूनिंग ऑपरेशन (25 वीआरआरआर और 24 वीआरआर) कुछ अंतराल पर किए गए। सख्त तरलता स्थितियों के बीच, बैंकों ने सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) का भी सहारा लिया। स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के तहत अधिशेष निधियों के व्यापक उपयोग और एमएसएफ के एक साथ उपयोग को देखते हुए, एसडीएफ और एमएसएफ दोनों के तहत चलनिधि सुविधाओं को 30 दिसंबर 2023⁷ से सप्ताहांत और छुट्टियों के दौरान भी वापस लेने की अनुमति दी गई।

2.12 अतिरिक्त तरलता से मूल्य और वित्तीय स्थिरता को होने वाले जोखिम और अन्य बातों के साथ-साथ बैंकिंग प्रणाली में 2,000 रुपये के नोट वापस आने के कारण अधिशेष तरलता में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, आरबीआई ने 10 अगस्त 2023 को 10 प्रतिशत का अस्थायी आई-सीआरआर घोषित किया। आई-सीआरआर, जिसने बैंकिंग प्रणाली से लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपये जब्त किए, की 8 सितंबर 2023 को समीक्षा की गई और 7 अक्टूबर 2023 को समाप्त होने वाले चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया गया। इस प्रकार जब्त की गई राशि 10 अगस्त 2023⁸ को विकासात्मक और नियामक नीतियों की घोषणा के अनुरूप त्रैहारी सीजन से पहले बैंकिंग प्रणाली को जारी कर दी गई। इन कार्रवाईयों के परिणामस्वरूप बैंकिंग प्रणाली की तरलता धीमी हो गई, जिससे सितम्बर के मध्य में घाटा हो गया, जो वित्त वर्ष 2024 के दौरान जारी रहा।

तरलता की स्थिति में नरमी



मौद्रिक नीति संचरण

2.13 वित्त वर्ष 2024 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की उधार और जमा दरों में अधिक वृद्धि हुई, जो मई 2022-फरवरी 2023 के दौरान नीतिगत दरों में वृद्धि, ऋण मूल्य निर्धारण की बाहरी बेंचमार्क-आधारित उधार दर प्रणाली और अधिशेष तरलता के संयम के विलंबित प्रभाव को दर्शाती है। मौजूदा सख्त चक्र के दौरान, अर्थात मई 2022 से मई 2024 तक, बाहरी बेंचमार्क-आधारित उधार दर और एक वर्षीय औसत सीमांत-लागत-निधि-आधारित उधार दर में क्रमशः 250 बीपीएस और 175 बीपीएस की वृद्धि हुई। नीतिगत दरों में वृद्धि का उधार और जमा दरों पर संचरण तालिका II.1 में दिया गया है।

7 इस उपाय की समीक्षा छह महीने बाद या जरूरत पड़ने पर पहले भी की जाएगी।

8 आरबीआई गवर्नर का बयान: 10 अगस्त 2023, पैरा 18, https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=56175

तालिका II.1: घरेलू ऋण और जमा दरों में संचरण में तेजी

	मई-2022 से मई-2024	अप्रैल-2023 से मार्च-2024
डब्ल्यूएलआर- बकाया रुपया ऋण	1.14	0.11
डब्ल्यूएलआर - नया रुपया ऋण	1.88	0.05
डब्ल्यूडीटीडीआर- बकाया रुपया जमा	1.90	0.73
डब्ल्यूडीटीडीआर - नया रुपया जमा	2.44	0.14

स्रोत: एससीबी की उधार और जमा दरें, आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति (विभिन्न अंक)

नोट: डब्ल्यूएलआर: भारत औसत उधार दर

डब्ल्यूडीटीडीआर: भारत औसत घरेलू सावधि जमा दर

वित्तीय मध्यस्थता

2.14 वित्तीय विकास और आर्थिक वृद्धि एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई हैं, और वित्तीय मध्यस्थता वह मार्ग है जिसके माध्यम से पूर्व को उत्तरार्द्ध में परिवर्तित किया जाता है। वित्तीय मध्यस्थता सीमित संसाधनों के कुशल आवंटन में मदद करती है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जोसेफ शम्पीटर का मानना था कि वित्तीय मध्यस्थों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, जैसे बचत जुटाना, ऋण देना, आस्तियों का भंडारण करना, उन्हें बढ़ाना, जोखिम प्रबंधन करना और लेन-देन को सुविधाजनक बनाना, जो तकनीकी नवाचार और आर्थिक विकास⁹ के लिए आवश्यक थीं। वित्तीय मध्यस्थता विदेशी पूंजी प्रवाह को भी सुविधाजनक बनाती है और प्रोत्साहित करती है। अनुभवजन्य अध्ययनों¹⁰ से पता चलता है कि कुशल और विकसित वित्तीय बाजार बचत के आवंटन और उपयोग में सुधार करके और कमजोर समूहों और छोटे और मध्यम आकार की फर्मों सहित समाज के सभी वर्गों के लिए वित्त तक पहुँच सुनिश्चित करके बढ़ी हुई और समावेशी आर्थिक वृद्धि हो सकती हैं।

2.15 वित्तीय विकास के मापदंड न केवल सुदृढ़ होने चाहिए, बल्कि वे समग्र रूप से प्रणाली की वित्तीय स्थिरता भी सुनिश्चित करते हैं। इसके लिए जोखिम के लिए पूंजी (भारत) आस्ति अनुपात (सीआरएआर), जमाशियों के लिए तरल संपत्ति और अल्पकालिक ऋण जैसे संकेतकों को प्रबंधनीय सीमाओं के भीतर होना चाहिए। इसके अलावा, वित्तीय क्षेत्र के विकास का एक अनिवार्य हिस्सा सभी वित्तीय बाजार संस्थाओं, बाजार के किरदारों और वित्तीय लिखतों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए मजबूत नीतियों को लागू करना है। इस संबंध में नियामकों के बीच समन्वय सर्वोपरि है।

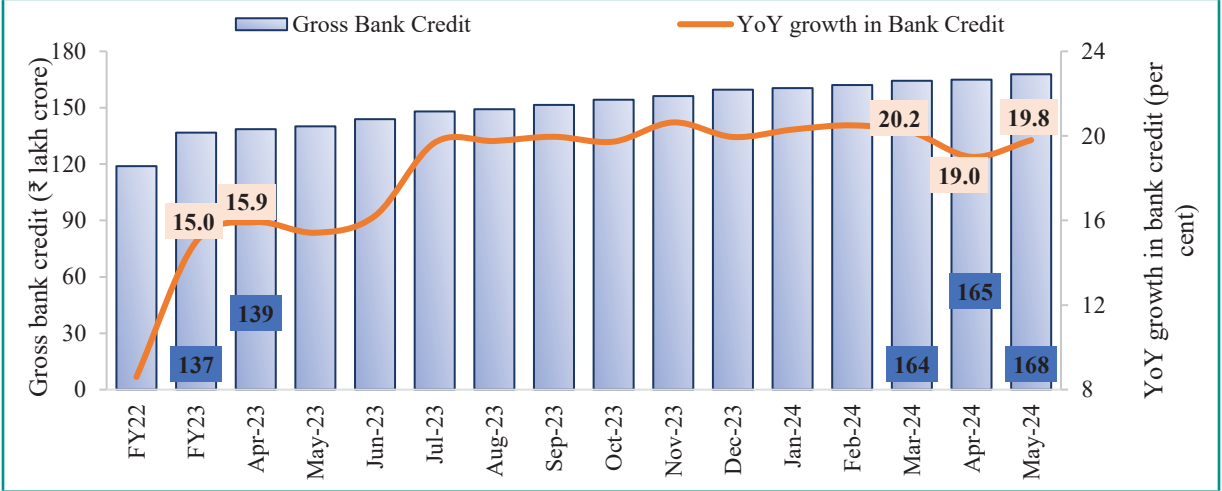
बैंकिंग क्षेत्र का प्रदर्शन और ऋण उपलब्धता

2.16 भारत के बैंकिंग क्षेत्र की सुदृढ़ता और समुत्थानशील आस्ति गुणवत्ता में निरंतर सुधार, अशोध्य ऋणों के लिए बेहतर प्रावधान, निरंतर पूंजी पर्याप्तता और लाभप्रदता में वृद्धि द्वारा समर्थित है। ऋण वृद्धि मजबूत बनी हुई है, जो मुख्य रूप से सेवाओं और व्यक्तिगत ऋणों को उधार देने से है। जैसा कि पैरा 2.9-2.10 में उल्लेख किया गया है, पिछली दर वृद्धि के संचरण के कारण जमा वृद्धि ने भी गति पकड़ी है, जिसके परिणामस्वरूप जमाओं का पुनर्मूल्यन हुआ है और सावधि जमाओं में वृद्धि हुई है। व्यक्तिगत ऋण और उद्योग को ऋण के कारण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा ऋण देने में तेजी आई है और उनकी आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

9 शम्पीटर, जोसेफ ए. आर्थिक विकास का सिद्धांत, (कैम्ब्रिज, एमए: हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1911)।

10 एर्रेस्टिस, पी., और डेमेट्रिएड्स, पी. (1997)। वित्तीय विकास और आर्थिक वृद्धि: साक्ष्य का आकलन। द इकोनॉमिक जर्नल, 107(142), 783-799; अजियाकपोनो, एम. जे. (2011)। वित्तीय विकास और आर्थिक वृद्धि: सिद्धांत और साक्ष्य का सर्वेक्षण। अर्थशास्त्र और अर्थमिति में अध्ययन, 35(1), 15-43; कैलडरॉन, सी., और लियू, एल. (2003)। वित्तीय विकास और आर्थिक वृद्धि के बीच कार्य-कारण की दिशा। जर्नल ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, 72(1), 321-334।

चार्ट II.5: एससीबी द्वारा ऋण वितरण में दोहरे अंकों की वृद्धि



स्रोत: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा बैंक ऋण की नियुक्ति, भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका, तालिका संख्या 170, आरबीआई टिप्पणी: इन आंकड़ों में बैंकों के साथ नॉन बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।

2.17 वित्त वर्ष 2024 के दौरान बैंक ऋण वृद्धि ने गति बनाए रखी है, जिसमें सभी क्षेत्रों में व्यापक आधार पर वृद्धि हुई है। मार्च 2024 के अंत में एससीबी द्वारा ऋण वितरण 20.2 प्रतिशत से बढ़कर 164.3 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि मार्च 2023 के अंत में यह 15 प्रतिशत की वृद्धि के साथ रहा। यह प्रवृत्ति वित्त वर्ष 2025 में भी जारी रहने की उम्मीद है, जैसा कि अप्रैल और मई 2024 में बैंक ऋण में 19 और 19.8 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि से पता चलता है।

क्षेत्रीय ऋण वृद्धि

2.18 कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण में वृद्धि दोहरे अंकों में रही। कृषि ऋण वित्त वर्ष 2021 में 13.3 लाख करोड़ से लगभग 1.5 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 20.7 लाख करोड़ हो गया। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना ने किसानों को समय पर और अवरोध मुक्त ऋण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें वर्ष 2023 के अंत तक¹¹ 7.4 करोड़ से अधिक सक्रिय केसीसी खाते हैं। कृषि क्षेत्र को ऋण वितरण में वृद्धि अप्रैल और मई 2024 में जारी रही, जिसमें कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को बैंक ऋण में 19.7 प्रतिशत और 21.6 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) क्रमशः की वृद्धि हुई।

2.19 वित्त वर्ष 2024 की दूसरी छमाही में औद्योगिक ऋण वृद्धि में तेजी आई, जो एक साल पहले 5.2 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2024 में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो छोटे और बड़े उद्योगों को बैंक ऋण में वृद्धि के कारण थी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ऋण वितरण में वृद्धि को आपातकालीन ऋण संबद्ध गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत 100 प्रतिशत ऋण गारंटी के साथ संपार्श्विक-मुक्त ऋण की उपलब्धता द्वारा समर्थित किया गया है। इसके अलावा, समृद्ध और समय पर ऋण डेटा की उपलब्धता और डिजिटल ऋण अवसंरचना के तेजी से कार्यान्वयन से ऋणदाताओं के विश्वास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। बॉक्स II.1 में एमएसएमई को ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने और उनकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों पर चर्चा की गई है। भविष्य में, ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क (ओसीईएन)¹² जैसी नई तकनीकों के विकास से एमएसएमई क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

11 वित्त मंत्रालय की पीआईबी प्रेस विज्ञापित दिनांक 27 दिसंबर 2023, <https://shorturl.at/EqWwK>

12 ओसीईएन एक विकेन्द्रीकृत खुला ऋण नेटवर्क है जो उधारकर्ताओं, उधारदाताओं और ऋण वितरकों के बीच ऋण के प्रवाह को मानकों के एक सामान्य सेट के तहत संहिताबद्ध करता है। इससे देश के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को और मजबूत करने की उम्मीद है

बॉक्स II.1: औपचारिकीकरण के माध्यम से एमएसएमई को बैंक ऋण का प्रवाह बढ़ाना

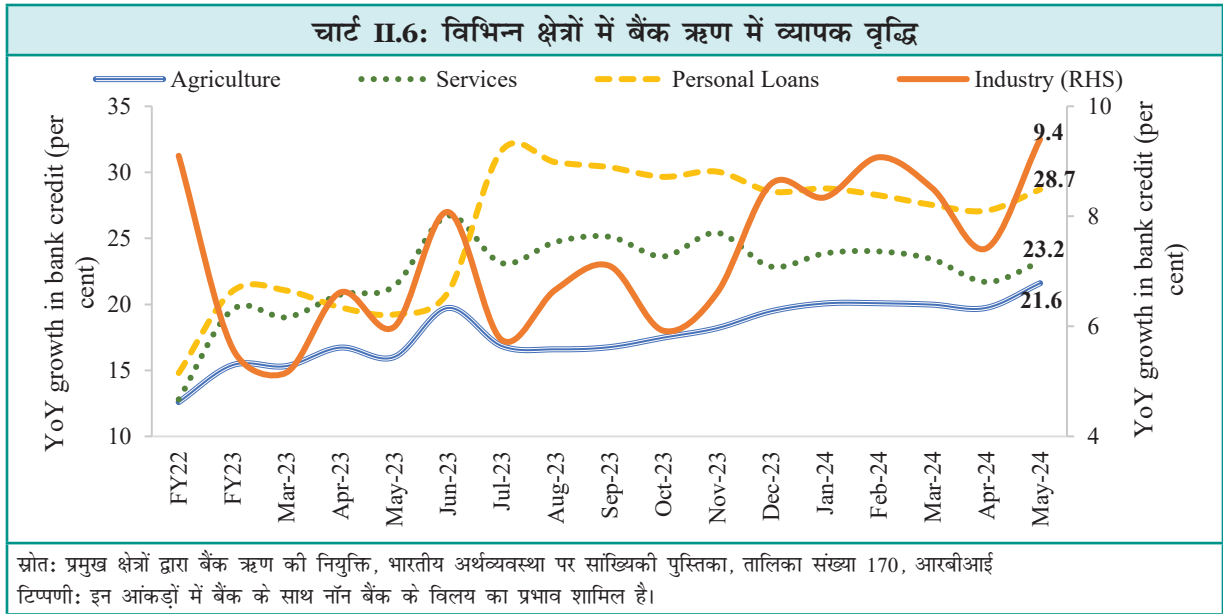
एमएसएमई क्षेत्र को कम लागत पर ऋण प्रवाह में सुधार करना सरकार और आरबीआई की नीतिगत प्राथमिकता रही है। इस संबंध में विभिन्न पहलें की गई हैं। इनका विवरण नीचे दिया गया है¹³

- **व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (टीआरईडीएस) की शुरूआत:** टीआरईडीएस एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो तरलता और कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई वित्तपोषकों- बैंकों और एनबीएफसी- के माध्यम से एमएसएमई के व्यापार प्राप्तियों की छूट की सुविधा प्रदान करता है। कुल मिलाकर, टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म पर 2.9 लाख करोड़ की राशि के 98.9 लाख इनवॉइस पर 31 मार्च, 2024 तक छूट मिली हैं, जिससे एमएसएमई को बेहतर तरलता और कार्यशील पूंजीगत प्रबंधन के लिए सहायता मिली है।
- **एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव:** 1 जुलाई 2020 से, एमएसएमई को टर्नओवर और संयंत्र और मशीनरी/ उपकरण में निवेश के समग्र मानदंडों के अनुसार परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, इससे बड़ी संख्या में उद्यमियों को औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र के दायरे में लाने की परिकल्पना की गई है, जिससे उद्योग को रियायती दरों पर ऋण का प्रवाह सुगम होगा।
- **उद्यम पोर्टल पर एमएसएमई का पंजीकरण:** एमएसएमई मंत्रालय ने 1 जुलाई 2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल (यूआरपी) लॉन्च किया और तब से इसने खुद को व्यापार करने में आसानी के लिए एक आवश्यक प्रवर्तक के रूप में स्थापित किया है, क्योंकि यह निःशुल्क, सरल और ऑनलाइन है। यह उद्यमियों को औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र के दायरे में लाने के लिए किया गया था, जिससे एमएसएमई को रियायती दरों पर ऋण का प्रवाह सुगम होगा। हालांकि, यूआरपी के साथ एक चुनौती अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) का पंजीकरण है। जो संख्या में काफी है। 73वें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार, वित्त वर्ष 2016 में 6.3 करोड़ अनिगमित गैर-कृषि संस्थाएं मौजूद थीं, जो मुख्य रूप से सूक्ष्म उद्यम थे चूंकि आईएमई के पास पैन/जीएसटी नहीं है, इसलिए वे यू आर पी पर पंजीकरण नहीं करा सकते और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते। ऐसे उद्यमों को औपचारिक रूप देने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय ने भारतीय लघु उद्योग और भारतीय विकास बैंक (सिडबी) के सहयोग से 11 जनवरी 2023 को उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म (यूएपी) लॉन्च किया। औपचारिकता के माध्यम से अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को विभिन्न सुविधाओं, जैसे; बाजारों और ऋण तक पहुंच आदि से जोड़ा जाएगा। जून 2024 तक, 1.86 करोड़ आईएमई यूएपी पर शामिल हो चुके हैं। 3 जून 2024 तक यूआरपी और यूएपी पर 4.5 करोड़ से अधिक उद्यम पंजीकृत हो चुके हैं।
- **एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस) का पुनरुद्धार:** केंद्रीय बजट वित्त वर्ष 23 में, एमएसई के लिए 2 लाख करोड़ के अतिरिक्त ऋण की सुविधा के लिए आवश्यक धनराशि के साथ सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सीजीएस के पुनरुद्धार की घोषणा की गई थी। तदनुसार, एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के कोष में 9,000/- करोड़ रुपये की समावेशन से सीजीएस का पुनरुद्धार किया गया था। इसके बाद, उक्त योजना के तहत ऋण सीमा को ₹2 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ कर दिया गया, जिसमें न्यूनतम वार्षिक गारंटी शुल्क 0.37 प्रतिशत प्रति वर्ष था। परिणामस्वरूप, चार वर्षों में ₹2 लाख करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले वित्त वर्ष 2023 और वित्त वर्ष 2024 के दौरान ₹3 लाख करोड़ की ऋण गारंटी स्वीकृत की गई। वित्त वर्ष 2023 के दौरान, ₹1.04 लाख करोड़ की गारंटी में से, ₹16,373 करोड़ और ₹2,750 करोड़ क्रमशः महिलाओं और एससी/एसटी के स्वामित्व वाले उद्यमों को दिए गए। वित्त वर्ष 2024 में ₹2.02 लाख करोड़ की गारंटी दी गई, जिसमें से क्रमशः ₹32,223 करोड़ और ₹5,393 करोड़ महिलाओं और एससी/एसटी के स्वामित्व वाले उद्यमों को दिए गए।

13 यह बॉक्स राइट अप एमएसएमई मंत्रालय और यूडीवाईएम पोर्टल, <https://www.msme.gov.in/>, <https://udyamregistration.gov.in/> से प्राप्त जानकारी/ डेटा पर आधारित है।

आईएमई को ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, 14 फरवरी 2024 से एमएसएमई मंत्रालय ने एमएसई के लिए मौजूदा सीजीएस के तहत एक विशेष प्रावधान किया है जिसके तहत यूएपी पर पंजीकृत आईएमई प्राथमिक सुरक्षा के बिना और 85 प्रतिशत गारंटी कवरेज और कम वार्षिक गारंटी शुल्क के साथ 20 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वित्तीय संस्थानों को गारंटी लागू करने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता नहीं है।

2.20 एनबीएफसी को ऋण वृद्धि में मंदी के बावजूद सेवा क्षेत्र को बैंक ऋण वितरण लचीला रहा। सेवा क्षेत्र के भीतर, वित्त वर्ष 24 की दूसरी छमाही में 'वाणिज्यिक अचल संपत्ति' और 'व्यापार' उप-क्षेत्रों को ऋण वितरण में सुधार हुआ है। बैंकों द्वारा वितरित ऋण में व्यक्तिगत ऋण और एनबीएफसी का सबसे बड़ा हिस्सा है। व्यक्तिगत ऋणों के भीतर, आवास ऋण में, अप्रैल और मई 2024 में वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2024 के दौरान सीमित रही।



2.21 आवास ऋण के लिए ऋण वितरण मार्च 2023 में ₹19.9 लाख करोड़ से बढ़कर मार्च 2024 में ₹27.2 लाख करोड़ हो गया। व्यक्तिगत ऋणों में ऋण वृद्धि का श्रेय पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण डिजिटलीकरण को दिया जा सकता है, जिसमें तेजी से निर्णय लेने, डेटा संग्रह और सत्यापन और ई-कॉमर्स लेनदेन के लिए क्रेडिट ब्यूरो का उपयोग बढ़ गया है। हालांकि, दिसंबर 2023 के बाद व्यक्तिगत ऋण वृद्धि में कमी आई, क्योंकि आरबीआई ने अप्रत्याभूत व्यक्तिगत ऋण, क्रेडिट कार्ड और एनबीएफसी को ऋण देने के लिए पूंजी आवश्यकताओं को 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 125 प्रतिशत^{14,15} कर दिया।

बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार

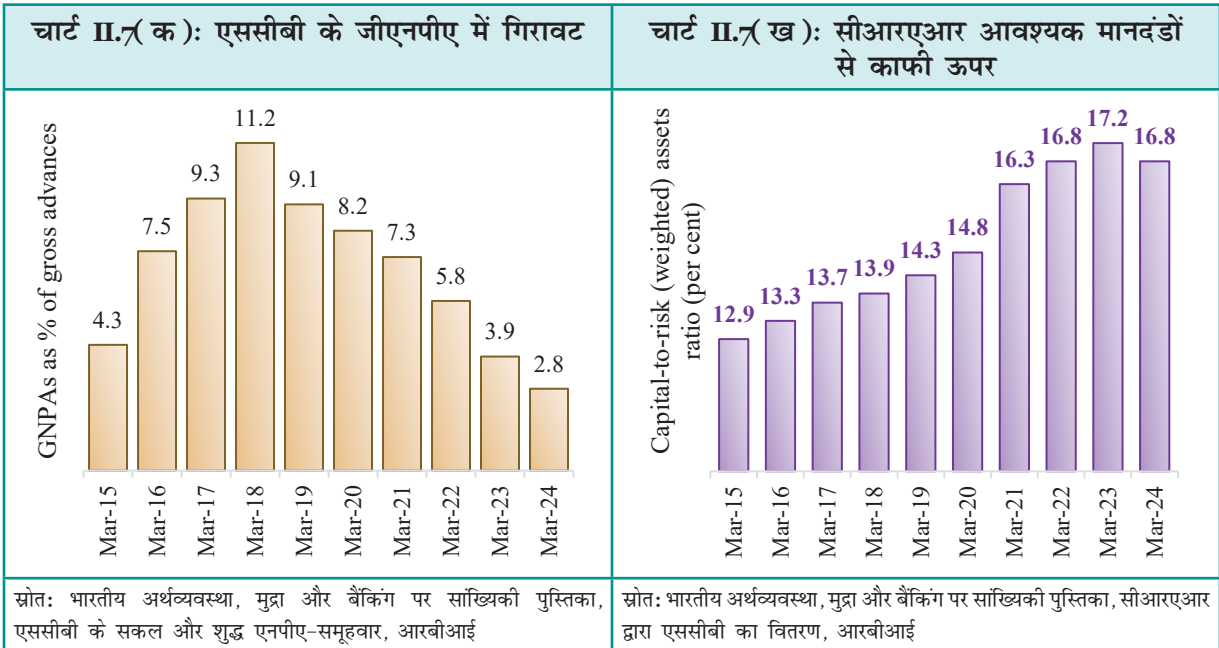
2.22 बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसका कारण उधारकर्ताओं का बेहतर चयन, अधिक प्रभावी ऋण वसूली और बड़े उधारकर्ताओं¹⁶ के बीच ऋण जागरूकता में वृद्धि है। विनियामक पूंजीगत और तरलता आवश्यकताओं के अलावा, गुणात्मक मैट्रिक्स जैसे कि बेहतर प्रकटीकरण, मजबूत आचार संहिता और पारदर्शी शासन संरचना ने भी बैंकिंग प्रदर्शन में सुधार किया है।

14 आरबीआई अधिसूचना, 'एनबीएफसी को उपभोक्ता ऋण और बैंक ऋण के लिए नियामक उपाय', दिनांक 16 नवंबर 2023, <https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12567&Mode=0>

15 आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार

16 वही 15

2.23 एससीबी के सकल गैर-निष्पादित आस्ति (जीएनपीए) अनुपात में गिरावट की प्रवृत्ति जारी रही, जो वित्त वर्ष 2018 में 11.2 प्रतिशत के अपने शिखर से मार्च 2024 के अंत में 2.8 प्रतिशत के 12 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया। कम स्लिपेज और वसूली, उन्नयन और राइट-ऑफ के माध्यम से बकाया जीएनपीए में कमी के कारण यह कमी आई। एससीबी की आस्ति गुणवत्ता में सुधार व्यापक आधार पर हुआ है। कृषि क्षेत्र का जीएनपीए अनुपात मार्च 2024 के अंत में 6.5 प्रतिशत के साथ उच्च स्तर पर बना हुआ है, लेकिन इसमें वित्त वर्ष 2024 की दूसरी छमाही के दौरान लगातार सुधार दर्ज किया गया है। व्यक्तिगत ऋण खंड में जीएनपीए अनुपात सभी श्रेणियों में सुधरा है। वाहनों और परिवहन उपकरणों को छोड़कर औद्योगिक क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण उप-क्षेत्रों में आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है।



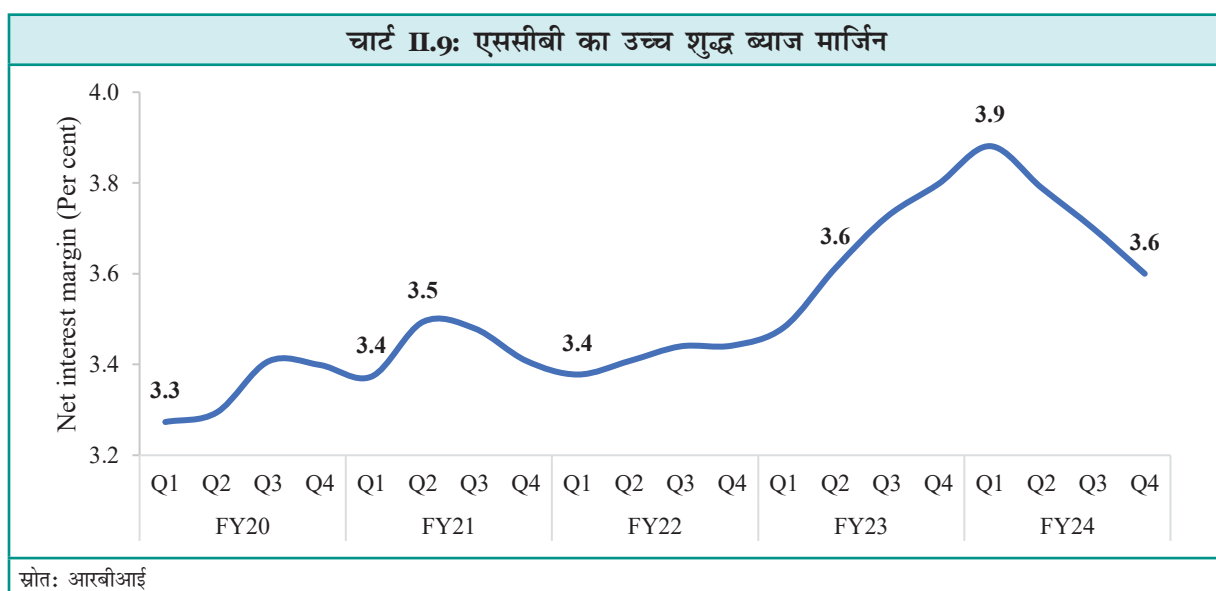
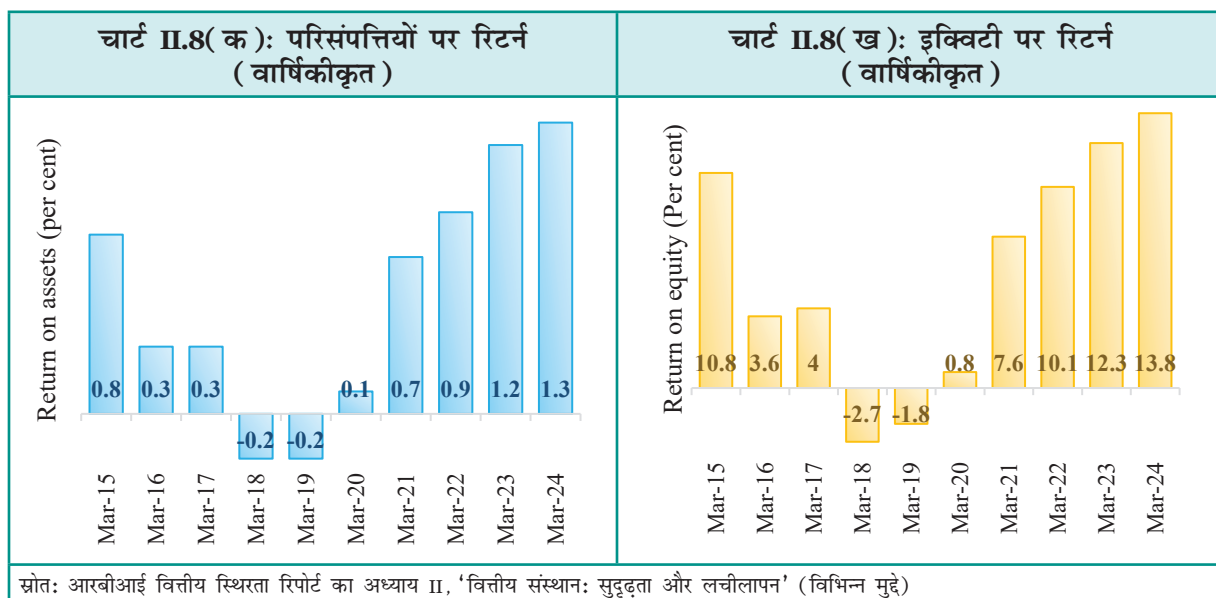
2.24 चूंकि एससीबी ने उच्च लाभ से प्राप्त भंडार को पूंजीकृत करके और नई पूंजी जुटाकर अपने पूंजी आधार को मजबूत किया है, इसलिए मार्च 2024 के अंत तक, 16.8 प्रतिशत हो गया है। सभी बैंकों ने इसे पूरा कर लिया है और साथ ही 13.9 प्रतिशत की सीईटी-1 अनुपात¹⁷ आवश्यकता को भी पूरा कर लिया है, जो नियामक न्यूनतम से काफी ऊपर है।

2.25 मार्च 2024 में एससीबी का शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) 3.6 प्रतिशत पर मजबूत रहा। निवल ब्याज आय और अन्य परिचालन आय में वृद्धि के साथ और अतिरिक्त प्रावधानों की आवश्यकता कम होने के कारण, परिचालन व्यय में बड़ी वृद्धि के बावजूद, मार्च 2024 में उनके कर पश्चात लाभ (पीएटी) में 32.5 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि हुई। लाभप्रदता संकेतक मजबूत रहे, इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) और आस्तियों पर रिटर्न (आरओए) अनुपात मार्च 2024 में दशक के उच्चतम स्तर को छू गए। मौद्रिक नीति दर वृद्धि के संचरण के विलंबित प्रभावों और तरलता स्थितियों में बदलाव के कारण वित्त वर्ष 2024 में आस्तियों पर प्रतिफल में 75 आधार अंकों की वृद्धि के मुकाबले निधियों की लागत में 100 आधार अंकों की वृद्धि हुई है। ब्याज दरों में वृद्धि के कारण आस्तियों पर प्रतिफल में और सुधार हुआ।

2.26 यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 'भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति 2021-22' पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट में, आईबीआई ने पाया कि उच्च एनआईएम वित्तीय स्थिरता के साथ नकारात्मक रूप से सहसंबद्ध है। फिर भी, वह सीमा जिसके ऊपर उच्च एनआईएम वित्तीय स्थिरता के लिए प्रतिकूल है, जो 5 प्रतिशत है। एससीबी का एनआईएम उससे काफी नीचे है। यह वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में 3.9 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जिसके बाद मार्च 2024 तक यह 3.6 प्रतिशत पर आ गया।

17 कॉमन इक्विटी टियर 1 का तात्पर्य सामान्य शेयरों (गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए समतुल्य) और स्टॉक अधिशेष, प्रतिधारित आय, अन्य व्यापक आय, अर्हक अल्पसंख्यक हित और विनियामक समायोजन के योग से है

प्रदर्शन संकेतकों में लगातार सुधार



2.27 भारत के बैंकिंग क्षेत्र ने उल्लेखनीय मजबूती दिखायी है। हाल के वर्षों में आरबीआई और सरकार द्वारा किए गए मैक्रो-और माइक्रो-विवेकपूर्ण उपायों ने जोखिम अवशोषण क्षमता को बढ़ाया है, जिससे बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता में सुधार हुआ है। आरबीआई के बुनियादी सांख्यिकीय रिटर्न 2 (एससीबी के पास जमा) से पता चलता है कि मार्च 2024 तक, भारत की 56.9 प्रतिशत जमा राशि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के पास है। कुल जमा राशि का 61.1 प्रतिशत उन परिवारों के पास है जिन्हें स्टिकी रिटेल ग्राहक माना जाता है; इसलिए, किसी प्रतिकूल घटना की स्थिति में, इस श्रेणी में जमा निकासी सीमित रहने की संभावना है। दूसरा, आस्ति आकार में शीर्ष 10 भारतीय बैंकों के लिए, ऋण उनकी कुल आस्तियों का 50 प्रतिशत से अधिक है, जिससे बैंक बढ़ती ब्याज दर चक्र से प्रतिरक्षित हैं। तीसरा, पिछले वर्षों के दौरान पुनर्पूजीकरण और बैंक बैलेंस शीट के परिशोधन के एक चरण के बाद, विभिन्न बैंकिंग संकेतकों में स्पष्ट सुधार हुआ है। शीर्ष 10 एससीबी (आस्ति आकार के आधार पर) के लिए सीआरएआर बेसल III मानदंडों से काफी ऊपर रहा है। चौथा, भारत में ब्याज दर चक्र काफी प्रमुख रहे हैं, जो आरबीआई की वित्तीय स्थितियों और

आर्थिक स्थिरता बनाए रखने तथा मुद्रास्फीति के दबावों को प्रबंधित करने के लक्ष्य के साथ संरेखित हैं। नियमित ब्याज दर चक्रों के संपर्क ने भारतीय बैंकों को चक्रों को संभालने के लिए अच्छी तरह से तैयार किया है।

2.28 ऊपर वर्णित विश्लेषण के आधार पर, यह देखा गया है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली उच्च पूंजीगत पर्याप्तता अनुपात, बेहतर आस्ति गुणवत्ता और मजबूत आय वृद्धि द्वारा समर्थित, सुदृढ़ और लचीली बनी हुई है। एससीबी की लाभप्रदता में सुधार की प्रवृत्ति, जो वित्त वर्ष 2020 में शुरू हुई थी, वित्त वर्ष 2024 में लगातार पांचवें वर्ष जारी रही। इसमें उच्च आय और कम प्रावधान और आकस्मिकताओं से सहायता मिली है।

संकटग्रस्त परिसंपत्तियों से निपटना

2.29 बाजार में संकट को दूर करने की क्षमता अर्थव्यवस्था की मजबूती का एक माप है, और आर्थिक मंदी के दौर में ऐसा करने की क्षमता अर्थव्यवस्था के लचीलेपन का एक अनिवार्य संकेतक है। पिछले दशक में भारतीय वाणिज्यिक बैंकों को एनपीए के भारी बोझ के कारण संकट का सामना करना पड़ा। मार्च 2016 तक, सार्वजनिक क्षेत्र का जीएनपीए अनुपात 14.5 प्रतिशत था। इसका दूसरा पहलू बैंक ऋण का स्थिर होना था, जिसने कारपोरेट लाभ में वृद्धि को बढ़ावा दिया, जिससे दोहरी बैलेंस शीट समस्या पैदा हुई। सबसे अधिक दबाव उद्योग और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में था।

2.30 सरकार ने पिछले दशक में बैंकों और निगमों में दबाव को दूर करने पर पूरा ध्यान दिया है। बैंकिंग विनियामक ढांचे को मजबूत करने, वसूली कानूनों में संशोधन करने, व्यापक दिवाला और दिवालियापन कानून बनाने और सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी की स्थापना जैसे उपायों को लागू किया गया। इन उपायों ने ऋण क्षेत्र को फिर से स्वस्थ बनाया है और मार्च 2024 में जीएनपीए अनुपात घटकर 2.8 प्रतिशत रह गया है।

2.31 बाजार की ताकतों के प्रचालन और उसके बाद व्यापार/उद्यम विफलताओं के कारण बाजार में दबाव का उभरना एक सक्रिय और गतिशील अर्थव्यवस्था का संकेत है। चूँकि बैंक भारत में व्यवसायों के लिए वित्त का सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख स्रोत हैं, इसलिए बैंकों को संकटग्रस्त आस्तियों के प्रवाह से निपटने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है, और बाजारों को ऐसी संपत्तियों के पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार में निवेश करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है।

2.32 बैंकिंग विनियमन संकटग्रस्त आस्तियों की निगरानी और समय पर पहचान के लिए प्रावधान करते हैं, और आरबीआई ने अपने विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं। विनियमन ऋणों के पुनर्गठन और पुनर्निर्धारण के माध्यम से दबाव को उसके प्रारंभिक चरणों में समाधान करने के उपाय भी प्रदान करते हैं। इन विकल्पों की व्यापक रूपरेखा बैंकों के जोखिम प्रबंधन टूल किट का एक हिस्सा है। बैंकिंग विनियमन रक्षा की पहली पंक्ति और संकट का समाधान करने के उपाय हैं। आरबीआई उन्हें बाजार की जरूरतों और आर्थिक स्थितियों के जवाब में अपडेट करता है।

पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण के पारंपरिक चैनल

2.33 रिकवरी रूट अर्थात्, ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (एसएआरएफईएसआई) अधिनियम, 2002, दबाव को दूर करने के लिए उपलब्ध उपायों की दूसरी पंक्ति बनाते हैं। वित्त वर्ष 2023 के दौरान, एससीबी के जीएनपीए में लगभग 45 प्रतिशत की कमी वसूली और उन्नयन के कारण हुई।¹⁸

2.34 एसएआरएफईएसआई अधिनियम के तहत विनियमित आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (एआरसी)¹⁹ एफपीआई सहित निवेशकों के लिए बैंकों द्वारा धारित एनपीए/संकटग्रस्त आस्तियों तक पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक चैनल के रूप में उभर रही हैं। वित्त वर्ष 2023 के दौरान, 28 एआरसी बाजार²⁰ में परिचालन कर रही थीं। इस तरह का अधिग्रहण प्रतिभूति रसीदे (एसआर) जारी करके किया जाता है, और एआरसी को जारी किए गए एसआर का कम से कम 15 प्रतिशत या

18 भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर आरबीआई की रिपोर्ट वर्ष 2023, पृष्ठ 80, <https://shorturl.at/dOXt1>

19 एआरसीएस आरबीआई के साथ पंजीकृत संस्थाएँ हैं और उन्हें पुनर्निर्माण के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण, अग्रिमों, बांड, गारंटी और ऋण पत्र सहित वित्तीय आस्तियां प्राप्त करने की अनुमति है।

20 <https://tinyurl.com.56vmwnkv>

जारी किए गए कुल एसआर का 2.5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, लेने का अधिकार है। नियामक ढांचे ने एआरसी को कुछ शर्तों के अधीन आईबीसी प्रक्रिया के तहत समाधान आवेदकों के रूप में भाग लेने की अनुमति दी है। इसने आस्ति पुनर्निर्माण के दो बाजार चैनलों की सहक्रियाओं और पूरकताओं का दोहन करने की अनुमति दी है। वित्त वर्ष 2023 के दौरान, एससीबी के जीएनपीए के पिछले वर्ष के स्टॉक का 9.7 प्रतिशत एआरसी को बेचा गया, जबकि वित्त वर्ष 2022 में यह केवल 3.2 प्रतिशत था। वित्त वर्ष 2023 के दौरान अंततः भुनाए गए एसआर की संख्या में वृद्धि हुई, जो इस माध्यम से बढ़ी हुई वसूली का संकेत देता है।

2.35 एनपीए के लिए एक कुशल बाजार के लिए आवश्यक शर्तें हैं कि यह गहन, प्रतिस्पर्धी हो और इसमें पर्याप्त तरलता हो। बाजार में पर्याप्त निवेशक होने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एनपीए की कीमत संबंधी खोज कुशल हो। बैंकों से अधिग्रहण का समर्थन करने और आस्तियों के टर्न-अराउंड का समर्थन करने के लिए इसमें पर्याप्त तरलता होनी चाहिए। जीएनपीए को कम करने के लिए किए गए प्रत्यक्ष उपायों के अलावा, सरकार एक बैड बैंक की स्थापना और दिवालियेपन और दिवालियापन पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करके तरलता और प्रतिस्पर्धा में सुधार के लिए बाजार-आधारित पहलों के साथ बाजार में प्रणालीगत ताकत का निर्माण कर रही है।

2.36 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने संकटग्रस्त आस्तियों के बाजार में तरलता में सुधार के लिए कई उपाय लागू किए हैं। (एफपीआई) को समाधान के दौर से गुजर रही कंपनियों द्वारा जारी ऋण लिखतों और एआरसी द्वारा जारी एसआर में निवेश करने की अनुमति है। इन निवेशों के लिए एफपीआई पर कोई न्यूनतम निवेशक सीमा या अवशिष्ट परिपक्वता आवश्यकता नहीं लगाई गई है। इन उपायों से वित्त वर्ष 2022²¹ के दौरान एआरसी द्वारा जारी एसआर में एफपीआई निवेश लगभग ₹10,000 करोड़ से बढ़कर ₹14,482 करोड़ हो गया है। सेबी ने संकटग्रस्त आस्ति बाजार में भाग लेने के लिए वर्ष 2022 में एक विशेष मार्ग, विशेष स्थिति कोष, वैकल्पिक निवेश कोष का एक उप-घटक भी खोला। इसने इन निवेश साधनों को एआरसी द्वारा जारी एसआर में निवेश करने तथा कुछ शर्तों के अधीन आईबीसी प्रक्रिया के तहत समाधान आवेदक के रूप में कार्य करने की अनुमति दी। धन तक पहुंच बढ़ने से, बाजार सहभागियों द्वारा अधिक एनपीए/संकटग्रस्त आस्तियों में निवेश किए जाने की संभावना है, तथा बैंकों के लिए वसूली दर अधिक होने की उम्मीद है।

संकटग्रस्त आस्ति बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा

2.37 संकटग्रस्त आस्ति बाजार को और अधिक मजबूत करने के लिए, सरकार ने जुलाई 2021 में नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन राष्ट्रीय आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) और इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड (आईडीआरसीएल) की स्थापना की। एनएआरसीएल बैंकों से आस्तियों प्राप्त करती है, और सरकार इन आस्तियों के विरुद्ध जारी किए गए एसआर की गारंटी देती है। इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड (आईडीआरसीएल) के पास एनएआरसीएल द्वारा अधिग्रहित आस्तियों के समाधान के लिए एनएआरसीएल के साथ एक विशेष व्यवस्था है। आईडीआरसीएल को आस्ति के लिए उपयुक्त समाधान रणनीति की पहचान करने और इष्टतम समाधान परिणामों में एनएआरसीएल की सहायता करने का अधिकार है। एनएआरसीएल द्वारा अर्जित आस्तियां बैंक बैलेंस शीट को तुरंत क्लियर करती हैं, ताकि आगे उधार देने के लिए पूंजी मुक्त होती है।

2.38 एनएआरसीएल ने अब तक लगभग ₹92,000 करोड़²² के ऋण जोखिम वाले 18 खातों का अधिग्रहण किया है, जिसमें समाधान आवेदकों के रूप में रुग्ण एसआरआईआई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और एसआरआईआई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड का अधिग्रहण शामिल है। जबकि ₹1.25 लाख करोड़ की आस्तियों पर प्रस्ताव अधिग्रहण के विभिन्न चरणों में हैं, लगभग ₹40,000 करोड़ की आस्तियों के लिए सम्यक उद्यम और मूल्यांकन चल रहा है। संकटग्रस्त आस्तियों के एकीकरण और समाधान के लिए सरकार द्वारा समर्थित कंपनी की स्थापना से बाजार में तरलता और प्रतिस्पर्धा में और सुधार होगा।

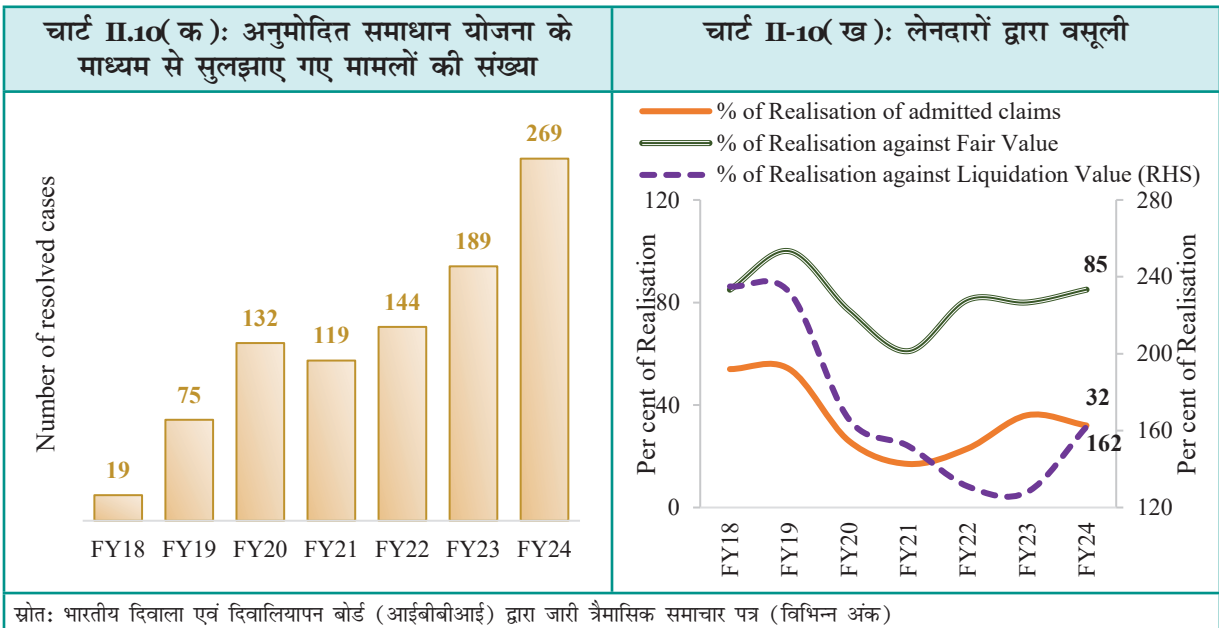
21 भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर आरबीआई की रिपोर्ट वर्ष 2021-2022, <https://shorturl.at/yx9n4>

22 वित्तीय सेवा विभाग के आंकड़े।

दिवालियापन समाधान के माध्यम से संकटग्रस्त आस्तियों का समाधान

2.39 आईबीसी को दोहरी बैलेंस शीट समस्या के लिए एक प्रभावी समाधान के रूप में मान्यता दी गई है, जहां बैंक एनपीए के दबाव में हैं, जबकि कारपोरेट अत्यधिक ऋणग्रस्त हैं और अपने ऋण को चुकाने में असमर्थ हैं। कोड समय रहते वित्तीय संकट को दूर करने का प्रावधान करता है। यह दिवालियापन पेशेवर को दिवालियापन प्रक्रिया का संचालन करने और संकटग्रस्त कारपोरेट क्षेत्र के प्रचालन के लिए अधिकृत करता है। साथ ही, लेनदारों की समिति प्रक्रिया और सभी महत्वपूर्ण निर्णयों को संचालित करती है, इस प्रकार प्रक्रिया के दौरान मूल्य के और अधिक क्षरण को कम करती है। डिजाइन और संचालन के द्वारा, कोड सभी हितधारकों की आवश्यकताओं को संतुलित करता है। आईबीसी ने कॉर्पोरेट देनदारों को अपने ऋण का समाधान करने और असफल व्यावसायिक प्रयासों से सम्मानजनक तरीके से बाहर निकलने का एक रास्ता प्रदान किया है, इस प्रकार व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा दिया है और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया है। कोड ने जीएनपीए को महत्वपूर्ण रूप से कम करके और असफल कारपोरेट देनदारों को बचाने में मदद करके बैंकों के दबाव को दूर करने के लिए एक प्रभावी सहायता से समाधान के रूप में खुद को स्थापित किया है। इसने वित्तीय बाजारों के रिकवरी सेगमेंट और रियल सेक्टर में विफल/संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण को नई गति प्रदान की है। 2016 से अब तक के आठ वर्षों में, मार्च 2024 तक ₹13.9 लाख करोड़ मूल्य के 31,394 कारपोरेट देनदारों का निपटारा किया जा चुका है (प्रवेश-पूर्व मामले निपटारा सहित)। समाधान प्रक्रिया में प्रवेश के तुरंत बाद नियंत्रण खोने के कारण देनदारों ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) में आवेदन दाखिल करते ही लेनदारों के साथ समझौता कर लिया है। एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि ₹10.2 लाख करोड़ के अंतर्निहित डिफॉल्ट का प्रवेश-पूर्व चरण²³ में ही समाधान किया गया था। देनदार व्यवहार में यह बदलाव बैंकों और अन्य ऋण देने वाली संस्थाओं के लिए एक बड़ा वरदान रहा है। संहिता ने लेनदार-देनदार संबंधों में स्पष्ट और पारदर्शी व्यवहार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक इष्टतम प्रोत्साहन-निराशाजनक मिश्रण बनाया है।

आईबीसी के अंतर्गत निपटाए गए मामलों और ऋणदाताओं द्वारा वसूली में उल्लेखनीय प्रगति



2.40 संहिता संकटग्रस्त परिसंपत्ति का समाधान करने के सर्वोत्तम साधनों की पहचान करने के लिए कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रियाओं (सीआईआरपीएस) का उपयोग करती है। इसने मार्च 2024 तक 4,131 सीआरपीएस को सफलतापूर्वक बंद करने में मदद की है। 3,171 कॉर्पोरेट देनदारों को बचाया गया है, जिनमें से 947 मामलों को अनुमोदित

23 स्रोत: आईबीबीआई न्यूजलेटर, जनवरी-मार्च 2024

<https://ibbi.gov.in/uploads/publication/21aa7620a9e809f7a20b432eec89888b.pdf>

समाधान योजनाओं के माध्यम से हल किया गया है, जिससे ₹3.36 लाख करोड़ का वसूली योग्य मूल्य प्राप्त हुआ है। हल किए गए मामलों में, लेनदारों ने अपने दावों का लगभग 32 प्रतिशत वसूल किया। यह उचित मूल्य का 85 प्रतिशत और परिसंपत्तियों के परिसमापन मूल्य का 162 प्रतिशत वसूल हुआ।

2.41 वित्तीय बाजारों की सामान्य स्थिति पर आईबीसी का प्रभाव स्पष्ट है क्योंकि यह आज एससीबी के लिए प्रमुख वसूली माग²⁴ है। भारत में बैंकिंग के रुझान और प्रगति पर आबीआई की रिपोर्ट, वर्ष 2022-23 के अनुसार, आईबीसी ने वित्त वर्ष 2023 में एससीबी द्वारा वसूल की गई कुल राशि का 43 प्रतिशत हिस्सा धारित किया। वित्त वर्ष 2018 के बाद से छह वर्षों में, आईबीसी ने एससीबीएस के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वसूली को सक्षम बनाया है, जो कि लोक अदालतों, डीआरटी और एसएआरएफआईएसआई अधिनियम के माध्यम से वसूल की गई राशि से अधिक है।

2.42 रियल सेक्टर के लिए अधिक महत्वपूर्ण यह है कि 3,000 से अधिक व्यवसाय सीआईआरपी से विकसित हुए हैं, निरंतर व्यावसायिक संचालन से इन कॉर्पोरेट देनदारों में वित्तीय संकट के कारण फंसे संसाधनों का उत्पादक उपयोग बढ़ रहा है। भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद द्वारा किए गए एक अध्ययन²⁵ में बताया गया है कि संहिता के तहत समाधान प्रक्रिया से गुजरने वाली समाधित (रिजाल्ड) फर्मों ने समाधान-पूर्व अवधि की तुलना में समाधान-पश्चात अवधि में मूर्त आस्तियों और औसत पूंजीगत व्यय में वृद्धि के संदर्भ में अपने प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार देखा है, समाधान-पूर्व चरण में समाधित फर्मों का कुल बाजार मूल्यांकन लगभग 2 लाख करोड़ से बढ़कर समाधान-पश्चात चरण में ₹6 लाख करोड़ हो गया। समाधान के बाद के तीन वर्षों में समाधानित फर्मों (सूचीबद्ध) में कुल रोजगार में पर्याप्त वृद्धि हुई है और औसत कर्मचारी खर्च में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि है।

2.43 मार्च 2024 तक, परिसमापन में समाप्त होने वाले कुल सीआईआरपीएस 2,476 थे। इन कॉर्पोरेट देनदारों में से लगभग 77 प्रतिशत प्रक्रिया की शुरुआत में निष्क्रिय थे और औसतन, उनका मूल्य बकाया ऋण का 7 प्रतिशत था। परिसमापन प्रक्रिया, सुनाम प्रतिष्ठान की बिक्री/समझौता/व्यवस्था के माध्यम से परिसंपत्ति के पुनरुद्धार के लिए अवसर की अंतिम विंडो प्रदान करती है ताकि बचाए गए मूल्य को अधिकतम किया जा सके। इस अंतिम उपाय से लगभग 50 व्यवसायों को बचाया गया है। परिसमापन प्रक्रिया के अंत में 586 फर्मों को भंग कर दिया गया, जिससे वैकल्पिक उपयोगों के लिए जो भी संसाधन आवश्यक थे, उन्हें जारी कर दिया गया।

2.44 आईबीसी के तहत समाधान के लिए आरबीआई द्वारा संदर्भित बारह बड़े खातों²⁶ में से नौ का समाधान किया गया है। इन कॉर्पोरेट देनदारों के लिए समाधान योजनाओं ने स्वीकार किए गए दावों का 54 प्रतिशत प्राप्त किया। इन देनदारों में इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड, भूषण स्टील लिमिटेड, मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड, एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड, भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड आदि जैसी स्टील और बिजली की बड़ी कंपनियाँ शामिल थीं, और उनके समाधानों ने स्टील क्षेत्र के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आईबीसी की धारा 227 के तहत रूपरेखा वित्तीय सेवा प्रदाताओं के समाधान के लिए प्रावधान करती है, और वर्तमान में, 500 करोड़ या उससे अधिक की संपत्ति वाले आवास वित्त कंपनियों सहित एनबीएफसी को कवर किया जाता है। इस रूपरेखा के तहत दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड और श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड के समाधान को संभव किया है। प्रत्येक मामले में, लेनदारों ने लगभग 42 प्रतिशत दावों की वसूली की है। बॉक्स-II.2 रियल एस्टेट कंपनियों के वित्तीय दबाव के समाधान हेतु आईबीसी प्रक्रिया की भूमिका पर चर्चा करता है।

24 यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संहिता का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य तनावग्रस्त कॉर्पोरेट देनदारों का समाधान करना है। दावों की वसूली समाधान की प्रक्रिया का एक हिस्सा मात्र है।

25 आईआईएम अहमदाबाद की रिपोर्ट, 'समाधान प्रक्रिया की प्रभावशीलता: आईबीसी के बाद के परिणामों से', <https://ibb.gov.in/uploads/resources/59f737b213b4700cc16428aefd62869a.pdf>

26 आईबीसी के तहत समाधान के लिए आरबीआई द्वारा संदर्भित कारपोरेट ऋण प्राप्तकर्ताओं का पहला सेट।

बॉक्स II.2: ठप्प पड़ी रियल एस्टेट परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने और घर खरीदारों के अधिकारों को मजबूत करने में आईबीसी की भूमिका

वर्ष 2016 से पहले, घर खरीदने वालों के लिए एकमात्र उपाय, जिनकी आवासीय परियोजनाएं विभिन्न कारणों से रुकी हुई थीं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित उपभोक्ता फोरम के माध्यम से उपलब्ध था। वित्त वर्ष 24 में, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में 5,50²⁷ से अधिक मामले दर्ज किए गए, और लगभग 21 प्रतिशत आवास क्षेत्र से संबंधित थे। हालांकि, उपभोक्ता निवारण मार्ग के माध्यम से हल किए गए मामलों की संख्या न्यूनतम रही है। यह अनुमान लगाया गया था कि 4.1 लाख करोड़ रुपये की रियल एस्टेट परियोजनाओं में 4.1 लाख आवासीय इकाइयाँ संकट²⁸ में थीं।

वर्ष 2016 में रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 (रेरा अधिनियम) का अधिनियमन हुआ। इसने पीड़ित घर खरीदारों को एक समर्पित शिकायत निवारण तंत्र और चूककर्ता रियल एस्टेट ठेकेदारों और कंपनियों पर लगाम लगाने का एक साधन प्रदान किया। उसी वर्ष आईबीसी के बाद के अधिनियमन ने एक और चौनल खोला और तीन उपलब्ध उपायों में से यह सबसे पसंदीदा रहा है। मार्च 2024 तक, 1500 से अधिक रियल एस्टेट कंपनियों को आईबीसी के तहत दिवालियेपन समाधान प्रक्रिया में भर्ती कराया गया था, जो कुल प्रवेश का 21 प्रतिशत था। प्रवेश के बाद निपटाए गए चार मामलों में से एक भी इसी क्षेत्र से था। हल किए गए 891 कॉर्पोरेट देनदारों में से 133 रियल एस्टेट कंपनियाँ थीं, जो हल की गई कंपनियों का 15 प्रतिशत था।

रियल एस्टेट कंपनियों के दिवालियेपन समाधान ने मानकीकृत कॉर्पोरेट दिवालियेपन प्रक्रिया के लिए चुनौतियों का एक अनूठा समूह पेश किया। रियल एस्टेट कंपनियों के पास भौगोलिक क्षेत्रों में फैली कई परियोजनाएँ, निर्माण के विभिन्न चरणों में परियोजनाएँ और विविध व्यवसाय मॉडल हैं। इन परियोजनाओं में घर खरीदने वालों की बड़ी संख्या का मतलब था कि हजारों घर खरीदने वालों के दावे जिन्हें इस प्रक्रिया में शामिल करने की आवश्यकता थी। न्यायपालिका, सरकार और बाजार ने इन कठिनाइयों को पहचाना है और इन परियोजनाओं के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एकजुट कदम उठाए हैं। दो नए उपचारात्मक मार्गों की उपलब्धता ने प्रणाली में कलह और टकराव को जन्म दिया।

दिवाला कानून समिति ने अपनी मार्च 2018²⁹ की रिपोर्ट में रियल एस्टेट क्षेत्र की खासियत का संज्ञान लिया। इसने सुझाव दिया कि घर खरीदने वालों से जुटाई गई राशि को वित्तीय ऋण माना जाना चाहिए क्योंकि यह जुटाई गई राशि में महत्वपूर्ण योगदान देता है और उधार लेने का वाणिज्यिक प्रभाव होता है। इसने घर खरीदने वालों को लेनदारों के एक प्रतिष्ठित वर्ग और लेनदारों की समिति का हिस्सा बनाकर सीआईआरपी में महत्वपूर्ण बदलाव किए, जिससे उन्हें निर्णय लेने में प्रत्यक्ष भागीदारी करने में सक्षम बनाया गया। हजारों घर खरीदने वालों के बहुमत के मतदान के माध्यम से निर्णय लेने और प्राप्त करने की एक प्रणाली भी तैयार की गई, ताकि अधिकृत प्रतिनिधियों के रूप में दिवाला पेशेवरों को पेश किया जा सके। आगे के संशोधनों ने एक ही परियोजना के तहत कम से कम 100 आवंटियों या कुल आवंटियों की संख्या के कम से कम 10 प्रतिशत के संयुक्त आवेदन द्वारा दिवाला शुरू करने में सक्षम बनाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि झूठे आवेदन दायर नहीं किए जाते हैं। चूंकि घर खरीदने वालों के लिए एक उपाय के रूप में आईबीसी के उपयोग पर स्पष्टता सामने आई है, इसलिए यह भी निर्धारित किया गया कि रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए अनुमोदित समाधान योजनाएं अनिवार्य रूप से आरईआरए अधिनियम के अनुरूप होनी चाहिए, जिससे क्षेत्र की इष्टतम निगरानी के लिए अपने क्षेत्र में क्षेत्रीय कानून और क्षेत्रीय नियामक को प्राथमिकता मिल सके।

27 <https://cms.nic.in/ncdrcusersWeb/dashboard.do?method=loadDashBoardPub> पर सीओएनएफओएनईटी डैशबोर्ड, जैसा कि 21 मई 2024 को दर्शाया गया है

28 मॉडल बिल्डिंग बाय लॉज 2016 नगर एवं देश नियोजन संगठन, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, [https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/report\(1\).pdf](https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/report(1).pdf)

29 कारपोरेट कार्य मंत्रालय की मार्च 2018 की, दिवाला कानून समिति की रिपोर्ट। https://ibbi.gov.in/uploads/resources/ILRReport2603_03042018.pdf

आर्थिक कानून में नवाचार के माध्यम से, न्यायपालिका ने रियल एस्टेट कॉरपोरेट देनदारों के समाधान में समाधान का मार्ग प्रशस्त किया। लेनदारों के एक वर्ग के रूप में, इसने घर खरीदारों को समाधान आवेदक के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाया। इसने रिवर्स सीआईआरपीए नामक एक प्रक्रिया को मंजूरी दी, जहाँ कॉरपोरेट देनदार समाधान प्रक्रिया के दौरान भी परियोजना को पूरा करने के लिए उपाय कर सकता था। न्यायपालिका ने परियोजना-विशिष्ट समाधान योजनाओं की अनुमति दी है, जो एक ही कॉरपोरेट देनदार के तहत प्रभावित परियोजना को लक्षित करती है। इस उपाय ने कॉरपोरेट देनदारों और विभिन्न परियोजनाओं के आवंटियों को राहत दी, और बाजार ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है।

कई रियल एस्टेट कंपनियों ने ठप्प पड़ी हुई परियोजनाओं का सफलतापूर्वक हल निकालकर उन्हें आगे बढ़ाने हेतु सक्षम बनाया है। वेल्यू इंफ्राकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, समाधान प्रक्रिया ने लेनदारों को दावा मूल्य का 98 प्रतिशत और परिसंपत्ति के परिसमापन मूल्य का 189 प्रतिशत प्रदान किया।

आशियाना लैंडक्राफ्ट रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड और अनुदान प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के मामलों में, समाधानों ने परिसंपत्तियों के परिसमापन मूल्य का लगभग 2.5 गुना प्राप्त किया। जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड जैसे सेक्टर के बड़े कॉरपोरेट देनदारों का समाधान लेनदारों के लिए 88 प्रतिशत की वसूली के साथ किया गया है, और परिसंपत्तियों को परिसमापन मूल्य के 114 प्रतिशत³⁰ से अधिक पर अधिग्रहित किया गया है।

आईबीसी के तहत समाधान की गति बढ़ने के बावजूद, इन संकटग्रस्त परियोजनाओं में निवेश को चैनल/रीडायरेक्ट करने की आवश्यकता बनी हुई है। इस महत्वपूर्ण अंतर को दूर करने के लिए, सरकार ने 2019 में ₹12,500 करोड़ के लक्ष्य कोष के साथ किफायती और मध्यम आय आवास के लिए विशेष विंडो (एसडब्ल्यूएमआईएच) की स्थापना की। यह एक पेशेवर रूप से प्रबंधित वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) है जिसका उद्देश्य कॉरपोरेट देनदारों और संहिता के तहत समाधान प्रक्रिया से गुजरने वाली परियोजनाओं सहित ठप्प पड़ी आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता ऋण वित्तपोषण प्रदान करना है। अप्रैल 2024 तक, एसडब्ल्यूएमआईएच फंड ने 32,000 से अधिक घर वितरित किए हैं और अगले तीन वर्षों के लिए हर साल 20,000 घरों की डिलीवरी का लक्ष्य रखा जा रहा है।

आईबीसी के तहत मामलों के निर्बाध समाधान और प्रगति तथा एआईएफ के माध्यम से तरलता में सुधार का प्रभाव बैंकों के अच्छे तुलन पत्र में परिलक्षित होता है, जिससे उनकी आगे और अधिक उधार देने की क्षमता बढ़ जाती है।

2.45 सरकार ने दिवालियापन पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। इसने बुनियादी ढांचे के संबंध में एनसीएलटी को मजबूत किया है, रिक्तियों को भरकर और एक एकीकृत आईटी प्लेटफॉर्म का प्रस्ताव देकर इसकी ताकत बढ़ाई है। बाजारों की जरूरतों और न्यायिक घोषणाओं में प्रगति के अनुरूप नियमों में संशोधन किया गया है। आईबीसी ने खुद को आस्ति परिसंपत्ति वसूली और पुनर्निर्माण बाजार के एक अपरिहार्य घटक के रूप में स्थापित किया है। इस प्रक्रिया में, इसने देश में ऋण बाजार परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया है।

वित्तीय समावेशन पहुंच के भीतर है; डिजिटल वित्तीय समावेशन अगला लक्ष्य है

2.46 वित्तीय समावेशन सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि सतत आर्थिक विकास, असमानता में कमी और गरीबी उन्मूलन के लिए एक साधन भी है। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने वित्तीय समावेशन को 2030 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में अन्य विकास लक्ष्यों के एक प्रमुख प्रवर्तक के रूप में स्थान दिया है। शैक्षणिक साक्ष्य बताते हैं कि वित्तीय समावेशन समग्र आर्थिक विकास को बढ़ा सकता है और विभिन्न एसडीजी की उपलब्धि को सुगम बना सकता है।

2.47 सरकार ने अंतिम छोर तक वित्तीय सेवाएँ पहुँचाने को प्राथमिकता दी है। 2008 में वित्तीय समावेशन और औपचारिक पहचान के निम्न स्तर को देखते हुए, एक दशक से थोड़ा पहले भारत के सामने चुनौतियों की मात्रा बहुत बड़ी थी। विश्व बैंक के वैश्विक वित्तीय समावेशन डेटाबेस के अनुसार, भारत ने पिछले दस वर्षों में अपने वित्तीय समावेशन लक्ष्यों में उल्लेखनीय प्रगति की है। औपचारिक वित्तीय संस्थान में खाता रखने वाले वयस्कों की संख्या 2011 में 35 प्रतिशत से बढ़कर 2021 में 77 प्रतिशत हो गई। वित्तीय संस्थान में बचत करने वाले और औपचारिक स्रोतों से उधार

30 आईबीबीआई द्वारा जारी परिणामों में दर्शाए गए आंकड़ों के अनुसार, (<https://ibbi.gov.in/en/claims/cd-summary>)

लेने वाले वयस्कों के प्रतिशत में वृद्धि हुई है। अमीर और गरीब के बीच उपलब्धता के अंतर में कमी आई है। इसके अलावा, वित्तीय समावेशन के मामले में लैंगिक विभाजन भी कम हुआ है। जबकि वित्तीय समावेशन में लैंगिक आधार पर प्रगति हुई है, यह भी स्पष्ट है कि भारत के युवाओं को भी वही लाभ मिल रहे हैं (तालिका II.2)। दक्षिण एशियाई और विश्व औसत की तुलना में, भारत का प्रदर्शन विशिष्ट संकेतकों में बेहतर है (तालिका II.3)।

2.48 बैंक खाते के आंकड़ों और प्रति व्यक्ति जीडीपी के साथ संबंध के आधार पर, एक मोटा अनुमान यह है कि अगर भारत पूरी तरह से पारंपरिक विकास प्रक्रियाओं³¹ पर निर्भर होता, तो 80 प्रतिशत वयस्कों के पास बैंक खाता होने में 47 साल लग जाते।

तालिका II.2: वित्तीय समावेशन और वित्तीय शिक्षा के संकेतकों में भारत का प्रदर्शन			
क्र.सं.	वित्तीय समावेशन के संकेतक	2011	2021
1.	औपचारिक वित्तीय संस्थान में खाता रखने वाले वयस्क (% , आयु 15+)	35	77
2.	डिजिटल भुगतान किया या प्राप्त किया (% आयु 15+)	22'	35
3.	औपचारिक वित्तीय संस्थान से उधार लिया, अधिक उम्र वाले (% आयु 15+)	8	12
4.	खाता, सबसे गरीब 40% (% आयु 15+)	27	78
5.	खाता, सबसे अमीर 60% (% आयु 15+)	41	77
6.	खाता, महिला (% आयु 15+)	26	78
7.	खाता, पुरुष (% आयु 15+)	44	78
8.	युवा (आयु 15-24 वर्ष) जिन्होंने डिजिटल भुगतान किया या प्राप्त किया	19'	30

स्रोत: विश्व बैंक का वैश्विक वित्तीय समावेशन डेटाबेस

नोट: 'डेटा 2014 का है, क्योंकि 2011 का डेटा उपलब्ध नहीं है

तालिका II.3: वित्तीय समावेशन और वित्तीय शिक्षा पैरामीट्रो की क्रॉस-कट्टी तुलना			
	औपचारिक वित्तीय संस्थान में खाता रखने वाले वयस्क (% , आयु 15+)	वित्तीय संस्थान में बचत करने वाले वयस्क (25+ आयु वर्ग के %)	औपचारिक वित्तीय संस्थान से उधार लिया गया, अधिक आयु (25 वर्ष से अधिक आयु का%)
विश्व	76	29	32
दक्षिण एशिया	68	11	12
ब्राजील	84	23	42
चीन	89	45	42
भारत	78	13	13
इंडोनेशिया	52	20	15
दक्षिण अफ्रीका	85	37	20

स्रोत: विश्व बैंक का वैश्विक वित्तीय समावेशन डेटाबेस, 2021 का डेटा (नवीनतम उपलब्ध)

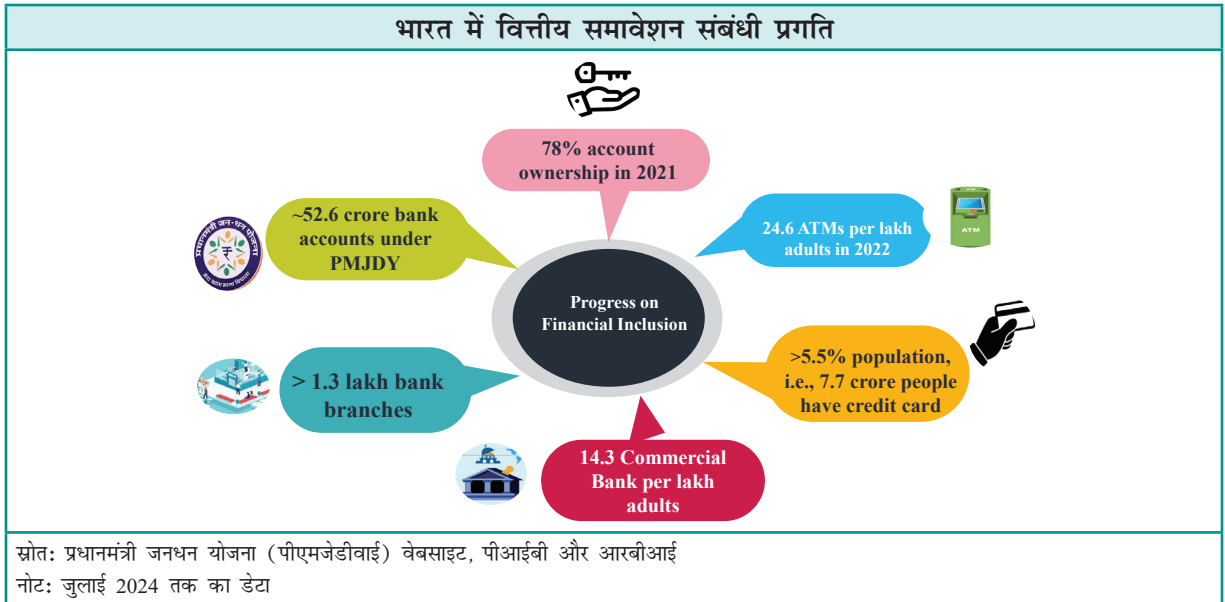
2.49 हाल ही में, देश में वित्तीय समावेशन रणनीति का फोकस 'हर घर' से 'हर वयस्क' की ओर स्थानांतरित हुआ है, जिसमें इन खातों के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रवाह को बढ़ाकर खातों के उपयोग पर अतिरिक्त जोर दिया गया है, रूपे कार्ड, यूपीआई आदि का उपयोग करके डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया गया है। आईबीआई ने मार्च 2022 में फीचर फोन के लिए यूपीआई भुगतान करने के विकल्प के रूप में यूपीआई 123 पे लॉन्च किया, और नेशनल

31 बीआईएस पेपर संख्या 106: डिजिटल वित्तीय अवसंरचना का डिजाइन: भारत से सबक, डेरिल डी'सिल्वा, जुजाना फिल्कोवा, फ्रैंक पैकर और सिद्धार्थ तिवारी द्वारा, मौद्रिक और आर्थिक विभाग, दिसंबर 2019, (<https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap106.pdf>)

पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने यूपीआई लाइट पेश किया, जो चुनिंदा बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली ऑन-डिवाइस वॉलेट सेवा है जो बीएचआईएम ऐप के माध्यम से 200 तक के कम मूल्य के लेनदेन की अनुमति देती है। ये नवाचार भारत में डिजिटल अपनाने की प्रक्रिया को तेज करने की दिशा में कदम हैं, जो एक अधिक समृद्ध और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर आबादी के बड़े हिस्से को समायोजित कर सकते हैं। भारत राष्ट्रीय और सीमा पार भुगतान प्रणालियों में अधिक दक्षता लाने के लिए कई देशों के साथ सहयोग भी कर रहा है।

2.50 आरबीआई भारत के फास्ट पेमेंट्स सिस्टम (एफपीएस), अर्थात् यूपीआई को सीमा पार व्यक्ति से व्यक्ति (पी 2 पी) और व्यक्ति से व्यापारी (पी 2 एम) भुगतान के लिए अपने संबंधित एफपीएस के साथ जोड़ने के लिए विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग कर रहा है। आरबीआई ने प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल किया है, जो घरेलू एफपीएस को जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम करने के लिए एक बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय पहल है। नेक्सस का उद्देश्य चार एशियन देशों (मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड) और भारत के एफपीएस को जोड़ना है, जो इस मंच के संस्थापक सदस्य और पहले प्रस्तावक देश होंगे। इस आशय के एक समझौते पर 30 जून 2024³² को बीआईएस और संस्थापक देशों के केंद्रीय बैंकों ने हस्ताक्षर किए हैं। इस प्लेटफॉर्म के 2026 तक लाइव होने की उम्मीद है। एक बार कार्यात्मक होने के बाद, नेक्सस से सीमा पार खुदरा भुगतान को कुशल, तेज और अधिक लागत प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।

2.51 वित्तीय समावेशन के लिए आरबीआई की रणनीति के मुख्य घटक लक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण, बाजार विकास, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, नवाचार और प्रौद्योगिकी, अंतिम-मील वितरण, उपभोक्ता संरक्षण और वित्तीय साक्षरता और जागरूकता³³ रहे हैं। इस रणनीति के अनुसरण में, वित्तीय समावेशन पर अब तक की प्रगति नीचे प्रस्तुत की गई है:



डिजिटल वित्तीय समावेशन

2.52 वित्तीय समावेशन अभियान का एक प्रमुख प्रवर्तक वित्तीय प्रणाली का डिजिटलीकरण रहा है, जिसने दुनिया भर में वित्तीय सेवाओं के परिदृश्य के परिवर्तन को उत्प्रेरित किया है। अब जब वित्तीय सेवाएँ डिजिटल उपकरणों पर आसानी से उपलब्ध हैं, तो अगली बड़ी चुनौती 'डिजिटल वित्तीय समावेशन (डीएफआई)' सुनिश्चित करना है। डीएफआई में

32 दिनांक 1 जुलाई, 2024 को जारी बीआईएस प्रेस विज्ञापित, प्रोजेक्ट नेक्सस घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों को विश्व स्तर पर जोड़ने के लिए व्यापक खाका पूरा करना है और लाइव कार्यान्वयन की दिशा में काम करने की तैयारी करना।

<https://www.bis.org/press/p240701.htm>

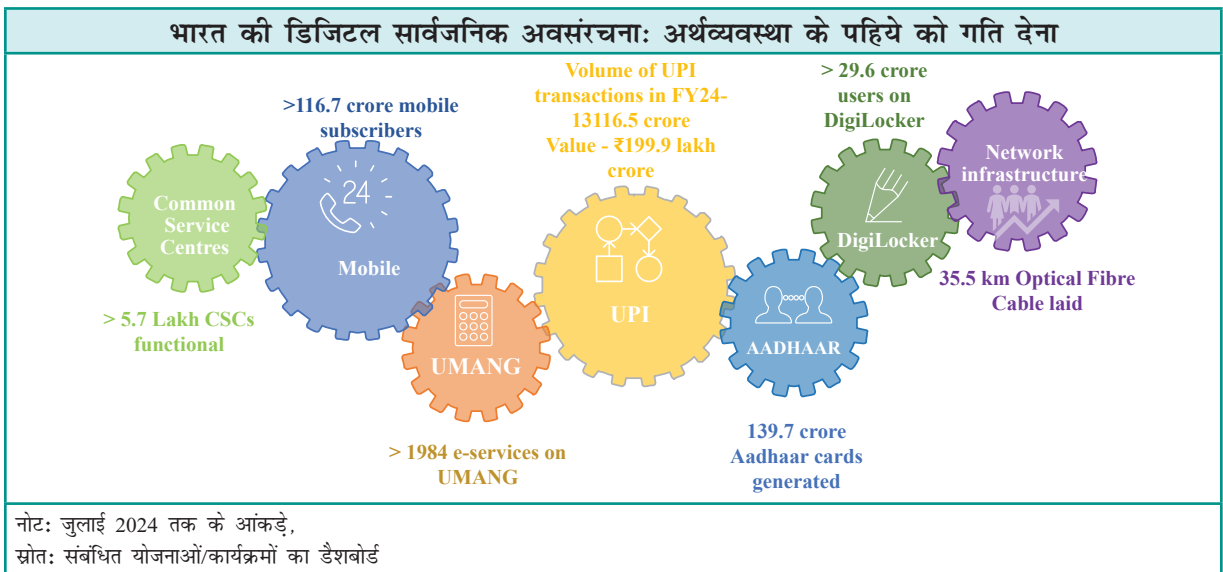
33 आरबीआई ने वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2019-2024 शुरू की, जिसका उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र में सभी हितधारकों को शामिल करते हुए कार्यों के व्यापक अभिसरण के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय समावेशन प्रक्रिया का विस्तार और उसे बनाए रखने में मदद करना है। इस रणनीति का उद्देश्य औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक सस्ती पहुँच प्रदान करना, वित्तीय समावेशन को व्यापक और गहरा बनाना तथा वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देना है।

वर्तमान में वित्तीय रूप से वंचित और अल्पसेवित नागरिकों तक उनकी जरूरतों के अनुरूप औपचारिक वित्तीय सेवाओं की एक श्रृंखला पहुँचाने के लिए लागत प्रभावी डिजिटल साधनों की व्यवस्था करना शामिल है। डीएफआई के आवश्यक घटकों में ग्राहकों को भुगतान करने या प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए डिजिटल लेनदेन प्लेटफॉर्म की उपलब्धता और उपकरण इस प्रकार के ट्रांजेक्शन करने के लिए शामिल हैं। इन खुदरा एजेंटों के पास डिजिटल डिवाइस और डिजिटल लेनदेन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अतिरिक्त वित्तीय सेवाएँ हैं।

2.53 जबकि भारत में वित्तीय सेवाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में कदम उठाए जा रहे थे, कोविड-19 महामारी ने इस प्रक्रिया को और गति दी, जब सबसे कमजोर और वंचित नागरिक गंभीर रूप से प्रभावित हुए। तदनुसार, सरकार ने नवाचार को प्रोत्साहित किया और एक अच्छी तरह से तैयार डिजिटल बुनियादी ढाँचा और प्रौद्योगिकी-आधारित प्रणाली विकसित की। यह एक समावेशी, लागत-कुशल और जिम्मेदार डीपीआई के रूप में विकसित हुआ है।

2.54 भारत को एक फिनटेक राष्ट्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से, सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन, मेक-इन-इंडिया आदि जैसी कई प्रमुख योजनाएँ शुरू की हैं। डीपीआई के निर्माण पर अधिक जोर दिया गया है जैसे आधार, ई-केवाईसी, आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली, यूपीआई, भारत क्यूआर, डिजीलॉकर, ई-साइन, अकाउंट एग्रीगेटर, डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क आदि। इन डीपीआई का उपयोग विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा साझा आधार पर किया जा सकता है ताकि इष्टतम परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें। इससे पारदर्शिता, बड़े पैमाने पर संचालन और जनता को वित्तीय सेवाओं की समय पर डिलीवरी हुई है।

2.55 भारत के मजबूत डीपीआई ने देश के डिजिटल परिवर्तन को सक्षम करने, नागरिक-केंद्रित और पारदर्शी शासन सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत की तेजी से बढ़ती आबादी, विश्व स्तरीय डीपीआई और सक्रिय विनियमन ने फिनटेक उद्योग के विकास को आधार प्रदान किया है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते फिनटेक बाजारों में से एक है, जिसे तीसरी सबसे बड़ी बढ़ती फिनटेक अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है।



2.56 डीएफआई में प्रगति ने औपचारिक और विशाल अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में लाखों लोगों को भुगतान स्वीकार करने, चालान का निपटान करने और देश में कहीं भी कुछ स्क्रीन टैप के साथ धन हस्तांतरित करने में सक्षम बनाया है। ये प्रगति इंडिया स्टैक, एक व्यापक डिजिटल पहचान, भुगतान और डेटा-प्रबंधन प्रणाली पर आधारित है। इंडिया स्टैक में तीन परस्पर जुड़ी परतें हैं जो हर भारतीय को आसान, लागत-मुक्त, मोबाइल-प्रथम डिजिटल लेनदेन की सुविधा प्रदान करते हुए एक डिजिटल पहचान प्रदान करती हैं। इंडिया स्टैक के³⁴ तीन महत्वपूर्ण घटक पहचान स्तर, भुगतान स्तर और डेटा शासन स्तर हैं। पहचान स्तर के संबंध में, आधार भारत के प्रमाणीकरण पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने में सहायक रहा

34 विश्व बैंक का ब्लॉग, 'भारत का डिजिटल परिवर्तन आर्थिक विकास के लिए गेम-चेंजर हो सकता है', दिनांक 2डीएफ10 जून 2023, <https://shorturl.at/Z2rL9>

है। इसने केवाईसी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया है, ई-केवाईसी करने की लागत को 12 अमेरिकी डॉलर से घटाकर 6 सेंट कर दिया है जिससे करोड़ों भारतीयों तक बैंकिंग सुविधा का विस्तार हुआ और वित्तीय समावेशन में सुधार हुआ है। भुगतान के स्तरों में, यूपीआई ने देश की भुगतान प्रणाली में क्रांति ला दी है। 31 मार्च 2024³⁵ तक 116.5 करोड़ से अधिक स्मार्टफोन ग्राहकों के साथ भारत में स्मार्टफोन के उपयोग के विस्तार से यूपीआई की सफलता में वृद्धि हुई है। यूपीआई प्लेटफॉर्म पर किए गए लेन-देन का मूल्य वर्ष 17 में ₹0.07 लाख करोड़ से कई गुना बढ़कर वर्ष 2024³⁶ में ₹200 लाख करोड़ हो गया है। डेटा गवर्नेंस स्तर उपयोगकर्ता डेटा पर स्वामित्व और नियंत्रण को उसके सही स्वामियों तक सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।

2.57 डिजिटल ऋण व्यक्तियों और फर्मों को आर्थिक अवसरों को विकसित करने के लिए सशक्त बनाकर सतत और समावेशी विकास के लिए एक शक्तिशाली एजेंट हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के शोध के अनुसार, भुगतान के डिजिटल वित्तीय समावेशन में वृद्धि से औसत आर्थिक विकास में 2.2 प्रतिशत की वृद्धि होती है, जो संभवतः उपभोग चैनल और उच्च औपचारिकता³⁷ के माध्यम से संचालित होती है।

माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं: वित्तीय समावेशन को सुगम बनाना

‘औपचारिक वित्त तक पहुँच से रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल सकता है, आर्थिक उतार-चढ़ाव के प्रति अरक्षितता कम हो सकती है और मानव पूंजी में निवेश बढ़ सकता है। वित्तीय सेवाओं तक पर्याप्त पहुँच के साथ, व्यक्ति और फर्म अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने और विकास के अवसरों का लाभ उठाने के लिए वित्त के महंगे अनौपचारिक स्रोतों पर भरोसा कर सकते हैं। व्यापक स्तर पर, अधिक वित्तीय समावेशन से सभी के लिए सतत और समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास का हेतु सहायता मिल सकती है।’

- वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2019-24, आरबीआई

2.58 माइक्रोफाइनेंस का तात्पर्य उन परिवारों, छोटे व्यवसायों और उद्यमियों को छोटे-मूल्य के ऋण सहित वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना है, जिनकी औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच नहीं है। यह वित्तीय समावेशन के लिए एक प्रभावी साधन है, जिसमें गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों को सामाजिक समानता और सशक्तीकरण प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए माइक्रोफाइनेंस और संबंधित सेवाएँ स्थायी रूप से प्रदान करना शामिल है। माइक्रोफाइनेंस किफायती डोरस्टेप सेवाएँ प्रदान करके कम आय वाले परिवारों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में एक आवश्यक भूमिका निभा रहा है। उन्होंने बीमा, धन प्रेषण, वित्तीय साक्षरता आदि जैसी अन्य वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने में भी भूमिका निभाई है। माइक्रोफाइनेंस वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक के रूप में उभरा है।

2.59 भारत में एमएफआई क्षेत्र के विकास को आरबीआई के सहायक नियामक ढाँचे के साथ-साथ स्व-नियामक संगठनों (एसआरओ) द्वारा उद्योग आचार संहिता के निर्माण से काफी सुविधा हुई है। क्षेत्र में बदलती गतिशीलता ने सा-धन³⁸ द्वारा उत्तरदायी उधार के लिए संहिता के विकास को भी आवश्यक बना दिया है, जो माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में काम करने वाले सभी उधारदाताओं के लिए एक स्वैच्छिक संहिता है। सा-धन के साथ, एमएफआईएन³⁹ यह एमएफआई क्षेत्र के लिए एक एसआरओ है जो माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र के विकास की दिशा में काम करता है। 14 मार्च 2022 को माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र के लिए आरबीआई द्वारा जारी माइक्रोफाइनेंस ऋणों के लिए नया नियामक ढाँचा यह सुनिश्चित करता है कि माइक्रोफाइनेंस

35 भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की रिपोर्ट, ‘31 मार्च 2024 तक दूरसंचार सदस्यता डेटा’, पृष्ठ संख्या 6, https://www.trai.gov.in/sites/default/files/PR_No.23of2024_o.pdf.

36 भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, <https://www.npci.org.in/what-we-do/upi/product-statistics>

37 आईएमएफ वर्किंग पेपर, जून 2021, ‘क्या डिजिटल वित्तीय समावेशन विकास को अनलॉक कर रहा है’, <https://tinyurl.com/2russwem>

38 सा-धन को आरबीआई द्वारा वर्ष 2015 में माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र के लिए एक एसआरओ के रूप में मान्यता दी गई थी ताकि एमएफआई की प्रभावी निगरानी, नियमों के अनुपालन और ग्राहकों के सर्वोत्तम हित में आचार संहिता के लिए उद्योग के नियमों, उपकरणों और प्रदर्शन मानकों को प्रशासित किया जा सके। एसआरओ के रूप में, सा-धन एमएफआई की प्रभावी निगरानी, नियमों के अनुपालन और ग्राहकों के सर्वोत्तम हित में आचार संहिता के लिए उद्योग के नियमों, उपकरणों और प्रदर्शन मानकों को तैयार करने और प्रशासित करने में सबसे आगे रहा है। सा-धन भारतीय माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र को पेशेवर, स्वस्थ और नैतिक तर्ज पर विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

39 <https://mfinindia.org/>

क्षेत्र में काम करने वाली सभी संस्थाएं समान नियमों के अधीन हों, सभी के लिए समानता का दृष्टिकोण सृजित करता है तथा उधारकर्ताओं के हित की रक्षा करता है।

2.60 वैश्विक स्तर पर, भारतीय माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारत में उधार लेने वाले ग्राहकों की संख्या अगले सबसे बड़े बाजार अर्थात् इंडोनेशिया से लगभग तीन गुना है। भारतीय माइक्रोफाइनेंस कवरेज (स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और संयुक्त देयता समूह (जेएलजी)) 50 प्रतिशत से अधिक घरों और भारतीय जनसंख्या⁴⁰ के 10 प्रतिशत से अधिक है।

तालिका II.4: भारत में दूसरा सबसे बड़ा माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र है

देश	बचतकर्ता (लाखों में)	उधारकर्ता (लाखों में)	बकाया ऋण (बिलियन अमेरिकी डॉलर में)
बांग्लादेश (जून 2022)	66.4	44.6	17.4
कंबोडिया (दिसंबर 2022)	2.7	2.1	9.7
फिलीपींस (दिसंबर 2020)	-	17.0	7.6
इंडोनेशिया (दिसंबर 2019)	-	56.8	2.1
पाकिस्तान (मार्च 2023)	98.1	9.25	1.8
भारत (मार्च 2023)			
एसएचजी	161	83	23.5
एमएफआई	-	73	44

स्रोत: उद्योग संघों, केंद्रीय बैंक की वेबसाइटों और शैक्षणिक प्रकाशनों जैसे विभिन्न स्रोतों से एकत्रित डेटा

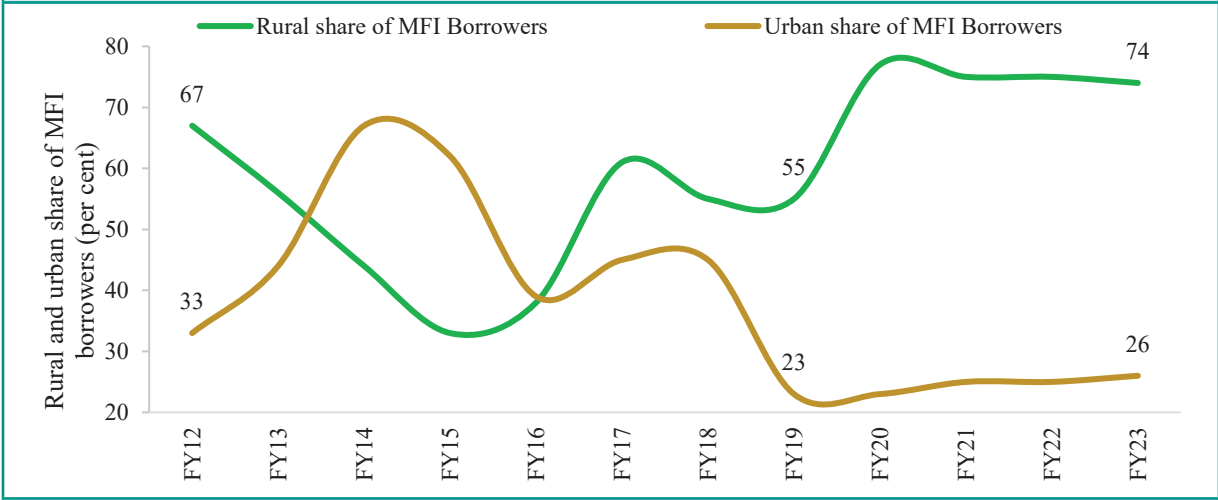
2.61 2023 भारत माइक्रोफाइनेंस रिपोर्ट के अनुसार, एमएफआई भारत के 28 राज्यों, पांच संघ राज्य क्षेत्रों और 646 से अधिक जिलों में काम करते हैं। वित्त वर्ष 23 तक भारत में दो सौ तेरह एमएफआई काम करते हैं, जिनकी 25,790 शाखाओं का नेटवर्क है और जिसमें 2.2 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। साथ में, वे माइक्रो-क्रेडिट⁴¹ के तहत ₹1.8 लाख करोड़ के कुल ऋण बकाया के साथ 532 लाख से अधिक ग्राहकों तक पहुँच चुके हैं। नए ग्राहकों का जुड़ना इस क्षेत्र के निरंतर समावेशन संबंधी प्रयासों को दर्शाता है और दूरस्थ और कम सेवा वाले भौगोलिक क्षेत्रों के लिए उम्मीद जगाता है। 31 मार्च 2023 तक, एमएफआई के पास बकाया ऋण वाले ग्राहकों की संख्या, जिसमें 179 दिनों से अधिक बकाया वाले ग्राहक भी शामिल हैं, 571 लाख थी। इनमें से, एमएफआई द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले सक्रिय ग्राहक (179 दिनों से अधिक बकाया वाले ग्राहकों को छोड़कर) 532 लाख थे, जो कि वर्ष दर वर्ष 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

2.62 यद्यपि एमएफआई ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के गरीबों की सेवा करते हैं, लेकिन वे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की ओर अधिक उन्मुख हैं। कुछ समय के लिए शहरी उधारकर्ताओं का प्रभुत्व था, और उद्योग में बड़े निवेशक, जैसे बंधन और अन्य एमएफआई जो बैंक/लघु वित्त बैंक (एसएफबी) बन गए, एमएफआई क्षेत्र का हिस्सा थे। ग्रामीण क्षेत्र की ओर एक निश्चित बदलाव हुआ है, और यह पिछले चार वर्षों से जारी है। ग्रामीण ग्राहकों की वर्तमान हिस्सेदारी 74 प्रतिशत है।

40 समावेशी वित्त भारत रिपोर्ट, 2023, एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज, <https://inclusivefinanceindia.org/wp-content/uploads/2023/12/IFI-Report-2023.pdf>

41 भारत माइक्रोफाइनेंस रिपोर्ट, 2023, सा-धन, <https://rb.gy/hnq8zo>

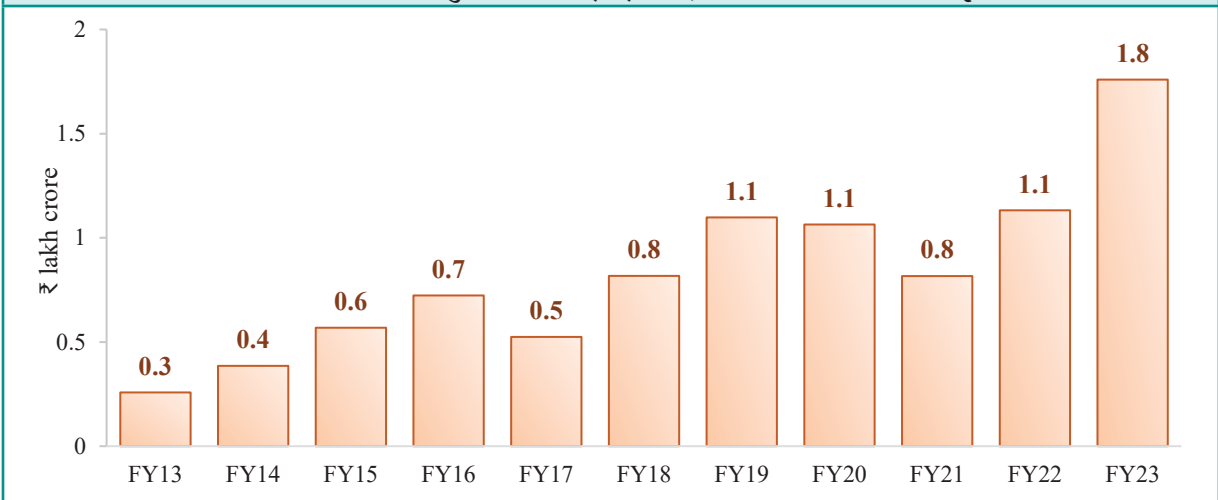
चार्ट II.11: ग्रामीण एमएफआई उधारकर्ताओं की बढ़ती हिस्सेदारी



स्रोत: भारत माइक्रोफाइनेंस रिपोर्ट 2023, सा धन (पृष्ठ 16, चित्र 2.8)

2.63 माइक्रोफाइनेंस मुख्यतः महिला-केंद्रित गतिविधि है। भारत में, एमएफआई के कुल ग्राहकों में से 98 प्रतिशत महिलाएँ हैं। इसके अलावा, यह अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अल्पसंख्यकों जैसे अन्य कमजोर और हाशिए पर पड़े वर्गों को भी महत्वपूर्ण तरीके से सेवा प्रदान करता है। एससी/एसटी उधारकर्ताओं का एक बड़ा हिस्सा अर्थात् 23 प्रतिशत ग्राहकों है।

चार्ट II.12: पिछले कुछ वर्षों में एमएफआई द्वारा ऋण वितरण में वृद्धि



स्रोत: भारत माइक्रोफाइनेंस रिपोर्ट 2023, सा धन (पृष्ठ 28, चित्र 2.18)

2.64 एमएफआई द्वारा ऋण वितरण में कोविड-19 महामारी जैसी बाह्य घटनाओं के कारण कुछ वर्षों को छोड़कर पूरे वर्ष स्थिर वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष 23 के दौरान, माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र ने जोरदार वापसी की, तथा पिछले वर्ष की तुलना में 55 प्रतिशत अधिक ₹1.8 लाख करोड़ का कुल वितरण प्राप्त किया।

2.65 वित्त वर्ष 23 के दौरान एमएफआई के प्रदर्शन और लाभप्रदता अनुपात उद्योग के अच्छी स्थिति और बेहतर संभावनाओं की तस्वीर पेश करते हैं। उद्योग ने प्रचालन लागत में कटौती करने में कामयाबी हासिल की, जबकि वित्त लागत को पिछले वर्षों की तरह कमोबेश उसी स्तर पर बनाए रखा। वित्त वर्ष 2023 के अंत में एमएफआई की कुल संपत्ति ₹1.5 लाख करोड़ थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक थी। पिछले कुछ वर्षों से यह क्षेत्र कुछ बाह्य घटनाओं के कारण बीच में एक या दो साल को छोड़कर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 23 में,

सभी एमएफआई के लिए आरओए और आरओई 2.5 प्रतिशत और 12.2 प्रतिशत रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में सुधार को दर्शाता है। आईबीआई के नियामक मानदंडों के अनुसार, एनबीएफसी-एमएफआई को अपनी जोखिम-भारित आस्तियों का कम से कम 15 प्रतिशत पूंजी के रूप में बनाए रखना होगा। यद्यपि अन्य कानूनी रूपों के लिए कोई शर्त नहीं है, लेकिन एनबीएफसी एमएफआई के बराबर पूंजी रखना वांछनीय है। भारतीय एमएफआई की पूंजी पर्याप्तता निर्धारित मानदंडों से काफी ऊपर है, यहां वित्त वर्ष 23 के लिए औसत सीएआर 26.5 रहा।

2.66 वित्त वर्ष 23 के दौरान, पोर्टफोलियो गुणवत्ता बढ़ाने में अच्छी प्रगति हासिल की गई है। एमएफआई चूक से बचने, वसूली में सुधार करने और निपटान और राइट-ऑफ के माध्यम से पुराने मामलों से निपटने में सक्षम रहे हैं। एमएफआई के लिए प्रदर्शन और जवाबदेही रिपोर्टिंग (पीएआर) 30+ अनुपात कोविड-पूर्व स्तरों की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी वित्त वर्ष 19 में हासिल किए गए न्यूनतम अपचारी (डेलिक्वेंसी) अनुपातों से कम हैं। सीआरआईएफ-हाईमार्क विश्लेषण से पता चलता है कि वित्त वर्ष 23 के दौरान, एमएफआई 30, 60 और 90-दिवसीय पीएआर के मामले में एक बकेट से दूसरे में हासिल ऋणों⁴² के आगे के प्रवाह को कम करने में सक्षम थे। हालांकि, एमएफआई और बैंकों⁴³ के लिए 91 से 180-दिवसीय बकेट में आगे के प्रवाह में वृद्धि हुई।

2.67 ग्रामीण भारत में माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र की सफलता को कई संकेतकों का उपयोग करके मापा जा सकता है। सबसे व्यापक माइक्रोफाइनेंस कार्यक्रम, एसएचजी-बैंक लिंकेज प्रोग्राम (एसएचजी-बीएलपी) ने वित्त वर्ष 22 और वित्त वर्ष 23 में बैंकों के पास बकाया ऋण वाले एसएचजी की संख्या और राशि के माध्यम से महामारी के बाद के पुनरुत्थान को दर्शाया है। वित्त वर्ष 23 के दौरान, एसएचजी-बीएलपी के तहत ऋण वितरण ₹1.5 लाख करोड़ था, जो 45.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता करता है। वित्त वर्ष 23 के दौरान ऋण से जुड़े एसएचजी की संख्या वित्त वर्ष 22 में 34 लाख से बढ़कर 43 लाख हो गई। मार्च 2023 तक, बैंकिंग प्रणाली में 24.7 प्रतिशत की अच्छी वृद्धि के साथ ₹58,893 करोड़ की एसएचजी बचत थी, जिसमें प्रति एसएचजी औसत बचत ₹43,940 थी⁴⁴। आरबीआई के वित्तीय समावेशन सूचकांक में मार्च 2023 के 60.1 से मार्च 2024 में 64.2 तक सुधार, भारत में वित्तीय क्षेत्र⁴⁵ की पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता के क्षेत्र में की जा रही प्रगति को दर्शाता है।

भारतीय पूंजी बाजार में रुझान

2.68 भू-राजनीतिक जोखिम बढ़ने, ब्याज दरों में वृद्धि और कमोडिटी की अस्थिर कीमतों के बावजूद, भारतीय पूंजीगत बाजार वित्त वर्ष 24 में उभरते बाजारों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले बाजारों में से एक रहे हैं, जो भारत की उज्ज्वल आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। पूंजीगत बाजार भारत की विकास गाथा में महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, प्रौद्योगिकी, नवाचार और डिजिटलीकरण के बल पर पूंजी निर्माण और निवेश परिदृश्य में उनकी हिस्सेदारी बढ़ रही है। निम्नलिखित खंड भारत में प्राथमिक बाजारों, द्वितीयक बाजारों और संस्थागत निवेश में महत्वपूर्ण रुझान प्रस्तुत करते हैं।

प्राथमिक बाजार

2.69 स्वस्थ घरेलू आर्थिक प्रदर्शन और अनुकूल निवेश माहौल के बीच, प्राथमिक बाजार वित्त वर्ष 24 के दौरान मजबूत रहे, जिससे ₹10.9 लाख करोड़ का पूंजी निर्माण हुआ (जो वित्त वर्ष 23 के दौरान निजी और सार्वजनिक निगमों के

42 बिगड़ा हुआ ऋण एक ऐसा ऋण है जो समझौते की मूल शर्तों के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर रहा है।

43 माइक्रोफाइनेंस ऋण पर सीआरआईएफ त्रैमासिक प्रकाशन का खंड XXIII, 'माइक्रोलेंड', मार्च 2023, <https://www.crihighmark.com/media/2921/crif-microlend-vol-iii-mar-2023.pdf>

44 भारत में माइक्रोफाइनेंस की स्थिति 2022-23, <https://shorturl.at/Blzyna>

45 एफआई-इंडेक्स की अवधारणा एक व्यापक सूचकांक के रूप में तैयार की गई है, जिसमें सरकार और संबंधित क्षेत्रीय विनियामकों के परामर्श से बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक, साथ-साथ ही पेंशन क्षेत्र का विवरण शामिल है। एफआई-इंडेक्स में तीन व्यापक पैरामीटर (कोष्ठक में दर्शाए गए) शामिल हैं, अर्थात्, एक्सेस (35 प्रतिशत), उपयोग (45 प्रतिशत), और गुणवत्ता (20 प्रतिशत), इनमें से प्रत्येक में विभिन्न आयाम शामिल हैं, जिनकी गणना कई संकेतकों के आधार पर की जाती है।

सकल स्थिर पूंजी निर्माण का लगभग 29 प्रतिशत है), जबकि वित्त वर्ष 23 में यह ₹9.3 लाख करोड़ था। वित्त वर्ष 24 में जुटाई गई कुल राशि में से 78.8 प्रतिशत ऋण निर्गमों के माध्यम से जुटाई गई थी। तीनों तरीकों, अर्थात् इक्विटी, ऋण और हाइब्रिड के माध्यम से निधियों का संग्रहण पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 24 में क्रमशः 24.9 प्रतिशत, 12.1 प्रतिशत और 513.6 प्रतिशत बढ़ा।

2.70 आरंभिक सार्वजनिक निर्गमों (आईपीओ) की संख्या वित्त वर्ष 24 में 66 प्रतिशत बढ़कर वित्त वर्ष 23 के 164 से वित्त वर्ष 24 में 272 हो गई, जबकि जुटाई गई राशि वित्त वर्ष 23 की तुलना में 24 प्रतिशत बढ़ी (वित्त वर्ष 23 में ₹54,773 करोड़ से वित्त वर्ष 24 में 67,995 करोड़) थी। एक्सचेंजों पर एसएमई प्लेटफॉर्म पर वित्त वर्ष 24 के दौरान अत्यधिक गतिविधियाँ देखी गई क्योंकि एसएमई के आईपीओ/एफपीओ की संख्या 1.6 गुना बढ़ गई (वित्त वर्ष 23 में 125 से वित्त वर्ष 24 में 196 तक), जबकि जुटाई गई इसी राशि में पिछले वर्ष की तुलना में ढाई गुना से अधिक की वृद्धि हुई (वित्त वर्ष 23 में ₹2,333 करोड़ से वित्त वर्ष 24 में ₹6,095 करोड़ तक)। ईएण्डवाई ग्लोबल आईपीओ ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय एक्सचेंज आईपीओ लिस्टिंग में वैश्विक अग्रणी थे। भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़कर 2023 में 17 प्रतिशत हो गई, जो 2021 और 2022 में क्रमशः 6 प्रतिशत और 11 प्रतिशत थी⁴⁶। बाजार की सकारात्मक परिस्थितियों को दर्शाते हुए, योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी)⁴⁷ वित्त वर्ष 24 के दौरान कारपोरेट्स के लिए एक महत्वपूर्ण इक्विटी फंड जुटाने के तंत्र के रूप में उभरे। राइट्स इश्यू के माध्यम से संसाधन जुटाना वित्त वर्ष 24 के दौरान दोगुना से अधिक बढ़कर ₹15,110 करोड़ हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह ₹6,751 करोड़ था।

सार्वजनिक ऋण निर्गम

2.71 भारत में कॉर्पोरेट ऋण बाजार लगातार मजबूत होता जा रहा है। वित्त वर्ष 2024 के दौरान, कारपोरेट बंधपत्र जारी करने का मूल्य पिछले वित्त वर्ष के 7.6 लाख करोड़ से बढ़कर ₹8.6 लाख करोड़ हो गया। वित्त वर्ष 2024 में कारपोरेट बंधपत्र सार्वजनिक निर्गमों की संख्या किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए अब तक की सबसे अधिक थी, जिसमें जुटाई गई राशि (₹19,167 करोड़) चार साल के उच्चतम स्तर पर थी। कॉर्पोरेट्स के लिए निजी प्लेसमेंट पसंदीदा चैनल बना रहा, जो बॉन्ड मार्केट के माध्यम से जुटाए गए कुल संसाधनों का 97.8 प्रतिशत था। निवेशकों की बढ़ती मांग और बैंकों से उधार लेने की लागत में वृद्धि ने इन बाजारों को कॉर्पोरेट्स के लिए वित्तपोषण आवश्यकताओं के लिए अधिक आकर्षक बना दिया है। मार्च 2024 के अंत में बकाया कारपोरेट बंधपत्र की मात्रा साल-दर-साल 5.5 प्रतिशत बढ़कर ₹45 लाख करोड़ (यानी, जीडीपी का 15.5 प्रतिशत) हो गई।

आरईआईटी और इनविट्स

2.72 वित्त वर्ष 24 के दौरान, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (आरईआईटी) और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (इनविट्स) द्वारा 39,024 करोड़ रुपये जुटाए गए, जो वित्त वर्ष 23 की तुलना में पांच गुना से अधिक है, जिसे अवसरान्तरा के विकास पर सरकार द्वारा दिए गए बल के जोर से समर्थन मिला।

द्वितीयक बाजार

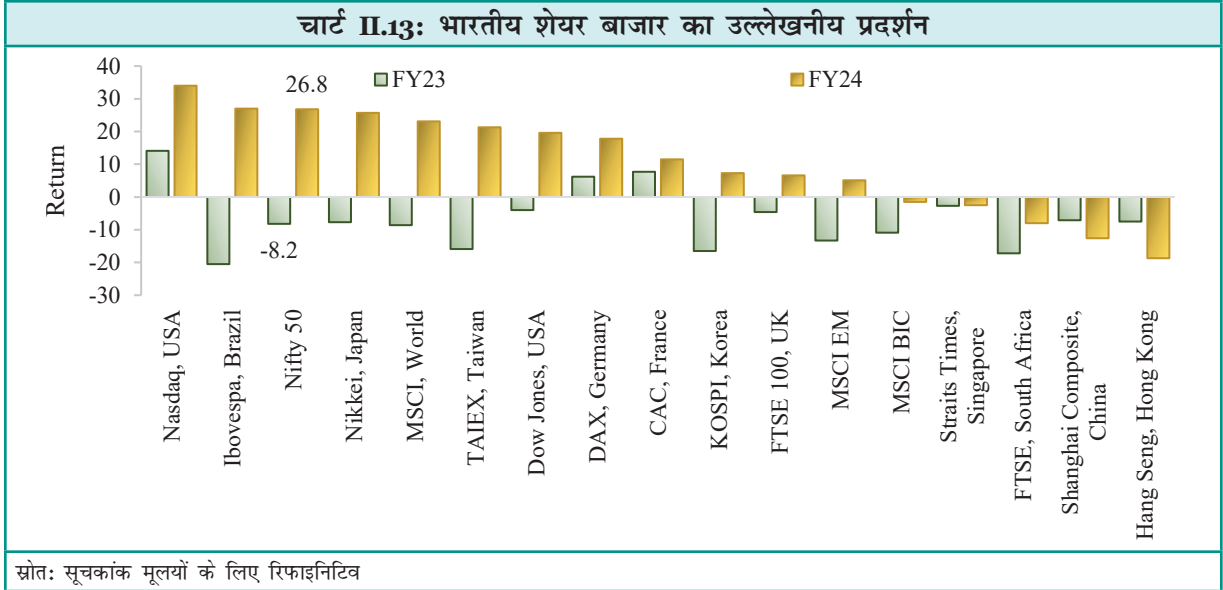
भारत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बाजारों में शामिल

2.73 वित्त वर्ष 23 में अत्यधिक अशांत वैश्विक माहौल को झेलने के बाद, वैश्विक शेयर बाजारों ने वित्त वर्ष 24 के दौरान सुधार किया और अच्छा प्रदर्शन किया। चीन और हांगकांग को छोड़कर सभी प्रमुख बाजारों ने पिछले वर्ष की तुलना में इस अवधि के दौरान बेहतर रिटर्न दिया। भारतीय शेयर बाजार सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले बाजारों में से

46 19 फरवरी 2024 को 'भारतीय स्टॉक एक्सचेंज 2023 में आईपीओ की संख्या के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर' पर ई एंड वाई प्रेस विज्ञापित, <https://shorturl-at/Lj6Z3>

47 क्यूआईपी की शुरुआत सेबी ने वर्ष 2006 में की थी, जिसके तहत भारतीय सूचीबद्ध कंपनियाँ इक्विटी शेयर, पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर या सेबी द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना के तहत उल्लिखित किसी भी अन्य प्रतिभूति को जारी करके धन जुटा सकती हैं। सूचीबद्ध कंपनियाँ सेबी को प्री-इश्यू फाइलिंग जमा करने जैसी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा किए बिना भी पूंजी जुटा सकती हैं।

एक रहा, जिसमें भारत का निफ्टी 50 इंडेक्स वित्त वर्ष 24 के दौरान 26.8 प्रतिशत चढ़ा, जबकि वित्त वर्ष 23 के दौरान (-)8.2 प्रतिशत था। वित्त वर्ष 24 में वैश्विक बाजारों में अमेरिका, ब्राजील और जापानी बाजारों से शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। एआई के नेतृत्व में टेक स्टॉक में उछाल के सबूत मिले, जिसमें वित्त वर्ष 23 में भारी नुकसान के बाद वित्त वर्ष 24 के दौरान टेक-हैवी यूएस नैस्डैक इंडेक्स में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई।



2.74 पिछले कुछ वर्षों में दुनिया और उभरते बाजारों की तुलना में भारतीय शेयर बाजार के शानदार प्रदर्शन का श्रेय मुख्य रूप से वैश्विक भू-राजनीतिक और आर्थिक उतार-चढ़ावों के प्रति भारत की समुत्थानशीलता, इसके ठोस और स्थिर घरेलू समष्टि आर्थिक दृष्टिकोण और घरेलू निवेशक आधार की मजबूती को दिया जा सकता है। भारतीय बाजारों के सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाते हुए, एमएससीआई-ईएम सूचकांक में भारत का भार 23 अप्रैल के अंत में 13.7 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 24 के अंत में 17.7 प्रतिशत हो गया है, जो सूचकांक में ईएम के बीच दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है।

2.75 भारतीय शेयर बाजार के बाजार पूंजीकरण में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। आकर्षक निवेश स्थल के रूप में भारतीय शेयर बाजार में घरेलू और वैश्विक निवेशकों की उल्लेखनीय रुचि और निरंतर आईपीओ गतिविधि ने वित्त वर्ष 24 में बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारतीय बाजार को दुनिया में पांचवें स्थान पर पहुंचा दिया। भारत का बाजार पूंजीकरण और जीडीपी अनुपात पिछले पांच वर्षों में काफी सुधरकर वित्त वर्ष 24 में 124 प्रतिशत हो गया है, जबकि वित्त वर्ष 19 में यह 77 प्रतिशत था, जो चीन और ब्राजील जैसी अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कहीं अधिक है। सावधानी बरतना जरूरी है। हालांकि, बाजार पूंजीकरण और जीडीपी अनुपात जरूरी नहीं कि आर्थिक उन्नति या विकास का संकेत हो। वित्तीय आस्तियों वास्तविक वस्तुओं और सेवाओं पर दावे हैं। यदि वास्तविक अर्थव्यवस्था पर इक्विटी बाजार के दावे अत्यधिक उच्च हैं, तो यह बाजार की समुत्थानशीलता के बजाय बाजार की अस्थिरता का अग्रदूत है।

2.76 वित्त वर्ष 2024 के दौरान निवेशकों की बढ़ती भागीदारी और सकारात्मक बाजार रुझानों के साथ मुद्रा डेरिवेटिव को छोड़कर एक्सचेंजों में सभी खंडों में कारोबार मूल्य में वृद्धि हुई, वित्त वर्ष 2024 में क्मोडिटी डेरिवेटिव कारोबार में 87 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो ऊर्जा खंड के विकल्प अनुबंधों के कारोबार में वृद्धि से प्रेरित थी।

तालिका II.5: विभिन्न देशों में बाजार पूंजीकरण से सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात (प्रतिशत)

	भारत	चीन	ब्राजील	जापान	दक्षिण कोरिया	यूनाइटेड किंगडम	संयुक्त राज्य अमेरिका
दिसम्बर-19	77	60	65	121	89	106	159
दिसम्बर-20	95	79	68	129	122	92	197
दिसम्बर-21	113	80	50	136	127	108	208
दिसम्बर-22	105	65	42	126	96	91	158
दिसम्बर-23	124	61	44	147	114	71	179

नोट: 'जीडीपी के आंकड़े वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज (डब्ल्यूएफई) से लिए गए हैं, और बाजार पूंजीकरण की गणना एनएसडीएक्यू और एनवाईएस के बाजार पूंजीकरण के योग के रूप में की जाती है।

स्रोत: सीईआईसी डेटाबेस, विश्व बैंक, डब्ल्यूएफई

2.77 बॉक्स II.3 प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से पूंजी बाजार को मजबूत करने के लिए की गई पहलों पर चर्चा करता है, जिन्होंने उनके प्रदर्शन और दक्षता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

बॉक्स II.3: प्रौद्योगिकी और भारतीय पूंजी बाजार का तालमेल: विकास और दक्षता को बढ़ावा देना

भारतीय पूंजी बाजारों में विभिन्न उप-बाजारों में व्यापक विस्तार देखा गया है, देश का इक्विटी बाजार पूंजीकरण मई 2024 में 415 लाख करोड़ (यूएसडी 5.0 ट्रिलियन) तक पहुंच गया है, जिससे यह वैश्विक रैंकिंग में पांचवीं स्थान पर है।

प्रौद्योगिकी का प्रसार दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं को बदलने में एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक रहा है, और भारतीय पूंजीगत बाजार इसका अपवाद नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में लगातार बदलाव हुए हैं, विकास और दक्षता को सुविधाजनक बनाने के लिए तकनीकी प्रगति का लाभ उठाया गया है। प्रौद्योगिकी बाजार नियामक सेबी के तीन लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है: बाजार विनियमन, निवेशक संरक्षण और बाजार विकास।

आज व्यक्तिगत निवेशकों की संख्या साढ़े नौ करोड़ से अधिक है और उनके पास लगभग 2500 सूचीबद्ध कंपनियों के माध्यम से बाजार का लगभग 10 प्रतिशत प्रत्यक्ष स्वामित्व है, जो मार्च 2024 तक लगभग 36 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के बराबर है, इसके अलावा इक्विटी म्यूचुअल फंड में अप्रत्यक्ष स्वामित्व है, जिनकी प्रबंधन के तहत संपत्ति 28 लाख करोड़ रुपये है। इस तरह, प्रौद्योगिकी एक्सचेंजों को फर्मों और लाखों बाजार निवेशकों को पूंजी आवंटित करने में मदद करती है ताकि वे उन कंपनियों में निवेश कर सकें, जहां वे कभी नहीं गए और उनकी दीर्घकालिक सफलता और धन सृजन में भाग ले सकें। कुल मिलाकर, पिछले तीन दशकों में भारत में बाजार पूंजीकरण 100 गुना से अधिक बढ़ गया है।

इंडिया स्टैक और विनियामक उपायों जैसी तकनीकी प्रगति ने खुदरा निवेशकों की भागीदारी और गतिविधि में अभूतपूर्व वृद्धि को बढ़ावा दिया है। उपयोगकर्ता के अनुकूल ट्रेडिंग ऐप्स, मोबाइल-फ्रेंडली शैक्षिक संसाधनों और वित्तीय बाजार मार्गदर्शन के प्रचलन और प्रसार ने पूंजीगत बाजारों⁴⁸ तक पहुंच को लोकतांत्रिक बना दिया है। प्रौद्योगिकी के निर्बाध उपयोग ने निवेशकों को मिनटों में ऑनलाइन ट्रेडिंग और डीमैट खाते खोलने, अपने घरों में आराम से व्यापार करने, निवेश रिपोर्ट तक पहुंचने और कुशलतापूर्वक ऑनलाइन पूछताछ करने का अधिकार दिया है। निवेशक शिकायत

48 समझाया गया: भारतीय शेयर बाजार में खुदरा भागीदारी में वृद्धि का कारण क्या है? लाइवमिंट (2024), लिंक यहां उपलब्ध है: <https://tinyurl.com/3xetmuvt>

समाधान के लिए मंच, सेबी शिकायत निवारण प्रणाली (एससीओआरईएस) तथा निवेशक शिक्षा के लिए कार्यक्रम, सिक््योरिटी मार्केट ट्रेनर (एसएमएआरटीएस) जैसी पहलें, बाजार सहभागियों, विशेषकर पहली बार निवेश करने वाले निवेशकों के हितों की रक्षा करने में सहायक रही हैं।

बाजार के विकास में प्रौद्योगिकी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत की अनूठी डिजिटल वास्तुकला ने पूंजीगत बाजार नियामक को “टी+1 निपटान व्यवस्था” को आराम से अपनाने का आत्मविश्वास दिया है, यह एक ऐसी उपलब्धि है जिसका अनुसरण दुनिया भर⁴⁹ के बहुत कम देश कर रहे हैं। क्लियरिंग कॉरपोरेशन (सीसी) के बीच “इंटरऑपरेबिलिटी” की शुरुआत ने स्टॉक एक्सचेंजों और सीसी के बीच उम्मीद से अधिक संबंध बनाए, जिसने प्रतिभागियों⁵⁰ के बेहतर मार्जिन उपयोग और पूंजी संसाधनों के माध्यम से ट्रेडिंग लागत को कम किया। भारतीय पूंजीगत बाजारों ने द्वितीयक बाजार में ब्लॉक किए गए खाते द्वारा समर्थित आवेदन (एसबीए) “सुविधा को भी प्रायोगिक आधार पर अपनाया है, जो निवेशकों को व्यापार की पुष्टि होने तक अपने बैंक में धन को अवरुद्ध करने की अनुमति देता है। नेशनल सिक््योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की हाल ही में एनएसडीएल-सीएस नामक पहल ने कई खातों और म्यूचुअल फंड फोलियो⁵¹ में डीमैट प्रारूप में रखी गई आस्तियों का एक समग्र दृश्य प्रस्तुत करके निवेशकों के जीवन को और आसान बना दिया है।

विकास, निवेशक सुरक्षा और बाजार विकास से परे, आज व्यापार निरंतरता पूंजी बाजारों का एक महत्वपूर्ण पहलू बन गई है। वर्ष 2022 में शुरू किया गया, “डीआर45” ढांचा न्यूनतम स्विचिंग टाइम⁵² के साथ अप्रत्याशित घटनाओं के मामले में मौजूदा कनेक्टिविटी मापदंडों का उपयोग करके व्यापार जारी रखने की अनुमति देता है। सेबी के परामर्श से, स्टॉक एक्सचेंजों और ब्रोकरों ने स्टॉकब्रोकर्स के इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ियों को दूर करने के लिए विभिन्न उपायों को लागू किया है, जैसे कि “एलएएमए⁵³ (लॉग एनालिटिक्स और मॉनिटरिंग एप्लिकेशन) रिपोर्टिंग” एपीआई, जो आईटी संरचना का अवलोकन करने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है। इसके अतिरिक्त, एनसीएल और आईसीसीएल⁵⁴ जैसे क्लियरिंग कॉरपोरेशन ने अप्रत्याशित सॉफ्टवेयर विफलताओं⁵⁵ को प्रबंधित करने के लिए ‘एसएएस’ (सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस) मॉडल के रूप में संचालित होने के लिए दो-तरफा पोर्टेबिलिटी पर काम किया है।

जबकि प्रौद्योगिकी और पूंजीगत बाजारों के तालमेल ने महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त किए हैं, उभरती चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए। गोपनीयता संबंधी चिंताएँ, साइबर सुरक्षा जोखिम और आबादी में बढ़ता डिजिटल विभाजन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर भी, नियामक यह महसूस करते हुए कि प्रौद्योगिकी और पूंजीगत बाजारों के समन्वय से अधिकतम क्षमता को अनलॉक करना भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र विकास और विकास के लिए आवश्यक है, अपने दृष्टिकोण में दृढ़ रहे हैं।

पूंजी बाजार में खुदरा भागीदारी

2.78 भारतीय पूंजीगत बाजारों में पिछले कुछ वर्षों में प्रत्यक्ष (अपने खातों के माध्यम से बाजारों में व्यापार) और अप्रत्यक्ष (म्यूचुअल फंड के माध्यम से) चौनलों के माध्यम से खुदरा गतिविधि में उछाल देखा गया है। इक्विटी कैश सेगमेंट टर्नओवर में व्यक्तिगत निवेशक की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 24 में 35.9 प्रतिशत थी। दोनों डिपॉजिटरी के साथ डीमैट खातों की संख्या वित्त वर्ष 23 में 1,145 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 1,514 लाख हो गई। बाजार में व्यक्तिगत

49 भारतीय इक्विटी बाजारों ने सीमित तरीके से एक ही दिन के निपटान चक्र (“टी+ओ”) में भी बदलाव किया है, ऐसा करने वाला यह पहला देश बन गया है। छोटे निपटान चक्रों में बदलाव ने दक्षता बढ़ाई है और निपटान जोखिम कम किया है।

50 क्लियरिंग कॉरपोरेशन के बीच अंतर-संचालन, पीडब्ल्यूसी (2019)

51 प्रौद्योगिकी और शिक्षा के माध्यम से निवेशक केंद्रित सेवाओं को बढ़ाना, एआईबीआई शिखर सम्मेलन (2022)

52 <https://www.nseindia.com/trade/disaster.recovery.faqs>

53 एलएएमए रिपोर्टिंग: विफलता कोई विकल्प नहीं है, आईटीआरएस ब्लॉग (2023)

54 नेशनल सिक््योरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड; इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड

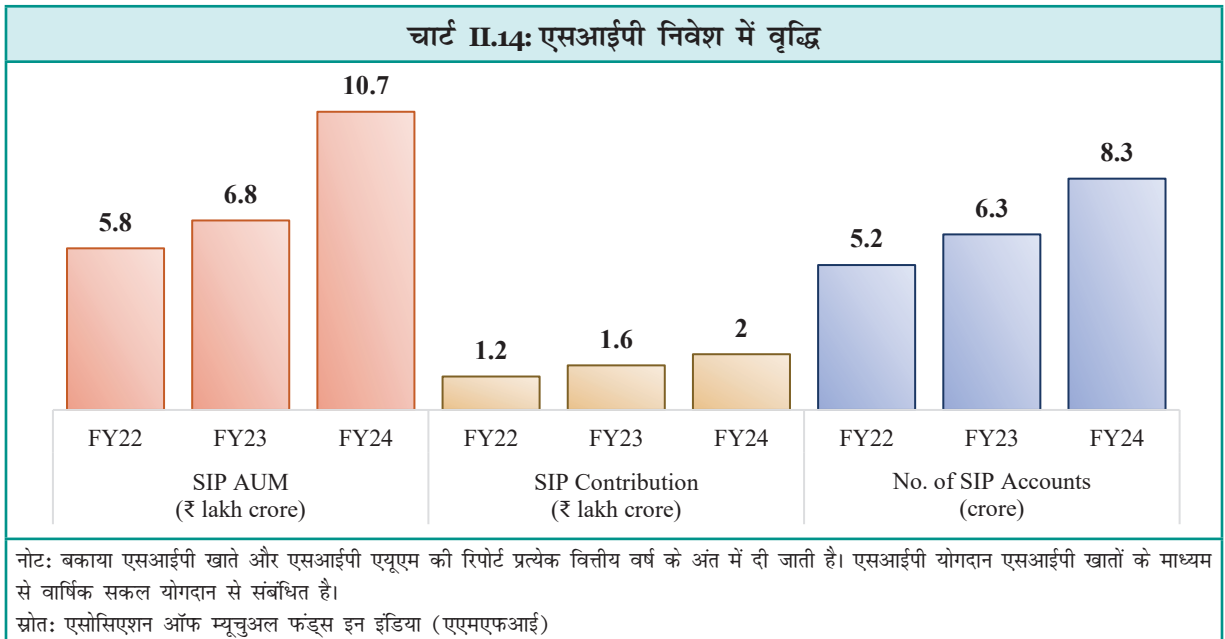
55 एनएसई क्लियरिंग आर्काइव दिनांक 29 मार्च, 2023

निवेशकों की आमद का यह प्रभाव एक्सचेंजों के साथ नए निवेशक पंजीकरण, कुल कारोबार मूल्य में उनकी हिस्सेदारी, उनके निवल निवेश और सूचीबद्ध कंपनियों में उनके स्वामित्व में भी परिलक्षित होता है। उदाहरण के लिए, एनएसई में पंजीकृत निवेशक आधार मार्च 2020 से मार्च 2024 तक लगभग तिगुना बढ़कर 31 मार्च 2024 तक 9.2 करोड़ हो गया है, जिसका संभावित अर्थ यह है कि अब 20 प्रतिशत भारतीय परिवार अपनी घरेलू बचत को वित्तीय बाजारों में लगा रहे हैं।

म्यूचुअल फंड: पूंजी बाजार में वित्तीय बचत और खुदरा भागीदारी में तेजी लाना

2.79 म्यूचुअल फंड के द्वारा अप्रत्यक्ष चैनल के माध्यम से खुदरा भागीदारी में वृद्धि अधिक महत्वपूर्ण और स्थिर थी। वित्त वर्ष 2024 म्यूचुअल फंड (एमएफ) के लिए एक शानदार वर्ष रहा है क्योंकि एमएफ की 'प्रबंधन के तहत आस्ति' (एयूएम) वित्त वर्ष 2024 के अंत में ₹14 लाख करोड़ (वार्षिक आधार पर 35 प्रतिशत की वृद्धि) बढ़कर ₹53.4 लाख करोड़ हो गई, जिसे मार्क-टू-मार्केट (एमटीएम) लाभ और उद्योग के विस्तार से बढ़ावा मिला। वित्त वर्ष 23 के अंत में फोलियो की कुल संख्या 14.6 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 24 के अंत में 17.8 करोड़ हो गई। आय/ऋण-उन्मुख योजनाओं को छोड़कर, एमएफ योजनाओं की सभी श्रेणियों में निवल निवेश हुआ। विकास/इक्विटी-उन्मुख और हाइब्रिड योजनाओं में निवेश एमएफ में निवल निवेश का 90 प्रतिशत से अधिक था। निष्क्रिय योजनाओं में, एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) (गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड के अलावा) में निवल आस्तियों में 37 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

2.80 भारतीय एमएफ सेगमेंट में वर्तमान में लगभग 8.4 करोड़ व्यवस्थित निवेश योजना (एसआईपी)⁵⁶ खाते हैं, जिनके माध्यम से निवेशक नियमित रूप से योजनाओं में निवेश करते हैं। पिछले तीन वर्षों में वार्षिक निवल एसआईपी प्रवाह दोगुना हो गया है, जो वित्त वर्ष 21 में ₹0.96 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में ₹2 लाख करोड़ हो गया है। इक्विटी-उन्मुख योजनाओं के लिए कुल एसआईपी एयूएम एमएफ उद्योग के एयूएम का लगभग 35 प्रतिशत है। इसने 31 दिसंबर 2023 तक भारतीय इक्विटी में एमएफ के स्वामित्व को 9.2 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है, जबकि 31 दिसंबर 2021 तक यह 7.7 प्रतिशत था।



2.81 महामारी की अवधि और उसके बाद निवेशकों के प्रवेश को सुविधाजनक बनाने वाले कुछ कारकों में निर्बाध तकनीकी एकीकरण, वित्तीय समावेशन के लिए सरकारी उपाय, डिजिटल अवसंरचना का विकास, तेजी से स्मार्टफोन की पहुंच, कम लागत वाली ब्रोकरेज का उदय, वैकल्पिक स्रोतों से आय उत्पन्न करने की खोज और रियल

56 एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक व्यवस्थित तरीका है, जिसमें नियमित अंतराल पर बाजार में निवेश के लिए एक छोटी पूर्व-निर्धारित राशि आवंटित की जाती है।

एस्टेट और सोने जैसे पारंपरिक आस्ति वर्गों द्वारा उत्पन्न कम लाभ शामिल हैं। हालांकि, खुदरा निवेशकों ने वित्तीय बाजारों में अपने लाभ को भुनाया है और वास्तविक आस्तियों में निवेश कर रहे हैं। यह स्मार्ट पोर्टफोलियो विविधताकरण है। कम ब्याज दरों, कोविड-19 के बाद ठोस रिकवरी, उच्च मुद्रास्फीति और सहायक नीति पृष्ठभूमि के रूप में अनुकूल आर्थिक माहौल ने भी पूंजीगत बाजार आस्तियों के खुदरा संचय को बढ़ावा दिया। इसके अलावा, निवेशकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करने वाले निरंतर निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों ने प्रतिभूति बाजारों में व्यक्तिगत भागीदारी की निरंतर वृद्धि में योगदान दिया है। अगस्त 2023 में, सेबी ने ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) की शुरुआत की, जो प्रतिभूति बाजार में उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करने के लिए ऑनलाइन सुलह और ऑनलाइन मध्यस्थता को जोड़ती है। वित्त वर्ष 24 में शुरू किया गया एक और महत्वपूर्ण उपाय निवेशक की मृत्यु के मामले में रिपोर्टिंग और सत्यापन के लिए केंद्रीकृत तंत्र था, जिससे कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरण प्रक्रिया सुचारू हो गई। निवेशक सुरक्षा कोष⁵⁷ और निपटान गारंटी कोष⁵⁸ में वृद्धि और निपटान चक्र को छोटा करने से भारतीय बाजारों में सुरक्षा और सुरक्षा की धारणा में सुधार हुआ है। फिर भी, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि खुदरा निवेशक इन फंडों को अपने नुकसान को कम करने और बैकस्टॉप प्रदान करने के तंत्र के रूप में न समझें।

2.82 एनएसई पर पूंजीकृत अद्वितीय कर आईडी की संख्या वित्त वर्ष 19 में 2.7 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 9.2 करोड़ हो गई। भारतीय पूंजीगत बाजार में खुदरा निवेशकों की बढ़ी हुई भागीदारी बेहद स्वागत योग्य है और पूंजीगत बाजार को स्थिरता प्रदान करती है। इसने खुदरा निवेशकों को अपनी बचत पर अधिक लाभ अर्जित करने में भी सक्षम बनाया है। अधिकांश नए खुदरा निवेशक संभवतः युवा हैं और उनमें जोखिम लेने की क्षमता अधिक हो सकती है। यह खुदरा निवेशकों द्वारा डेरिवेटिव ट्रेडिंग, खास तौर पर एक्सपायरी-डे ट्रेडिंग में दिखाई गई रुचि में भी परिलक्षित होता है। जबकि डेरिवेटिव हेजिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन दुनिया भर के निवेशक इनका इस्तेमाल ज्यादातर सट्टा इंस्ट्रूमेंट के तौर पर करते हैं। भारत भी शायद इसका अपवाद नहीं है।

2.83 डेरिवेटिव ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा लाभ की संभावना होती है। इस प्रकार, यह मनुष्यों की जुआ खेलने की प्रवृत्ति को पूरा करता है और अगर लाभदायक हो तो आय बढ़ा सकता है। ये विचार डेरिवेटिव ट्रेडिंग में सक्रिय खुदरा भागीदारी को बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि, वैश्विक स्तर पर, डेरिवेटिव ट्रेडिंग में निवेशकों को ज्यादातर समय नुकसान होता है। निवेशकों को जागरूक करना और निरंतर वित्तीय शिक्षा देना उन्हें डेरिवेटिव ट्रेडिंग से कम या नकारात्मक अपेक्षित रिटर्न के बारे में चेतावनी देने के लिए जरूरी है। एक महत्वपूर्ण शेरर सुधार में नुकसान हो सकता है जो डेरिवेटिव के माध्यम से पूंजीगत बाजारों में भाग लेने वाले खुदरा निवेशकों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। निवेशकों की व्यावहारिक प्रतिक्रिया अदृश्य अधिक महत्वपूर्ण ताकतों द्वारा श्थोखाश महसूस करना होगी। वे लंबे समय तक पूंजीगत बाजारों में वापस नहीं आ सकते हैं। यह उनके और अर्थव्यवस्था के लिए क्षति है।

2.84 अर्थव्यवस्थाओं का वित्तीयकरण अच्छा नहीं रहा है, यहाँ तक कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी। वर्ष 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट इसका स्पष्ट उदाहरण है। विकासशील देशों को तब दुर्बल करने वाले संकटों का सामना करना पड़ता है जब वित्तीय बाजार के श्वाचारश् और विकास आर्थिक विकास से आगे निकल जाते हैं। वर्ष 1997-98 के एशियाई संकट ने क्षेत्र की ऊंची उड़ान भरने वाली अर्थव्यवस्थाओं को लंबे समय के लिए पीछे धकेल दिया। इसलिए, भारत को वित्तीय बाजार⁵⁹ का व्यवस्थित और क्रमिक विकास करने की आवश्यकता है।

2.85 सभी हितधारकों - बाजार सहभागियों, बाजार अवसरचना संस्थानों, विनियामकों और सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पूंजीगत बाजार बचत को उनके सबसे अधिक उत्पादक निवेशों की ओर निर्देशित करने की अपनी सैद्धांतिक रूप से सौंपी गई भूमिका निभाए। यह सिर्फ राष्ट्रीय हित में नहीं है। यह एक स्वार्थपूर्ण कार्य भी है।

57 निवेशक संरक्षण निधि, दावे के स्वीकृत मूल्य को पूरा करने के लिए चूककर्ताओं के खते में अपर्याप्त पाई गई धनराशि की सीमा तक निवेशकों को मुआवजा देती है, जो सदस्यों के निष्कासन/चूक की घोषणा पर उत्पन्न होने वाले दावों के संबंध में प्रति चूककर्ता/निष्कासित सदस्य प्रति निवेशक 25 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन है।

58 निपटान गारंटी निधि का उद्देश्य स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से एक्सचेंज के सदस्यों के सभी लेनदेन के निपटान की गारंटी देना है।

59 अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें: नागेश्वरन, वी. एवं नटराजन, गुलजार. (2019), 'दा राइज ऑफ फाइनेंस: कॉजिस कॉनसिक्वेंसिस एंड क्योर्स' कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज: सामाजिक दृष्टिकोण से वित्त का लाभ उठाना

2.86 बॉक्स II.4 में सामाजिक-विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक धन जुटाने के साधन प्रदान करके वित्तपोषण अंतर को पाटने में सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई) की भूमिका पर चर्चा की गई है।

बॉक्स II.4: भारत में सोशल स्टॉक एक्सचेंज: प्रगति कर रहे हैं

पिछले कुछ वर्षों में भारतीय प्रतिभूति बाजारों की विशेषता रही है कि उन्होंने वित्त में खुदरा उपस्थिति बढ़ाने, नए तरीके से धन जुटाने और स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म की विनियामक कड़ी जांच में महत्वपूर्ण प्रगति की है। सामाजिक भलाई के लिए इक्विटी बाजारों की इस पारदर्शिता और कठोरता का लाभ उठाने के लिए, केंद्रीय बजट वित्त वर्ष 2020 में, सरकार ने सामाजिक कल्याण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करने वाले सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों को सूचीबद्ध करने के लिए सेबी के विनियामक दायरे में एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई) बनाने की दिशा में कदम उठाने का प्रस्ताव रखा, ताकि वे भारत में इक्विटी, ऋण के रूप में पूंजी जुटा सकें।

सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज की आवश्यकता: एसएसई का उद्देश्य सामाजिक-विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक निधि-उगाहने के साधन प्रदान करके वित्तपोषण अंतर को पाटना है। एसएसई मौजूदा स्टॉक एक्सचेंज का एक अलग खंड है, जो गैर-लाभकारी संगठनों (एनपीओ) और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) जैसे सामाजिक उद्यमों को स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से जनता से धन जुटाने में मदद कर सकता है। इस तरह, एसएसई से पारदर्शी और विनियमित वातावरण में भारत में परिणाम-संचालित लोक कल्याण के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है। एसएसई स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका सृजन आदि से संबंधित सामाजिक परियोजनाओं के क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों और अन्य उद्यमों के रचनात्मक जुड़ाव के लिए एक मंच भी प्रदान करता है, ताकि वे सीधे निजी क्षेत्र, कॉर्पोरेट संस्थाओं और व्यक्तियों (उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों (एचएनआई) सहित) से धन जुटा सकें और विकास लक्ष्यों में योगदान दे सकें। सामाजिक रूप से जिम्मेदार निवेशों के लिए बढ़ती वैश्विक भूख के साथ, एसएसई इस अंतर को पाटता है और विभिन्न सामाजिक कल्याण उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पूंजीगत बाजारों को जनता के करीब लाता है।

एसएसई का संचालन: एसएसई पर सूचीबद्ध सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए योगदान एक अनूठी सुरक्षा के माध्यम से किया जाता है, जिसे जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल (जेडसीजेडपी) साधन के रूप में जाना जाता है क्योंकि फंडिंग की प्रकृति दान के समान होती है और इस तरह, कूपन के भुगतान या मूल राशि की वापसी का वादा नहीं करती है। इस पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए, सरकार ने हाल ही में एसएसई पर जेडसीजेडपी के माध्यम से किए गए योगदान के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के तहत कर छूट को बढ़ा दिया है। एसएसई की एक और उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इस मंच पर धन उगाहना पात्र एनपीओ द्वारा शुरू की गई विशिष्ट परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है। इन एनपीओ को अपनी वर्ष-वार उपलब्धियां घोषित करने का आदेश दिया गया है, जिन्हें जनता से जुटाए गए धन से हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इस संबंध में, सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकता विनियम, 2018) व्यापक गतिविधियों की पहचान करना है जिनके लिए ये संस्थागत परियोजनाएं शुरू में जा सकती हैं, जैसे कि भूख, गरीबी, कुपोषण और असमानता का उन्मूलन; स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिए आजीविका को बढ़ावा देना; आपदा प्रबंधन; तथा पर्यावरणीय स्थिरता आदि।

एसएसई पर सूचीबद्ध होने के लिए, एनजीओ/एनपीओ को अपनी पिछली सामाजिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का खुलासा करना होगा, जिसमें सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए सिद्ध विशेषज्ञता और प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई हो। पात्रता मानदंड के रूप में, विनियामक ढांचे के लिए आवश्यक है कि एनजीओ/एनपीओ के पास सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं को क्रियान्वित करने का कम से कम तीन वर्ष का क्षेत्र अनुभव हो। इसके अलावा, फंड जुटाने वालों की फंड प्रदाताओं के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, एसएसई पर फंड जुटाने वाली

संस्थाओं को वित्तीय वर्ष के अंत से 90 दिनों के भीतर एक वार्षिक प्रभाव रिपोर्ट में अपने सामाजिक और पर्यावरणीय प्रदर्शन के बारे में विस्तृत जानकारी का खुलासा करना होगा, जिसका सोशल ऑडिट⁶⁰ द्वारा विधिवत ऑडिट किया गया हो। इस प्रकार, अपनी कठोरता, पारदर्शिता और जांच के माध्यम से, एसएसई प्लेटफॉर्म यह सुनिश्चित करता है कि दान विश्वसनीय संस्थाओं तक पहुँचे, पारिस्थितिकी तंत्र में विश्वास पैदा करे और जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इसकी मापनीयता का मार्ग प्रशस्त करे।

अब तक की प्रगति: सेबी द्वारा एसएसई के लिए विनियामक ढांचे के रोलआउट के बाद, एनएसई और बीएसई ने एसएसई का एक अलग खंड स्थापित करने के लिए सेबी की सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त की। अप्रैल 2024 तक, 51 एनपीओ बीएसई पर पंजीकृत हैं, और 50 (11 नवीनीकरण के दौर से गुजर रहे हैं) एनएसई पर पंजीकृत हैं। नौ एनपीओ ने एसएसई पर कुल ₹12.4 करोड़ की राशि जुटाई है। ये परियोजनाएँ शिक्षा, आजीविका सृजन, कौशल विकास आदि में सामाजिक परियोजनाओं तक फैली हुई हैं।⁶¹

जीआईएफटी आईएफएससी: भारत में वैश्विक पूंजीगत प्रवाह के लिए एक प्रमुख प्रवेशद्वार के रूप में उभर रहा है

2.87 गुजरात के जीआईएफटी सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) को भारत के अंदर स्थित एक अद्वितीय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्राधिकार के रूप में स्थापित किया गया है, जिसकी स्थापना भारत-केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा व्यवसाय को आँनशोर करने के साथ-साथ देश में और देश से बाहर वैश्विक पूंजीगत प्रवाह को चौनेलाइज करने के लिए एक पसंदीदा प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करने के दोहरे उद्देश्य से की गई है। पिछले कुछ वर्षों में, जीआईएफटी आईएफएससी ने इन दोनों उद्देश्यों को प्राप्त करने में बहुत प्रगति की है। जीआईएफटी आईएफएससी पहल वैश्विक वित्तीय सेवा व्यवसाय को आकर्षित करने और धीरे-धीरे अंतर्राष्ट्रीय वित्त में वैश्विक नेता बनने के लिए गहन, साहसिक और महत्वाकांक्षी वित्तीय क्षेत्र सुधार करने की भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता का एक शानदार उदाहरण है।

2.88 एक विशिष्ट और यादगार वित्तीय क्षेत्राधिकार के रूप में आईएफएससी की विशिष्टता तीन मूलभूत कारकों से उत्पन्न होती है। सबसे पहले, आईएफएससी को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत एक गैर-निवासी क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है, जिसका अर्थ है कि आईएफएससी में स्थापित संस्थाएँ पूंजी नियंत्रण प्रतिबंधों से बाहर हैं और इसलिए, ग्यारह अधिसूचित विदेशी मुद्राओं में से किसी में भी व्यवसाय कर सकती हैं।⁶² दूसरा, आईएफएससी को एक समर्पित और एकीकृत वित्तीय नियामक, अर्थात् आईएफएससी (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण) के विनियामक दायरे में लाया गया है, जिसे संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है। सरकार द्वारा किए गए इस विनियामक हस्तक्षेप ने वैश्विक निवेशकों और वित्तीय संस्थानों के बीच आईएफएससी के आकर्षण को काफी हद तक बढ़ा दिया है, क्योंकि अब उन्हें सभी अनुमोदनों और लाइसेंसों के लिए केवल एक प्राधिकरण से निपटना पड़ता है। तीसरा, लगातार केंद्रीय बजटों के माध्यम से, सरकार ने आईएफएससी के लिए एक अलग कर व्यवस्था प्रदान की है, जो अन्य प्रमुख वैश्विक वित्तीय केंद्रों में उपलब्ध कराये जाने वाले कर के बराबर है। प्रतिस्पर्धी कर व्यवस्था ने यह सुनिश्चित किया है कि आईएफएससी से संचालित वित्तीय सेवा संस्थान नुकसान में न रहें। जीआईएफटी आईएफएससी में कुछ प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियों को देखकर देश के वित्तीय उद्योग परिदृश्य को बदलने में जीआईएफटी आईएफएससी के योगदान को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है।⁶³

60 वित्तीय लेखा परीक्षक वित्तीय मामलों की स्थिति पर राय जारी करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वित्तीय विवरणों और लेन-देन का लेख करता है, जबकि सामाजिक लेखा परीक्षक संगठन द्वारा समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को देखता है, जिसमें पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक पहलू शामिल होते हैं। सेबी सामाजिक लेखा परीक्षक को भारतीय चार्टर्ड अकाउंट्स संस्थान (आईसीएआई) के दायरे में एक स्व-नियामक संगठन (एसआरओ) के साथ पंजीकृत व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है।

61 सेबी के अनुसार

62 अमेरिकी डॉलर (USD) यूरो (EUR) जापानी येन (JPY) यूके पाउंड स्टर्लिंग (GBP) कैंनेडियन डॉलर (CAD) ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (AUD) स्विस फ्रैंक (CHF) हांगकांग डॉलर (HKD) सिंगापुर डॉलर (SGD) यूएई दिरहम (AED) रूसी रूबल (आरयूबी)

63 डेटा जीआईएफटी सिटी से लिया गया है

2.89 **बैंकिंग क्षेत्र:** जीआईएफटी आईएफएससी में बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र विदेशी और घरेलू बैंकों के स्वस्थ मिश्रण के साथ तेजी से विकसित हो रहा है, जो मुख्य रूप से बाहरी वाणिज्यिक उधार, व्यापार वित्त आदि के माध्यम से भारतीय कारपोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की विदेशी मुद्रा उधार आवश्यकताओं को पूरा करता है। इन मदों के अंतर्गत पहले सिंगापुर, दुबई, हांगकांग आदि जैसे विदेशी वित्तीय केंद्रों से किए जाने वाले लेन-देन अब जीआईएफटी आईएफएससी से किए जा रहे हैं। मार्च 2024 तक, आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों (आईबीयू) की कुल संपत्ति का आकार 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया, और आईबीयू द्वारा किए गए लेन-देन का संचयी मूल्य 795 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया।

2.90 **फंड उद्योग:** जीआईएफटी आईएफएससी में मजबूत फंड उद्योग का स्टार्ट-अप इकोसिस्टम सहित भारत में वैश्विक पूंजी प्रवाह को उत्प्रेरित करने में परिवर्तनकारी प्रभाव है। पिछले तीन वर्षों में, आईएफएससी के साथ पंजीकृत फंड प्रबंधन संस्थाओं (एफएमई) और एआईएफ में तेजी से वृद्धि हुई है। मार्च 2024 तक, पंजीकृत संचयी एफएमई और फंड सितंबर 2022 तक 39 और 33 से बढ़कर मार्च 2024 तक क्रमशः 114 और 120 हो गए। पहले, भारत में निवेश के लिए अंतरराष्ट्रीय पूंजी की पूलिंग फंड (निजी इक्विटी) के माध्यम से संरचित की गई थी, उद्यम पूंजी, हेज फंड, आदि) अपतटीय क्षेत्राधिकार में स्थापित किए गए। अब, सक्षम नियमों, एक प्रतिस्पर्धी कर व्यवस्था और संचालन की लाभकारी लागत के साथ, लक्ष्य च्ये विदेशी और भारतीय फंड प्रबंधकों द्वारा वैश्विक पूंजी के पूलिंग के लिए एक पसंदीदा क्षेत्राधिकार के रूप में उभर रहा है।

2.91 **विमान और जहाज पट्टे और वित्तपोषण:** भारतीय विमानन उद्योग भारतीय एयरलाइनों द्वारा 1500 से अधिक विमानों के मजबूत ऑर्डर बुक और 2042 तक 2,200 से अधिक विमानों की अनुमानित मांग के साथ अभूतपूर्व वृद्धि के शिखर पर है, वर्तमान में, भारतीय एयरलाइनों द्वारा संचालित अधिकांश विमान अपतटीय पट्टेदारों से पट्टे पर लिए जाते हैं, जिनके पास प्रतिस्पर्धी पूंजीगत लागत तक पहुंच होती है। विमान पट्टे और वित्तपोषण व्यवसाय, विमानन मूल्य श्रृंखला में सबसे अधिक लाभदायक खंड, पूरी तरह से विदेशी अधिकार क्षेत्र में था। विमान पट्टे और वित्तपोषण व्यवसाय की अपार संभावनाओं को पहचानते हुए, आईएफएससी ने सक्षम पट्टे ढांचे की शुरुआत की, और सरकार ने कई कर प्रोत्साहन प्रदान करके इस प्रयास का समर्थन किया। तीन वर्षों में, आईएफएससी में वृद्धि दिखाई देने लगी है, 28 से अधिक विमान पट्टेदार पहले ही पंजीकृत हो चुके हैं, जिन्होंने वाणिज्यिक विमान, हेलीकॉप्टर, विमान इंजन और ग्राउंड सपोर्ट उपकरण सहित 120 से अधिक विमानन परिसंपत्तियों को पट्टे पर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि एयर इंडिया ने आईएफएससी जोन से अपने वाइड-बॉडी विमानों को पट्टे पर देना भी शुरू कर दिया है।

2.92 **समुद्री और शिपिंग उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, सरकार और आईएफएससी ने गिफ्ट आईएफएससी में एक मजबूत जहाज पट्टे और वित्तपोषण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।** प्रारंभिक फोकस उन भारतीय शिपिंग कंपनियों को वापस लाना है जो विदेशी अधिकार क्षेत्र से बाहर जहाजों को पट्टे पर/स्वामित्व में ले रही हैं। एक सक्षम नियामक ढांचे के साथ, जहाज पट्टे पर देने वाला पारिस्थितिकी तंत्र गति पकड़ रहा है। 31 मार्च 2024 तक, IFSC के साथ पंजीकृत जहाज पट्टे पर देने वाली कंपनियों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है, जो समुद्री व्यवसाय के लिए वित्तीय केंद्र की बढ़ती अपील को रेखांकित करती है। इसके अलावा, इन कंपनियों ने GIFT IFSC से चार संपत्तियां हासिल की हैं और पट्टे पर दी हैं। आगे बढ़ते हुए, IFSC एक जीवंत जहाज और विमान वित्तपोषण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने और परिसंपत्तियों के भारतीय स्वामित्व को बढ़ाने में योगदान देने के लिए IFSC बैंकिंग इकाइयों (IBU) के साथ काम करने का इरादा रखता है।

2.93 **विदेशी विश्वविद्यालयों की पहल:** आईएफएससी, एक अपतटीय क्षेत्राधिकार होने के नाते, भारत की प्रतिभा और जनसांख्यिकीय प्रोफाइल के कारण भारत में उत्सुकता से खोज करने वाले शीर्ष गुणवत्ता वाले वैश्विक विश्वविद्यालयों को आकर्षित करके एक 'अंतराष्ट्रीय उच्च शिक्षा केंद्र' बनने के लिए भी विशिष्ट रूप से स्थित है। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट वित्त वर्ष 23 में इस अवसर को रेखांकित किया, जिसमें कहा गया था कि 'विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को जीआईएफटी सिटी में वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में पाठ्यक्रम प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी, जो कि आईएफएससी द्वारा वित्तीय सेवाओं और प्रौद्योगिकी के

लिए उच्च-स्तरीय मानव संसाधनों की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने के लिए घरेलू नियमों से मुक्त होंगे।' इस प्रयास में, आईएफएससी ने वित्त वर्ष 24 में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जब ऑस्ट्रेलिया का डीकिन विश्वविद्यालय आईएफएससी (अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर और अपतटीय शिक्षा केंद्र की स्थापना और संचालन) विनियमन, 2022 के तहत जीआईएफटी आईएफएससी में अपने अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर के लिए अंतिम पंजीकरण प्राप्त करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया। इसके अतिरिक्त, ऑस्ट्रेलिया का वोलोंगोंग विश्वविद्यालय जीआईएफटी आईएफएससी में अपने अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त करने वाला दूसरा विदेशी विश्वविद्यालय बन गया। जीआईएफटी आईएफएससी में दो विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश ने अन्य विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के लिए इस अवसर को देखने और एक शिक्षित और कुशल भारत के उदय में योगदान करने का मार्ग प्रशस्त किया है।

2.94 वित्तीय सेवाओं के विकास और विनियमन के दोहरे अधिदेश को प्राप्त करने की दिशा में आईएफएससी को एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए कई सुधार चल रहे हैं। आईएफएससीए सर्वश्रेष्ठ-इन-क्लास तकनीक द्वारा समर्थित मजबूत विनियामक और पर्यवेक्षी प्रणालियों को लागू करने की प्रक्रिया में है। केंद्रीय बजट एफवाई 24 में की गई घोषणाएँ, जैसे पंजीकरण के लिए एकल खिड़की आईटी प्रणाली और दोहरे विनियमन से बचने के लिए आईएफएससीए को एसईजेड अधिनियम के तहत शक्तियाँ सौंपना, व्यापार करने में आसानी को बढ़ाएगा। आईएफएससी के देश में और देश से बाहर वैश्विक पूंजी प्रवाह के लिए एक पसंदीदा प्रवेश द्वार के रूप में उभरने की उम्मीद है।

बीमा क्षेत्र में विकास

वैश्विक बीमा बाजारों में नरमी

2.95 वैश्विक आर्थिक मंदी और मुद्रास्फीति ने बीमा कंपनियों के लिए चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं। अधिक मजबूत निवेश लाभ के साथ पूंजी की लागत बढ़ रही है। उच्च मुद्रास्फीति और कोविड-19 महामारी के वर्तमान और हाल के उतार-चढ़ाव के कारण अनुकूल विकास की लंबी अवधि के क्षीण होने के कारण रिजर्व पर्याप्तता एक महत्वपूर्ण विचार के रूप में उभरी है। एक बड़ा बफर होने के बावजूद, उद्योग रिजर्व रिलीज की गति धीमी हो गई है। मौजूदा माहौल में, कई अनिश्चितताएँ व्याप्त हैं, जैसे कि विलंबित निपटान, जो उच्च आर्थिक और सामाजिक मुद्रास्फीति की अवधि में एक अधिक महत्वपूर्ण समस्या के रूप में उभरता है। वस्तुओं से सेवाओं की ओर मुद्रास्फीति के बदलाव ने देयता जोखिमों को प्रभावित किया है। भविष्य में, मुद्रास्फीति के कम होने पर कम दावे और ब्याज दर-संवेदनशील निवेशों पर अधिक रिटर्न लाभप्रदता का समर्थन करने की उम्मीद है।

2.96 उपर्युक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए, वैश्विक बीमा बाजारों में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2022 में संकुचन देखा गया है। विश्व बीमा वर्ष 2023 पर स्विस् रे इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022 में कुल वैश्विक बीमा प्रीमियम⁶⁴ में वास्तविक रूप से 1.1 प्रतिशत की कमी आई है, जबकि वर्ष 2021 में इसमें 3.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। हालांकि, गैर-जीवन बीमा क्षेत्र में वर्ष 2022 में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, हालांकि यह वर्ष 2021 में दर्ज 2.6 प्रतिशत की वृद्धि से कम है, जो विकसित बाजारों में वाणिज्यिक लाइनों में दरों में सख्ती के कारण है। जीवन बीमा खंड में, वर्ष 2022 में वैश्विक प्रीमियम में 3.1 प्रतिशत की कमी आई, जबकि वर्ष 2021 में इसमें 4.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

भारत आने वाले दशक में सबसे तेजी से बढ़ते बीमा बाजारों में से एक के रूप में उभरने के लिए तैयार है

2.97 आर्थिक विकास, मध्यम वर्ग का विस्तार, नवाचार और विनियामक सहायता ने भारत में बीमा बाजार की वृद्धि को गति दी है। वित्त वर्ष 23 में, प्रीमियम वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ी कम हुई, जो कोविड-19 के बाद के युग में अभी भी प्रक्रियाधीन समायोजन को दर्शाती है। भारत में कुल बीमा निवेश⁶⁵ वित्त वर्ष 23 में थोड़ी कम होकर 4 प्रतिशत हो गई, जो वित्त वर्ष 22 में 4.2 प्रतिशत था। इसी अवधि के दौरान, जीवन बीमा खंड में बीमा निवेश वित्त वर्ष

64 स्विस् रे इंस्टीट्यूट रिपोर्ट, विश्व बीमा बाजार 2023, <https://t.ly/64ENQ>

65 बीमा प्रवेश से तात्पर्य किसी विशेष वर्ष में लिखे गए बीमा प्रीमियम और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात से है

22 में 3.2 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 23 में 3 प्रतिशत हों गया, जबकि गैर-जीवन बीमा खंड के लिए यह 1 प्रतिशत पर स्थिर रहा। कुल बीमा घनत्व⁶⁶ वित्त वर्ष 22 में 91 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 23 में 92 अमेरिकी डॉलर हो गया। जीवन बीमा खंड में, यह वित्त वर्ष 22 में 69 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 23 में 70 अमेरिकी डॉलर हो गया और गैर-जीवन बीमा खंड में स्थिर रहा।⁶⁷

2.98 स्विस री इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट⁶⁸ के अनुसार, भारत में जीवन बीमा प्रीमियम की वृद्धि वित्त वर्ष 23 में 4.1 प्रतिशत (2012-2021 के दौरान 3.2 प्रतिशत के ऐतिहासिक औसत से अधिक) धीमी होने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 22 में 5.9 प्रतिशत थी, क्योंकि महामारी की यादें (अर्थात् जोखिम जागरूकता) कम हो गई हैं और हाई⁶⁹-टिकट पॉलिसियों के लिए कर मानदंडों में हाल ही में हुए बदलाव ने नए प्रीमियम की वृद्धि को प्रभावित किया है। इन कारकों के कारण, वित्त वर्ष 22 की पहली तिमाही में 40 प्रतिशत की वृद्धि के बाद, नए व्यवसाय प्रीमियम चौथी तिमाही (7 प्रतिशत) में सिकुड़ गए। यह गति वित्त वर्ष 23 में भी जारी रही, जिसमें दूसरी तिमाही में नए व्यवसाय प्रीमियम में 21.2 प्रतिशत की गिरावट आई, जिसका मुख्य कारण समूह बीमा व्यवसाय में संकुचन था।

गैर-जीवन बीमा खंड की स्थिति

2.99 महामारी के बाद बाजार के स्थिर होने के कारण गैर-जीवन प्रीमियम वृद्धि वित्त वर्ष 22 में 9 प्रतिशत से थोड़ी कम होकर वित्त वर्ष 23 में अनुमानित 7.7 प्रतिशत हो गई (2012-2021 के दौरान 8 प्रतिशत के ऐतिहासिक औसत से कम)। महामारी के बाद उद्योग के स्थिर होने के कारण पिछले साल लगभग सभी प्रकार के व्यवसायों में वृद्धि धीमी हो गई। इस क्षेत्र को आर्थिक मंदी, उच्च ब्याज दरों और उच्च खुदरा और चिकित्सा मुद्रास्फीति जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

2.100 वित्त वर्ष 23 में दर्ज किए गए सेक्टर प्रीमियम में स्वास्थ्य का हिस्सा करीब 35 प्रतिशत है। प्रीमियम में 11 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि के साथ, वित्त वर्ष 23 में सभी गैर-जीवन रेखाओं में स्वास्थ्य ने सबसे तेज वृद्धि देखी। स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता, सहायक सरकारी नीतियाँ, बढ़ती चिकित्सा लागत और इंश्योरटेक में नवाचारों ने इस वृद्धि का समर्थन किया है। हालाँकि कीमत और आय की बाधाएँ निम्न आय समूहों के लिए माँग को सीमित कर सकती हैं, लेकिन मध्यम वर्ग का विस्तार और विवेकाधीन खर्च में वृद्धि से समग्र वृद्धि को समर्थन मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, कम आय वाले परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) और राज्य सरकार की विस्तार योजनाएँ लागू हैं। हाल ही में, बी-पीएमजेएवाई ने पूरे भारत में 34.2 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने का मुकाम हासिल किया, जिनमें से 49.3 प्रतिशत कार्डधारक महिलाएँ हैं। मध्यम अवधि में, बीमा के आकर्षण को बेहतर बनाने के लिए नियामक पहलों से कुछ सहायता मिलने के साथ, 2024-28 में स्वास्थ्य प्रीमियम में सालाना 9.7 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

2.101 कृषि बीमा एक अन्य व्यवसाय है, जो गैर-जीवन बीमा बाजार का लगभग 12 प्रतिशत है। खरीफ फसल सीजन में प्रीमियम दरों में भारी गिरावट के कारण वित्त वर्ष 23 में कृषि बीमा में एकसमान वृद्धि दर्ज होने का अनुमान है। इस गिरावट की भरपाई मौसम के दौरान बीमित भूमि क्षेत्र और किसानों के नामांकन में वृद्धि से हुई। वर्ष 2024 के बाद से कृषि प्रीमियम में वृद्धि होने की संभावना है, जिसमें मध्यम अवधि में 2.5 प्रतिशत की औसत वास्तविक प्रीमियम वृद्धि होगी, जिसे फसल हानि की निगरानी के लिए मोबाइल एप्लिकेशन और रिमोट सेंसिंग जैसे बीमा अवसरनचा में सुधार द्वारा समर्थित किया जाएगा। सरकार ने फसल बीमा से जुड़ी मौजूदा चिंताओं को दूर करने के लिए कई पहल शुरू की हैं। इनमें उपग्रह आधारित उन्नत तकनीकों के माध्यम से फसल क्षति का आकलन करने के लिए वाईएस-टेक मैनुअल, डब्ल्यूआईएनडीएस पोर्टल और नामांकन ऐप एआईडीई/सहायक जैसी नई तकनीकी पहलों की शुरुआत और घर-घर जाकर नामांकन पहल के साथ कवर को और अधिक सुलभ बनाना शामिल है।

66 बीमा घनत्व से तात्पर्य जनसंख्या के प्रति बीमा प्रीमियम के अनुपात से है, अर्थात् प्रति व्यक्ति बीमा प्रीमियम और इसे अमेरिकी डॉलर में मापा जाता है।

67 स्विस री इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट, 'भारत का बीमा बाजार: लचीलापन बनाने की पर्याप्त गुंजाइश के साथ तेजी से बढ़ रहा है', <https://t.ly/tagPh>

68 वही

69 इस विनियमन के तहत, 5 लाख रुपये से अधिक वार्षिक प्रीमियम वाली जीवन बीमा पॉलिसी से प्राप्त कोई भी आय कराधान के अधीन है। परिणामस्वरूप, आयकर अधिनियम की धारा 10(10), जो पहले छूट प्रदान करती थी, अब इस सीमा से अधिक प्रीमियम वाली पॉलिसियों पर लागू नहीं होती है।

2.102 सरकार और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने उद्योग के विकास को सहायता देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है नवंबर 2022 में शुरू किया गया मिशन “2047 तक सभी के लिए बीमा”, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक नागरिक और उद्यम के पास उचित बीमा कवर/समाधान हो। बीमा पैठ बढ़ाने के लिए तीन प्रमुख पहल, बीमा सुगम⁷⁰, बीमा वाहक⁷¹ और बीमा वाहक⁷² एक महिला-केंद्रित बीमा वितरण चैनल है और बीमा विस्तार शुरू की गई हैं, खासकर अर्ध-शहरी क्षेत्रों, ग्रामीण कस्बों और गांवों में।

2.103 आईआरडीएआई ने भारत को वैश्विक पुनर्बीमा केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए पुनर्बीमा विनियमों में संशोधन को मंजूरी दी। मूलभूत परिवर्तनों में विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं (एफआरबी) की न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को 12.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर से घटाकर 6.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर करना और भारतीय बीमाकर्ताओं द्वारा पुनर्बीमाकर्ताओं को रियायत के लिए विनियामक के वरीयता क्रम को छह स्तरों से चार तक सुव्यवस्थित करना शामिल है। पुनर्बीमा प्रारूपों को सरल बनाया गया है, और बेहतर प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालयों (आईआईओ) के ढांचे को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) के नियमों के साथ जोड़ा गया है।

2.104 एक व्यापक विनियामक समीक्षा की गई है, जिसमें नियम-आधारित दृष्टिकोण से सिद्धांत-आधारित वास्तुकला में परिवर्तन करते हुए एक तन्यक और मजबूत जोखिम प्रबंधन ढांचा स्थापित किया गया है। परिचालन को सुव्यवस्थित करते हुए, 167 परिपत्रों और 82 लाभ को निरस्त कर दिया गया है, जबकि 78 विनियमों को संशोधित, समेकित और घटाकर 28 कर दिया गया है। बीमा उत्पादों के लिए विनियामक मंजूरी प्रक्रियाओं को भी 'फाइल और उपयोग' व्यवस्था के तहत पूर्व अनुमोदन की पूर्ववर्ती आवश्यकता से बदल दिया गया है, जिसमें सामान्य और स्वास्थ्य बीमा के तहत सभी उत्पादों और अधिकांश जीवन बीमा उत्पादों के लिए श्रुपयोग और फाइल प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है, जो बीमाकर्ताओं को बाजार की गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए उत्पादों को जल्दी से लॉन्च करने की सुविधा प्रदान करता है।

2.105 सभी खंडों के अंतर्गत उत्पाद पेशकशों के लिए विभिन्न विनियामक शर्तें भी हटा दी गई हैं, जिसमें स्वास्थ्य बीमा खंड पर ध्यान केंद्रित किया गया है ताकि ग्राहकों को बेहतर कवरेज और विकल्प प्रदान किया जा सके। इसके अलावा, पॉलिसीधारकों को उनके बीमा कवरेज की गहन समझ प्रदान करने के लिए, सभी प्रकार की बीमा पॉलिसियों के लिए पॉलिसीधारकों को संक्षिप्त ग्राहक सूचना पत्र (सीआईएस) जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है।

2.106 इसके अलावा, उद्योग को भविष्य के लिए तैयार करने और वैश्विक मानकों के साथ संरेखित करने के लिए, जोखिम-आधारित पर्यवेक्षी ढांचे (आरबीएसएफ), जोखिम-आधारित पूंजीगत ढांचे (आरबीसी) और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के कार्यान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आईआरडीएआई राज्य बीमा योजनाओं के माध्यम से बीमा कंपनियों और राज्य सरकारों के बीच समन्वित प्रयासों की सुविधा प्रदान करता है ताकि बीमा सेवाओं को देश के अंतिम छोर और यहां तक कि सबसे दूरदराज के इलाकों तक पहुंचाया जा सके।

2.107 इन सुधारों और सतत आर्थिक वृद्धि से बीमा क्षेत्र के निरंतर विकास और उन्नति में मदद मिलने की उम्मीद है, जिसे मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते मध्यम वर्ग, नवाचार और मजबूत नीतिगत सहायता से समर्थन मिलेगा। भारतीय बीमा बाजार के लिए अनुकूल अनुमान हैं। स्विस-री इंस्टीट्यूट की जनवरी 2024 की रिपोर्ट⁷³ में अनुमान लगाया गया है कि अगले पांच वर्षों (2024-28) में भारत में कुल बीमा प्रीमियम वास्तविक रूप से 7.1 प्रतिशत बढ़ेगा, जो वैश्विक (2.4 प्रतिशत), उभरती अर्थव्यवस्थाओं (5.1 प्रतिशत) और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (1.7 प्रतिशत) के बाजार औसत से काफी अधिक है। इस दर पर, भारत में जी20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाला बीमा क्षेत्र होगा। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में बीमा निवेश वित्त वर्ष 23 में 3.8 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 35 तक 4.3 प्रतिशत होने का

70 “बीमा सुगम” एक ऑनलाइन पोर्टल है जो बीमा खरीदने, पोर्टेबिलिटी सुविधाओं, बीमा एजेंटों को बदलने की क्षमता और बीमाकर्ताओं के साथ प्रत्यक्ष रूप से जीवन, मोटर और स्वास्थ्य दावों के निपटान की सुविधा प्रदान करता है।

71 “बीमा वाहक” एक महिला-केंद्रित बीमा वितरण चैनल है

72 ‘बीमा विस्तार’ एक सामाजिक सुरक्षा जाल है जो बीमा सुगम मंच के माध्यम से सभी के लिए सुलभ है

73 <https://tinyurl.com/mryvwjgm>

अनुमान है। जीवन व्यवसाय में वृद्धि (2024-28 में प्रीमियम में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि) मध्यम वर्ग द्वारा टर्म लाइफ कवर की बढ़ती मांग, देश की युवा आबादी और इश्योरटेक को उद्योग द्वारा अपनाए जाने से समर्थित होने की संभावना है। आर्थिक विकास, वितरण चैनलों में सुधार, सरकारी सहायता और अनुकूल विनियामक वातावरण के कारण गैर-जीवन प्रीमियम में 2024-28 के दौरान वार्षिक औसत 8.3 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। इसके अलावा, अगले दशक (2024-34) में कुल प्रीमियम दोगुने से अधिक (मुद्रास्फीति-समायोजित) होने की उम्मीद है, और बीमा प्रवेश वर्तमान 3.8 प्रतिशत से बढ़कर 2034 में 4.5 प्रतिशत हो जाएगा।

2.108 बीमा निवेश में अपेक्षित वृद्धि को साकार करने के लिए, उद्योग को अधिक ग्राहक-अनुकूल बनना होगा। वित्त वर्ष 23 के लिए आईआरडीएआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार⁷⁴, केंद्रीकृत शिकायत पोर्टल को वर्ष के दौरान दो लाख से अधिक शिकायतें मिलीं। यदि हम भारतीय जीवन बीमा निगम को छोड़ दें, तो जीवन बीमा कंपनियों के खिलाफ 50 प्रतिशत से अधिक शिकायतें अनुचित व्यावसायिक कार्यप्रणालियों के बारे में थीं, जो गलत बिक्री के लिए एक व्यंजना है। इसके अलावा, सामान्य बीमा कंपनियों के खिलाफ 66 प्रतिशत शिकायतें दावों के बारे में थीं, जिसमें विलंबित और अस्वीकृत निपटान शामिल थे। उद्योग को लंबी अवधि के लिए सोचना और काम करना होगा। बीमा निवेश नहीं बढ़ेगी। वित्त वर्ष 23 के आंकड़ों से बीमा निवेश में गिरावट देखी गई। जब वित्तीय उत्पादों की बात आती है, तो वैश्विक स्तर पर, शॉप्ट-टच विनियमन ग्राहक संतुष्टि और पैसे के लिए मूल्य⁷⁵ प्रदान करने में निरंतर अवधि में शायद ही कभी काम करते हैं। वैश्विक स्तर पर, निजी वित्तीय क्षेत्र ने बार-बार खुद को अपने लाभ के लिए सिद्धांत-आधारित विनियमों की चुनिंदा या गलत व्याख्या करने में माहिर दिखाया है।

पेंशन क्षेत्र में विकास

2.109 अधिकांश देशों की जनसांख्यिकीय संरचना में काफी बदलाव आ रहा है क्योंकि जन्म दर में गिरावट जारी है। इस विकास का पे-एज-यू-गो पेंशन व्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जो पिछली पीढ़ियों को प्रदत्त पेंशन को निधि देने के लिए करदाताओं की अगली पीढ़ी पर निर्भर करता है। हाल के दिनों में, मुद्रास्फीति के फिर से उभरने से भी समुदाय के इस विश्वास को नुकसान पहुंचा है कि पेंशन कार्यक्रम लंबी अवधि में पर्याप्त सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। हालाँकि कुछ अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति में कमी आई है, लेकिन इसके बने रहने से वर्तमान और भविष्य के सेवानिवृत्त लोगों के लिए यह जोखिम उजागर हुआ है। साथ ही, परिभाषित लाभ से परिभाषित योगदान व्यवस्था की ओर वैश्विक बदलाव जारी है, जिसमें व्यक्ति निवेश लाभ, मुद्रास्फीति और अक्सर, दीर्घायु से संबंधित सभी जोखिम उठाते हैं। बहुत कम प्रणालियों ने व्यक्ति-आधारित डीसी संचय प्रणाली से सेवानिवृत्ति के बाद की प्रणाली में जाने की दुविधा को हल किया है जो सेवानिवृत्त लोगों को पर्याप्त और सुरक्षित आय प्रदान करते हुए उन्हें उनके कार्य वर्षों के दौरान उपलब्ध समान लचीलापन प्रदान करती है।

2.110 कई पेंशन प्रणालियों के सामने एक चुनौती यह है कि गिग वर्कर्स और अनौपचारिक श्रम बाजार में शामिल लोगों को शामिल किया जाए। कई अर्थव्यवस्थाओं में, श्रम बाजार में दरार पड़ रही है; इसलिए, स्थिर या संरचित नियोक्ता-कर्मचारी संबंध गायब हो रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में, पेंशन व्यवस्था को अधिक व्यक्तिगत रूप से केंद्रित और तीसरे पक्ष पर कम निर्भर होना चाहिए।⁷⁶

भारत के पेंशन क्षेत्र का प्रदर्शन

2.111 15वें वार्षिक मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स (एमसीजीपीआई)⁷⁷ के अनुसार, भारत का समग्र वैश्विक पेंशन सूचकांक मूल्य 2022 के 44.5 से बढ़कर 2023 में 45.9 हो गया, जिसका मुख्य कारण पर्याप्तता और

74 <https://tinyurl.com/98vs72dc>

75 'बीमा उद्योग को नियामकीय बदलाव की जरूरत है', बिजनेस लाइन, 10 फरवरी 2024 (<https://www.thehindubusinessline.com/opinion/insurance-industry-needs-a-regulatory-shake-up/article67829954.ece>)

76 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, 'दुनिया भर में गैर-मानक रोजगार: चुनौतियों को समझना, संभावनाओं को आकार देना', <https://tinyurl.com/3uah4a4n>

77 मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स दुनिया भर में 47 रिटायरमेंट आय प्रणालियों का मूल्यांकन करता है, जिसमें प्रत्येक के भीतर चुनौतियों और अवसरों पर प्रकाश डाला जाता है। यह सूचकांक तीन उप-सूचकांकों, पर्याप्तता, स्थिरता और अखंडता से बना है जो प्रत्येक रिटायरमेंट आय प्रणाली को 50 से अधिक संकेतकों के आधार पर मापता है

स्थिरता उप-सूचकांक में सुधार है। भारत की पेंशन प्रणाली में आय-संबंधित कर्मचारी पेंशन योजना, एक निर्धारित अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और पूरक नियोक्ता-प्रबंधित पेंशन योजनाएं शामिल हैं जो अनिवार्य रूप से निर्धारित अंशदान के माध्यम से हैं। सरकार ने असंगठित क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। कार्यबल की गतिशीलता, रोजगार और पारिवारिक पैटर्न में बदलाव ने सेवानिवृत्ति के औपचारिक स्रोतों को सामने ला दिया है। जबकि निवल पेंशन प्रतिस्थापन दर और निजी पेंशन योजनाओं में भागीदारी में सुधार हुआ है, जो पर्याप्त और सधारणीयता उप-सूचकांकों के मूल्य में परिलक्षित होता है, निजी पेंशन योजनाओं के तहत भारतीय कार्यबल का कवरेज अभी बढ़ाया⁷⁸ जाना है। सरकार ने असंगठित क्षेत्र के लाभ के लिए सर्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के भाग के रूप में विभिन्न योजनाएं आरंभ की हैं।

2.112 राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) और हाल ही में अटल पेंशन योजना (एपीवाई) की शुरुआत के बाद से भारत के पेंशन क्षेत्र का विस्तार हुआ है। मार्च 2024 तक कुल ग्राहकों की संख्या 735.6 लाख थी, जो मार्च 2023 तक 623.6 लाख से 18 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज करती है। संख्या के लिहाज से, इसमें एपीवाई का दबदबा है। एपीवाई ग्राहकों (इसके पुराने संस्करण, एनपीएस लाइट सहित) की कुल संख्या मार्च 2023 तक 501.2 लाख से बढ़कर मार्च 2024 तक 588.4 लाख हो गई। एपीवाई ग्राहक पेंशन ग्राहक आधार का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा है।⁷⁹

2.113 पेंशन फंड विनियामक प्राधिकरण (पीएफआरडीए) कि अलग-अलग डेटा से पता चलता है कि एपीवाई ग्राहकों ने जेंडर मिक्स में सुधार देखा है, जिसमें महिला ग्राहकों की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 17 में 37.2 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 23 में 48.5 प्रतिशत हो गई है। 18-25 आयु वर्ग के युवा समूह के पक्ष में आयु मिश्रण भी बढ़ रहा है, जो वित्त वर्ष 17 में 35 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 23 में 46.7 प्रतिशत हो गया है। हालांकि, एपीवाई खातों का बड़ा हिस्सा, लगभग 92 प्रतिशत, ₹1,000 प्रति माह की पेंशन राशि के लिए था, इसके बाद 4.7 प्रतिशत ₹5,000 के लिए थे, और शेष 3 प्रतिशत बीच में थे। एपीवाई में ₹1,000 पेंशन का भारी हिस्सा कई कारकों के कारण हो सकता है, प्रमुख कारण यह है कि लक्षित आबादी निम्न आय वाले परिवार हैं, जहां दिन-प्रतिदिन के उपभोग व्यय को बचत⁸⁰ पर प्राथमिकता दी जाती है।

2.114 इन दो योजनाओं (एनपीएस और एपीवाई) के तहत कुल आबादी के हिस्से के रूप में आबादी की पेंशन कवरेज वित्त वर्ष 17 में 1.2 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 5.3 प्रतिशत हो गई है। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में एयूएम वित्त वर्ष 17 में 1.1 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 4 प्रतिशत हो गया है।

पेंशन क्षेत्र के लिए संभावना

2.115 भविष्य में, एनपीएस (निजी क्षेत्र) का तेजी से विस्तार होने की संभावना है क्योंकि कारपोरेट कर्मचारियों और अपेक्षाकृत बेहतर परिवारों की बढ़ती संख्या, उदाहरण के लिए, स्व-रोजगार और पेशेवर जैसे डॉक्टर, वकील और छोटे व्यवसाय के मालिक, एनपीएस में शामिल होने के लाभ को देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े किसानों, व्यापारियों और एकमुश्त आय वाले लोगों के लिए एनपीएस की संभावना है, क्योंकि एनपीएस के लिए मानक मासिक योगदान की आवश्यकता नहीं होती है।

2.116 भारत की प्रति व्यक्ति आय में और वृद्धि होने तथा उच्च-मध्यम आय वाले देश में तब्दील होने के कारण विकास की अपार संभावनाएं हैं। भारत की जनसांख्यिकी संरचना, जिसमें युवा लोगों का अनुपात अधिक है, संचय के चरण का पक्षधर है। चूंकि जीवन प्रत्याशा धीरे-धीरे बढ़ रही है, इसलिए वृद्धावस्था में गरीबी को कम करने के लिए एक स्थिर आय स्रोत की आवश्यकता भी बढ़ रही है। इसके अलावा, जैसे-जैसे बढ़ते शहरीकरण के साथ पारंपरिक पारिवारिक सहायता प्रणाली बदलती है, वृद्धावस्था में आय के एक स्वतंत्र स्रोत की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ जाती है।

2.117 औपचारिक वित्तीय क्षेत्र का लाभ उठाने के लिए लोगों के लिए वित्तीय साक्षरता आवश्यक हो जाती है। पेंशन साक्षरता के कई पहलू हैं; परिवार में महिलाओं के पास उनकी लंबी आयु को देखते हुए पेंशन खाता होना चाहिए; युवा

78 15वीं वार्षिक एमसीजीपीआई के अनुसार, वर्तमान में भारतीय कार्यबल का 6 प्रतिशत हिस्सा निजी पेंशन योजनाओं के अंतर्गत आता है।

79 <https://www.pfrda.org.in>

80 पीएफआरडीए का मासिक पेंशन बुलेटिन, <https://www.pfrda.org.in>

वयस्कों, विशेष रूप से छात्रों को पेंशन खाते के साथ सशक्त बनाना समझदारी है ताकि वे दीर्घकालिक बचत के वित्तीय अनुशासन को आत्मसात कर सकें।

2.118 वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण तभी पूरा होगा जब परिवार के प्रत्येक सदस्य का पेंशन खाता होगा। इस दिशा में, पेंशन उत्पाद की प्रकृति को देखते हुए, जहाँ भुगतान तत्काल नहीं होता है, सभी संबंधित पक्षों, नियोक्ताओं, मध्यवर्ती संस्थाएं, सरकार और पेंशन नियामक को लोगों, विशेष रूप से युवा वयस्कों को पेंशन योजना में शामिल होने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। इसमें शामिल होने का बहुत फायदा है क्योंकि छोटे-छोटे योगदानों से, चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति के कारण एक बड़ी राशि जमा की जा सकती है, जो किसी व्यक्ति के काम के बाद के जीवन में पर्याप्त स्थिर आय प्रदान करती है।

विनियामक समन्वय और समग्र वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए तंत्र

2.119 वित्तीय प्रणाली की स्थिरता सतत आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए सर्वोपरि है। वित्तीय रूप से स्थिर प्रणाली को वृष्ट आर्थिक गड़बड़ी के प्रति मजबूत होना चाहिए। इसे अप्रत्याशित झटकों का सामना करना चाहिए ताकि इस बात का अत्यधिक विश्वास हो कि यह अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करना जारी रखेगी। वित्तीय स्थिरता का अर्थ न केवल वास्तविक संकट की अनुपस्थिति है, बल्कि असंतुलन को सीमित करने और प्रबंधित करने की प्रणाली की क्षमता भी है, इससे पहले कि वे उस परिमाण को ग्रहण करें जो स्वयं या आर्थिक प्रक्रियाओं को खतरे में डालता है।

2.120 वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में सरकार की भूमिका बहुआयामी और महत्वपूर्ण है। दुनिया भर की सरकारें वित्तीय क्षेत्र की अखंडता और सुचारू कामकाज की रक्षा के लिए विभिन्न नीतियों, विनियमों और उपायों को लागू करती हैं। यह आकलन करना भी आवश्यक होगा कि वित्तीय अस्थिरता और वास्तविक अर्थव्यवस्था के बीच कैसे तालमेल स्थापित होता है ताकि शुरुआती झटकों के प्रभावों को बढ़ाया या कम किया जा सके। इस प्रकार, विभिन्न वित्तीय संस्थानों की निगरानी के लिए जिम्मेदार नियामकों को आपस में और कीमतों और वास्तविक अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ निकटता से बातचीत और सहयोग करना चाहिए।

2.121 भारतीय संदर्भ में, एफएसडीसी⁸¹ एक ऐसा मंच है जो विभिन्न वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के बीच बातचीत को सुगम बनाता है। एफएसडीसी को वित्तीय स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र के विकास, अंतर-विनियामक समन्वय, वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन, अर्थव्यवस्था के मैक्रो-विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण, जिसमें बड़े वित्तीय समूहों का कामकाज शामिल है, वित्तीय क्षेत्र के निकायों (जैसे वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ), वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) के साथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय इंटरफेस का समन्वय और किसी सदस्य/अध्यक्ष द्वारा संदर्भित और परिषद द्वारा विवेकपूर्ण माने जाने वाले वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता और विकास से संबंधित किसी भी अन्य मामले से संबंधित व्यापक मुद्दों से निपटने का अधिकार है।

2.122 आरबीआई गवर्नर एफएसडीसी उप-समिति (एफएसडीसी-एससी) बैठकों की अध्यक्षता भी करते हैं, जो एफएसडीसी-एससी के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तावित एजेंडा मदों के साथ-साथ आवश्यक सहायक कार्यों पर विचार-विमर्श करते हैं। आरबीआई वित्तीय संस्थानों को विनियमित करके, प्रणालीगत जोखिमों की निगरानी करके और मौद्रिक नीति को लागू करके वित्तीय क्षेत्र की तन्यकटा को बढ़ावा देता है। वित्तीय स्थिरता और भारतीय वित्तीय प्रणाली की मजबूती के लिए जोखिमों का सामूहिक मूल्यांकन किया जाता है और मार्च 2010 से आरबीआई द्वारा प्रकाशित द्वि-वार्षिक वित्तीय⁸² स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) में इसकी रिपोर्ट दी जाती है।

भारत के लिए वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी)

2.123 एफएसएपी 'प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण' वित्तीय क्षेत्रों वाले देशों में आईएमएफ और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप

81 वित्त मंत्री एफएसडीसी की अध्यक्षता करते हैं। इसके सदस्य हैं वित्त राज्य मंत्री, अन्य सभी वित्तीय क्षेत्र विनियामक निकायों (जैसे, आरबीआई, एसबीआई, आईआरडीआई, पीएफआरडीए, आईएफएससीए) के प्रमुख, (i) आर्थिक कार्य, (ii) व्यय, (iii) वित्तीय सेवाएँ, (iv) राजस्व, (v) कारपोरेट कार्य के मंत्रालय और (vi) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विभागों के सचिव और वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार। वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य के विभाग का वित्तीय स्थिरता और साइबर सुरक्षा प्रभाग परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करता है, और प्रभाग का प्रमुख परिषद का सदस्य सचिव होता है।

82 आरबीआई वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट दिसंबर 2023, <https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=1248>

से आयोजित एक पंचवार्षिक अभ्यास है। एफएसएपी में वित्तीय स्थिरता और वित्तीय क्षेत्र के विकास का आकलन करने के लिए देश के वित्तीय उद्योग का व्यापक और गहन विश्लेषण शामिल है। भारत ने अपना पहला एफएसएपी अभ्यास 2011-12 में और दूसरा 2017 में किया, जिसके बाद आईएमएफ-विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें वित्तीय प्रणाली स्थिरता आकलन रिपोर्ट (एफएसएसए) और वित्तीय क्षेत्र आकलन (एफएसए) रिपोर्ट शामिल थी। भारत के लिए तीसरा एफएसएपी अभ्यास 2023-24 के लिए चल रहा है। एफएसएसए और एफएसए रिपोर्ट फरवरी 2025 तक प्रकाशित की जाएंगी। एफएसबी जी20 वित्तीय नियामक सुधारों के कार्यान्वयन और प्रभावों पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट⁸³ प्रकाशित करता है, जिसमें विभिन्न न्यायालयों में कार्यान्वयन की स्थिति का उल्लेख होता है। रिपोर्ट में रंग-कोडित टेम्पलेट एफएसबी सिद्धांतों और मानकों के क्षेत्रीय कार्यान्वयन की सीमा पर प्रकाश डालता है। निगरानी किए गए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में (i) बेसल-प्स सुधार, (ii) मुआवजा, (iii) ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) डेरिवेटिव, (iv) रिजॉल्यूशन, और (v) गैर-बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थता (एनबीएफआई) शामिल हैं।

2.124 बेसल III⁸⁴ सुधारों के कार्यान्वयन ने घरेलू और वैश्विक बैंकिंग दोनों क्षेत्रों में लचीलेपन का समर्थन किया है। बेसल प्स स्तंभ सुधारों के तहत, भारत काफी हद तक अनुपालन कर रहा है क्योंकि इसने अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नेट स्थिर फंडिंग अनुपात, तरलता कवरेज अनुपात, व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों के लिए आवश्यकताएं और बैंक के बड़े एक्सपोजर को मापने और नियंत्रित करने के लिए पर्यवेक्षी ढांचे के प्रावधान निर्धारित किए हैं। भारत बेसल प्स के तहत अन्य दो आवश्यकताओं, यानी संशोधित उत्तोलन अनुपात आवश्यकताओं और जोखिम-आधारित पूंजी ढांचे को भी लागू करने की प्रक्रिया में है।

2.125 मुआवजे के स्तंभ के लिए, भारत में पहले से ही महत्वपूर्ण बैंकों, बीमाकर्ताओं और परिसंपत्ति प्रबंधकों के लिए ठोस मुआवजा प्रथाओं (सिद्धांत और मानक) के लिए मानक मौजूद हैं।

2.126 ओटीसी डेरिवेटिव खंड के तहत, भारत ने 2022 एफएसबी मूल्यांकन से 2023 में महत्वपूर्ण प्रगति की, क्योंकि 90 प्रतिशत से अधिक ओटीसी डेरिवेटिव अब एफएसबी सिद्धांतों के तहत व्यापार रिपोर्टिंग, केंद्रीय समाशोधन और प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग आवश्यकताओं का पालन करते हैं। ओटीसी स्तंभ के तहत चौथा पैरामीटर, यानी ओटीसी डेरिवेटिव से संबंधित मार्जिन आवश्यकताएं, वर्तमान में कार्यान्वयन के अधीन हैं।

2.127 एनबीएफआई की लचीलापन बढ़ाना एफएसबी की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है, जो प्रमुख सुधार क्षेत्र के तहत मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, प्रतिभूतिकरण और सिक्वोरिटीज फाइनेंसिंग लेनदेन (एसएफटी) आवश्यकताओं के तहत रखी गई है। संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए न्यूनतम नियामक मानकों, बैंक-से-गैर-बैंक लेनदेन पर संख्यात्मक हेयरकट फर्श आदि सहित एसएफटी आवश्यकताओं के कुल अनुपालन में एफएसबी द्वारा रिपोर्ट किए गए 24 में से भारत एकमात्र क्षेत्राधिकार है। भारत ने सक्रिय रूप से प्रतिभूतिकरण और एमएमएफ सुधार किए हैं। एफएसबी सिद्धांतों के अनुरूप।

वित्तीय प्रणाली दबाव सूचक

2.128 आरबीआई ने अपने एफसीआर⁸⁵ के 26वें अंक में भारतीय वित्तीय प्रणाली में समग्र दबाव स्तर की निगरानी के लिए वित्तीय प्रणाली तनाव संकेतक (एफएसएसआई)⁸⁶ नामक एक व्यापक संकेतक संकलित करने का प्रयास किया। एफएसएसआई का उद्देश्य (क) दबाव की अवधि की पहचान करने में मदद करना, (ख) वित्तीय प्रणाली में तनाव की

83 2023 वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) की वार्षिक रिपोर्ट, 11 अक्टूबर 2023, 'वैश्विक वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना', <https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P111023.pdf>

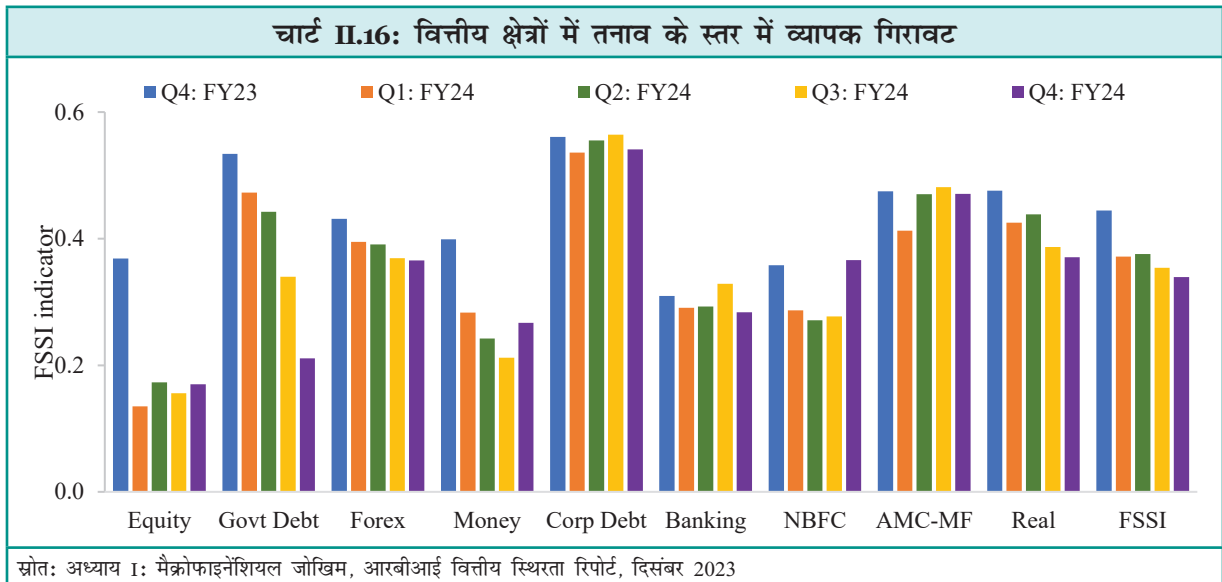
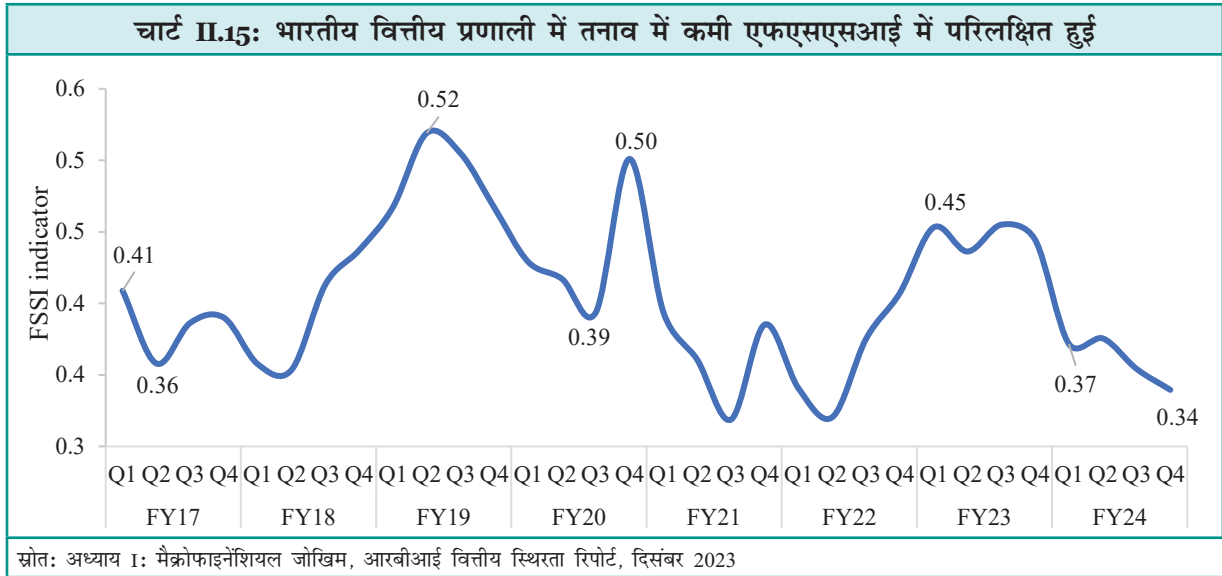
84 एफएसबी कार्यान्वयन को तीन प्रमुखों के अंतर्गत वर्गीकृत करता है जहां एक क्षेत्राधिकार ने अंतिम नियम प्रकाशित और कार्यान्वित किया है, नियम प्रकाशित किया है लेकिन लागू नहीं किया है और मसौदा विनियमन प्रकाशित नहीं किया है।

85 आरबीआई वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का 26वां अंक, दिसंबर 2022, पृष्ठ 56, https://t.ly/o_CZb.

86 एफएसएसआई में पाँच वित्तीय बाजार खंडों- इक्विटी, विदेशी मुद्रा, मुद्रा, सरकारी ऋण और कारपोरेट ऋण बाजारों और वित्तीय मध्यस्थ खंडों के तीन समूहों, अर्थात् बैंक, एनबीएफसी और एमसी-एमएफ के बारे में जोखिम कारक शामिल हैं। इसमें एक वास्तविक क्षेत्र घटक भी शामिल है जिसमें चुनिंदा वास्तविक क्षेत्र चर शामिल हैं जिनका वित्तीय क्षेत्र के साथ उनके मजबूत अंतर्संबंधों के कारण वित्तीय स्थिरता पर असर पड़ता है। अधिक जानकारी के लिए, देखें: https://rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=57005

तीव्रता और अवधि का आकलन करना, और (ग) वित्तीय बाजारों और मध्यस्थों की झटकों और असंतुलनों को झेलने की क्षमता का आकलन करना है।

2.129 जून 2024 के नवीनतम एफएसआर से पता चलता है कि एफएसएसआई ने वित्त वर्ष 2024 की पहली दो तिमाहियों के दौरान भारतीय वित्तीय प्रणाली में संकट में कमी देखी। दबाव के स्तर में गिरावट वित्तीय बाजारों और वित्तीय संस्थानों में व्यापक आधार पर हुई है। एफएसएसआई में गिरावट में इक्विटी बाजार का प्रमुख योगदान रहा, जिसमें उच्च निवल विदेशी पोर्टफोलियो प्रवाह, बेहतर प्रदर्शन और कम निहित अस्थिरता देखी गई। सरकारी ऋण बाजार में संकट भी काफी कम हो गया है, जो प्रतिशत और अस्थिरता में गिरावट के कारण हुआ है। वाणिज्यिक पत्र (सीपी), जमा प्रमाणपत्र (सीडी) और ट्रेजरी बिल दरों जैसे अल्पकालिक मुद्रा बाजार लिखतों की दरों के बीच अंतर कम होने से मुद्रा बाजार का संकट कम हो गया। विनिमय दर और अग्रिम प्रीमियम में कम अस्थिरता ने विदेशी मुद्रा बाजार में संकट को कम करने में योगदान दिया है। आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता में सुधार ने बैंकिंग और एनबीएफसी क्षेत्रों में संकट कम किया, जबकि बढ़ते म्यूचुअल फंड अंतर्वाह ने आस्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) के बीच दबाव को कम करने में मदद की।



मूल्यांकन और दृष्टिकोण

2.130 अधिकांश मामलों में, भारत के वित्तीय उद्योग ने समय के साथ बहुत प्रगति की है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निजी क्षेत्र को घरेलू ऋण 2010 में 50.6 प्रतिशत से बढ़कर 2021 में 54.7 प्रतिशत हो गया। एससीबी के सकल और निवल एनपीए समय के साथ घट रहे हैं, साथ ही सीआरएआर, आरओए और आरओई में सुधार हुआ है। भू-राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ने के बावजूद, भारत के शेयर बाजार स्थिर रहे हैं।

2.131 यहां तक कि जब बैंक, गैर-बैंक और कारपोरेट तुलन-पत्र की अधिकता, नई सहस्राब्दी के पहले दशक के क्रेडिट बूम और दूसरे दशक में उसके बाद आने वाली अपरिहार्य गिरावट के परिणामों से जूझ रहे थे, तब भी व्यापक उद्योग वित्तीय समावेशन और वित्तीय गहनता के कारण को आगे बढ़ाता रहा। चूंकि भारत वर्ष 2047 तक एक विकसित देश बनने के विजन पर चल रहा है, इसलिए यह जरूरी है कि वैश्विक स्तर पर वित्तीय मध्यस्थता की लागत में कमी आए। भारत ने इस संबंध में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जो कोविड के बाद की इसकी तन्यक आर्थिक रिकवरी का एक कारण हो सकता है। हालांकि, इसे वैश्विक वित्तीय अग्रणी बनाने के लिए अभी भी बहुत काम किया जा सकता है।

2.132 भारत के वित्तीय क्षेत्र का परिदृश्य उज्ज्वल दिखाई देता है। 2047 तक विकसित भारत का विजन वास्तव में समृद्ध समाज, मजबूत वित्तीय सेवा क्षेत्र, मजबूत सार्वजनिक वित्त और आर्थिक संप्रभुता के लिए एक अवसर है। एक मजबूत वित्तीय सेवा क्षेत्र के तत्वों में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और व्यवहार्य बैंकिंग क्षेत्र, सभी नागरिकों के लिए बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच, सबसे कम मध्यस्थता लागत, छोटे व्यवसायों के लिए ऋण और इक्विटी फंडिंग तक कुशल और त्वरित पहुंच, अत्यधिक तरल, कुशल और अच्छी तरह से विनियमित स्टॉक, बॉन्ड और कमोडिटी बाजार शामिल हैं। भारत के वित्तीय क्षेत्र को पूंजीगत निर्माण की सहायता करने और एमएसएमई में व्यापार, व्यवसाय और निवेश को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिससे उन्हें विस्तार करने में सक्षम बनाया जा सके। भारत की वित्तीय प्रणाली को सभी भारतीयों को बीमा सुरक्षा और सेवानिवृत्ति सुरक्षा प्रदान करने की भी आवश्यकता है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में बीमा और पेंशन फंड आस्तियों की हिस्सेदारी क्रमशः 19 प्रतिशत और 5 प्रतिशत है, जबकि अमेरिका में यह 52 प्रतिशत और 122 प्रतिशत और ब्रिटेन में 112 प्रतिशत और 80 प्रतिशत है।

2.133 आने वाले वर्षों में अगला बड़ा कदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग (एआई/एमएल), विकेंद्रीकृत वित्त, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) आदि की ओर है, जिसमें डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करने की बहुत बड़ी क्षमता है। इसके अलावा, भारत को एक शफिनटेक राष्ट्र के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की गई है, जिसमें सबसे अधिक संख्या में फिनटेक फर्म होंगी और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना द्वारा संचालित मौजूदा कंपनियों द्वारा फिनटेक अपनाने की उच्चतम दर होगी। नियामकों में सामान्य उपयोगकर्ता डेटा, जैसे केवाईसी, के लिए एक दृष्टिकोण विकसित किया जाना चाहिए। मध्यम अवधि में, विशेष रूप से लघु उद्योग के लिए निर्णय-आधारित ऋण के बजाय डेटा आधारित ऋण की ओर बढ़ने के प्रयास किए जाने चाहिए, खासकर छोटे व्यवसायों के लिए। इस संबंध में, विनियामक अंतराल/अतिव्यापीताओं की पहचान करने और उन्हें सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं के साथ बेंचमार्क करने के लिए निरंतर समीक्षा की आवश्यकता है। वित्तीय क्षेत्र की फर्मों - सार्वजनिक या निजी स्वामित्व वाली - को ग्राहक-केंद्रित बनना चाहिए। इसके बिना, अधिकांश मात्रात्मक मीट्रिक परिहारकारी बने रहेंगे।

2.134 भारतीय वित्तीय क्षेत्र एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। ऋण के लिए बैंकिंग सहायता का प्रभुत्व कम हो रहा है, और पूंजीगत बाजारों की भूमिका बढ़ रही है। वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षा रखने वाले देश के लिए, यह एक लंबे समय से प्रतीक्षित और स्वागत योग्य विकास है। हालांकि, पूंजी बाजार पर निर्भर रहना और उससे जुड़े रहना अपनी चुनौतियों और समझौतों के साथ आता है। जैसे-जैसे भारत का वित्तीय क्षेत्र इस महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजर रहा है, उसे संभावित संकट के लिए भी तैयार रहना चाहिए और आवश्यकतानुसार हस्तक्षेप करने और बचाव करने के लिए विनियामक और सरकारी नीतिगत प्रोत्साहन (लीवर) के साथ खुद को तैयार कराना चाहिए।
